Vol. 231
No. 3

Wednesday
11 June, 2014
21 Jyaishtha, 1936 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Proclamation under Article 356 of the Constitution (pages 1-8 and 9-10)

Papers Laid on the Table (pages 8-9)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development — *Laid on the Table* (page 10)

Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture — *Laid on the Table* (pages 10-11)

Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour — *Laid on the Table* (page 11)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment — *Laid on the Table* (pages 11-12)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development — *Laid on the Table* (page 12)

Clarification of Government concerning appointment of Army Chief (pages 12-15)

Motion of Thanks on the President's Address — *Adopted* (pages 15-140)

Valedictory Remarks (pages 140-141)

National Song (page 141)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : **Rs. 50.00**

# RAJYA SABHA

*Wednesday, the* 11*th June,* 2014/21*st Jyaishtha,* 1936 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

## PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION

MR. CHAIRMAN: Proclamation under Article 356 of the Constitution.

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर)** : महोदय, मैं श्री राजनाथ सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Proclamation [G.S.R. 385(E)], issued by the President on the 6th June, 2014, under article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 28th April, 2014, in relation to the State of Andhra Pradesh and varied by him on the 1st June, 2014, in relation to the successor State of Andhra Pradesh.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 16/16/14]

(ii) Report* (in Hindi only) of the Governor of Andhra Pradesh, dated the 20th February, 2014 to the President recommending the issue of the Proclamation [G.S.R. 132 (E)].

[Placed in Library. *See* No. L.T. 04/16/14]

(iii) Report* (in Hindi only) of the Governor of Andhra Pradesh, dated the 15th April, 2014 to the President recommending the issue of the Proclamation [G.S.R. 298 (E)].

[Placed in Library. *See* No. L.T. 06/16/14]

(iv) Report* (in Hindi only) of the Governor of Andhra Pradesh, dated the 25th May, 2014 to the President recommending the issue of the Proclamation [G.S.R. 373(E)].

[Placed in Library. *See* No. L.T. 08/16/14]

---

*English version of the Report was laid on the Table on 10th June, 2014.

**सुश्री मायावती** (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप अभी जरा बैठ जाइए, अभी वे बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : उनसे पहले आप दो मिनट मुझे सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : प्लीज़, आप एक मिनट बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, आप पहले उनको बोल लेने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : आपने जो कल की कार्यवाही में बीएसपी के सदस्यों को नेम किया है, यह कह कर कि उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाली है...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : देखिए, मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूं, आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : उत्तर प्रदेश का मामला जनहित का मामला था और हमारी पार्टी ने लिखित में नोटिस दिया था। यह एक अलग बात है कि आपने हमारा नोटिस स्वीकार नहीं किया। जब आपने हमारे नोटिस को स्वीकार नहीं किया तभी हमारी पार्टी के लोगों को अपनी बात को इस प्रकार से कहना पड़ा। इसके लिए आप हमारी पार्टी के सदस्यों को नेम करेंगे, यह गलत परम्परा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इधर बैठे हैं, लेकिन जब ये विपक्ष में थे...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : प्लीज़, आप बैठ जाइए।

**सुश्री मायावती** : उस समय जब नेम किया जाता था, तब तो बीजेपी के लोग कहते थे कि यह गलत परम्परा है। अब बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं?...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए, प्लीज़...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : *

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा** (उत्तर प्रदेश) : *

**श्री सभापति** : हाउस के प्रोसीजर में हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं है, वैल में आने की कोई गुंजाइश नहीं है।...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... प्लीज, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... सतीश जी, प्लीज़, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... देखिए, इसका एक तरीका होता है...**(व्यवधान)**... प्लीज़, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... Let the proceedings continue. ...*(Interruptions)*... देखिए, डिसरप्शन का हक़ किसी को नहीं है, डिसरप्शन का कोई रूल नहीं है...**(व्यवधान)**... आप ज़रा बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... Please allow the House to proceed. ...*(Interruptions)*... Let me clarify please. ...*(Interruptions)*... यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, उसे अगर किसी ने डिसरप्ट किया है तो वह प्रोसीडिंग्स में आता है...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

देखिए, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वह अलग बात है...**(व्यवधान)**... This is not going on record. What is the point.. ...*(Interruptions)*...

**सुश्री मायावती** : *

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा** : *

MR. CHAIRMAN: I request you to... ...*(Interruptions)*... त्यागी जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... सतीश जी, प्लीज़ बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... Thank you. ...*(Interruptions)*.... This is now the practice of the House... ...*(Interruptions)*... नहीं, वह ठीक है, but anybody coming to the Well has no right to come into the Well of the House. ...*(Interruptions)*... देखिए, आपको Rules of Procedure and Conduct मालूम है...**(व्यवधान)**... Please, please. ...*(Interruptions)*... क्या आप मुझे बोलने देंगे?...**(व्यवधान)**... मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... Rules of Procedure and Conduct are made by the House. The Chair is bound to observe them. If the rules have to be changed, please move to change the rules. ...*(Interruptions)*... अगर आपको रूल्स चेंज करने हैं, तो आप मीटिंग बुलाइए और चेंज कर दीजिए...**(व्यवधान)**...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा** : *

**श्री सभापति** : मैं आपको पिछले सैशन्स की प्रोसीडिंग्स दिखा दूंगा ...**(व्यवधान)**... Can we continue with the Business, please? ...*(Interruptions)*...

**सुश्री मायावती** : *

MR. CHAIRMAN: Can we please continue with the Business of the House? ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... I request a very senior Member, Leader of a Party, to please cooperate to allow the House to function. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... One minute. The Leader of the Opposition wishes to speak.

**विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : माननीय चेयरमैन साहब, हमने डेढ़ साल में बहुत ** देखा है। पिछले डेढ़ साल में शायद ही कोई ऐसा लेजिस्लेशन होगा, जो उस वक्त की सरकार पास करना चाहती थी और वह आसानी से पास हुआ हो। या तो लेजिस्लेशन बड़ी मुश्किल से पास हुआ या हुआ ही नहीं।

मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट रूल्स और रेगुलेशन्स से चलती है और उसका उल्लंघन करना बहुत खराब बात है। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो बात हम प्यार से, प्रेम से, विस्तार से कह सकते हैं, उसकी चर्चा अखबारों में भी होती है, टेलीविजन में भी होती है, लोगों तक पहुंचती भी है। लेकिन, जब हम वैल में आते हैं, तब एक तो अपनी बात

---

*Not recorded.

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

नहीं रख सकते हैं, दूसरा लोगों की बात नहीं रख सकते हैं। सदन का समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और जो बात कहना चाहते हैं, वह भी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। चूंकि एक-डेढ़ साल से इन दोनों सदनों में बदकिस्मती से दुर्भाग्य से उस वक्त विपक्ष के जो दल थे, उन्होंने इस तरह की गलत परम्परा डाली। मुझे बहुत खुशी है कि यह एक नयी शुरुआत हुई है, लेकिन नयी शुरुआत से पहले मेरे ख्याल में एक दफा माननीय चेयरमैन साहब अगर आज सब को कॉशन करेंगे कि अपनी जगह से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यदि अगर दोबारा कोई इस तरह की हरकत की, वैल में आने की कोशिश की या अनरूली कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि सबको मालूम है कि एक-डेढ़ साल से यह सिलसिला चलता आ रहा है, तब तो कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर हम आज यह बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी इत्तिला के करेंगे तो मेरे ख्याल में मैं सोचता हूं कि शायद जायज़ नहीं है। आज की दफा कह दें कि आइंदा नहीं होगा। अपोजिशन की तरफ से यह मेरी गुजारिश है।

**श्री सभापति** : शायद आपको मालूम हो कि पिछले सेशन में प्रोसीडिंग्स में यह चीज़ आई है, कई बार आई है और उसमें रिकॉर्डेड है। नेम नहीं किया गया है। 255 या 256 इन्वोक नहीं किया गया है।...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, ...**(व्यवधान)**... बी.एस.पी. के लोगों को क्यों नेम किया गया?...**(व्यवधान)**... हमने जनहित का मामला उठाया था।...**(व्यवधान)**... लिखित में नोटिस दिया था।...**(व्यवधान)**... दिल्ली की बिजली का मामला है, पानी की यहां किल्लत है...**(व्यवधान)**... दिल्ली में जनता को बिजली उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है।...**(व्यवधान)**... जो जनहित के मामले थे।...**(व्यवधान)**... हमने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया। उस पर भी आपने समय नहीं दिया।...**(व्यवधान)**... हमारे लोगों को मजबूरी में वेल में आना पड़ा। आपको भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो कोऑपरेट करें।...**(व्यवधान)**... जब जनहित के मामले को हम लोग उठा रहे हैं...**(व्यवधान)**... उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जनहित का मामला उठाया था।...**(व्यवधान)**... कल हमने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जनहित का मामला उठाया था।...**(व्यवधान)**... बदायूं का मामला था, दादरी का मामला था और जब मैं यहां से घर पहुंची तो मालूम हुआ कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी के एक नेता की हत्या हो गयी है।...**(व्यवधान)**... अब बीजेपी वाले क्यों चुप हैं, यह मैं नहीं कह सकती।...**(व्यवधान)**... दादरी में भी बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गयी, लेकिन वे चुप हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप मेरी बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**... देखिए, कल पूरा दिन डिबेट हुई और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने पूरा भाषण दिया। ...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, उसके तहत वह तो एक जनरल डिस्कशन है।

**श्री सभापति** : नहीं, उनके भाषण पर कोई रुकावट नहीं है, किसी के भाषण में रुकावट नहीं है।

**सुश्री मायावती** : सर, हमने लिखित में नोटिस दिया था, रिक्वेस्ट किया था कि बीएसपी को उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को उठाने का मौका दिया जाए। इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जब आपने समय नहीं दिया, तब हमारी पार्टी के मेम्बर्स को वैल में आना पड़ा।...**(व्यवधान)**... आप दो-तीन मिनट भी समय दे देते, तो हमारे लोग वैल में नहीं आते। लेकिन उसको लेकर उनको नेम कर देना कौन सी बात है? यानी, जनहित के मामले उठाना या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मामला उठाना ठीक नहीं है? मान लीजिए कल मैं दिल्ली के अन्दर बिजली की हालत का मामला भी उठाना चाहूं, तब आप तो हमें बिल्कुल मौका ही नहीं देंगे, हमको बांध कर रखना चाहेंगे। यह तो अच्छी बात नहीं है। जो नियम बने हैं, वे किनके लिए हैं? पार्लियामेंट किसके लिए है, संसद किसके लिए है? यह जनहित के लिए है। यदि हम जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे और आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम जनता को क्या जवाब देंगे?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : अगर हाउस को रूल्स बदलने हैं तो हाउस रूल्स बदल सकता है।...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : बीएसपी के लोगों को आप नेम करते रहेंगे...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*... One minute. ...*(Interruptions)*...

**सुश्री मायावती** : पिछली सरकार के समय क्या होता रहा?...**(व्यवधान)**... क्या आपने कभी उनको नेम किया?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : ज़रा मंत्री जी को सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. Chairman, this issue has come up many times even earlier. But this thing is under clear discretion of the Chair. यह मामला सभापति जी के विवेकाधीन है। इसलिए, हम कहेंगे कि पिछली बार भी इसके बारे में आपने जो एक प्रक्रिया अपनायी थी, so, it is up to you to decide. आज पहली बार दूसरा दिन है, जब हम ज़ीरो ऑवर नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज़ रोज ज़ीरो ऑवर, क्वेश्चन ऑवर और सब कुछ नियम से होगा ही। तो मुझे लगता है कि it is your discretion, Sir. But you have already shown due diligence even earlier on this issue and so it is up to you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Can we now proceed with the Business? ...*(Interruptions)*... Please. I think the matter…

**सुश्री मायावती** : सर, यह कोई बात नहीं है कि क्वैश्चन ऑवर नहीं था, ज़ीरो ऑवर नहीं था। यह तो पहले स्पष्ट करना चाहिए था। आप यह सीधा बोल दीजिए कि क्वैश्चन ऑवर नहीं था, ज़ीरो ऑवर नहीं था, इसलिए उन्होंने जो मामला उठाया था...**(व्यवधान)**... अगर आप मेरी बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह अलग चीज है, लेकिन इसको गोलमोल मत कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : एक मिनट जरा त्यागी जी की बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री ब्रजेश पाठक** (उत्तर प्रदेश) : सर, आप इनका माइक ऑन करवा दीजिए, आपने त्यागी जी का माइक ऑन करवा दिया, आप इनका भी माइक दो मिनट के लिए ऑन करवा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को रिकॉर्ड पर न लें, लेकिन इसको मीडिया लोग भी तो देख रहे हैं। ये उनकी तो लाइट बंद नहीं कर देंगे, जो मीडिया के लोग इधर बैठे हुए हैं। आप उनके पैन तो नहीं बंद कर देंगे।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Can we proceed? देखिए, इस तरह से 15 मिनट जाया हो गए हैं, समय की कमी है। Please. ...*(Interruptions)*...

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : सर...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, हमने कल जनहित का मामला उठाया था, यदि आप उसका समर्थन करते, तो मुझे अच्छा लगता। यूपी में रोज लोग मारे जा रहे हैं। महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कम से कम यह तो सोच लेते कि यूपी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेट है। वहां रोज लोग मारे जा रहे हैं, वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : इतने इल्जाम मुझ पर लगाए गए, बेगुनाही के अंदाज जाते रहे।...**(व्यवधान)**... त्यागी जी, आप अपनी बात जल्दी से कह दीजिए। We have a lot of Business.

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, मैं अपनी बात एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

**श्री सभापति** : ठीक है।

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस तरह के प्रश्न उठाने का रिवाज नहीं है, वह किताब मैं पढ़ कर आया हूं। लेकिन हमारे पुराने मित्र जो सिविल सोसाइटी के भी बड़े प्रसिद्ध लोगों में माने और गिने जाते हैं श्री अरुण जेटली जी, मैं उनके संज्ञान में एक पुरानी चीज लाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप कल बोल चुके हैं।

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, यह उसके बारे में नहीं है, यह अलग चीज है।

**श्री सभापति** : देखिए, आप कल बोल चुके हैं, इसलिए अब आप दोबारा नहीं बोल सकते हैं।

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, यह उससे अलग है।...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, हमारी बात को पूरा हो जाने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : त्यागी जी, आप कल अपना भाषण कर चुके हैं।

**सुश्री मायावती** : सर, यह जो हमारे मेम्बर्स को नेम किया गया है, मैं समझती हूं कि यह ठीक नहीं किया गया है, यह अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस वाले भी इस संबंध में थोड़ा गोलमोल कर रहे हैं, उधर बीजेपी वाले भी गोलमोल कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : देखिए, अब हाउस की यह established practice है, कल कोई नई चीज नहीं की गई है।

**सुश्री मायावती** : कांग्रेस वालों को सीधा बोलना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, can we proceed with the Business, hon. Members? ...*(Interruptions)*...

**सुश्री मायावती** : उधर बीजेपी वाले गोलमोल करें, तो यह अच्छी बात नहीं है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please.

**सुश्री मायावती** : सर, यह यूपी का मामला था और यह जनहित का मामला था। यहां सब कुछ पहले होता रहा है, लेकिन कल हमने यू.पी. का मामला उठाया, तो हमसे ही यह नई परंपरा लागू करनी थी? और मामले भी बहुत आएंगे।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : देखिए, हम इस पर बात कर सकते हैं, मैं सतीश जी से बात कर लूंगा। Thank you.

**सुश्री मायावती** : सर, आप सतीश जी से बात क्यों कीजिएगा? आप मुझसे बात कीजिए न।...**(व्यवधान)**... आपको मुझसे बात करने में क्यों परेशानी हो रही है?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : मैं ऑनरेबल पार्टी लीडर को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता हूं।

**सुश्री मायावती** : सर, मैं भी आपको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती हूं। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि कल जो कुछ हुआ है...**(व्यवधान)**... मैंने कल जनहित के मामले में यह मुद्दा उठाया था।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : इस पर बातचीत कर लेंगे, चलिए।

**सुश्री मायावती** : सर, यह अच्छी बात नहीं है कि आपने हमारे मेम्बर्स को नेम कर दिया।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आपने अपनी बात कह ली। चलिए, Thank you very much.

**सुश्री मायावती** : सर, इस पर आपका क्या कहना है?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : त्यागी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

**श्री के.सी. त्यागी** : सर मुझे आधे मिनट का समय दिया जाए।

**सुश्री मायावती** : सर, आप इस पर कोई व्यवस्था दें। इस संबंध में हाउस को मालूम तो होना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: What was done in the Bulletin of this morning has been done in previous Sessions of the House. It was not a new practice. Members are well aware of it. The Bulletins are on record. They can be consulted. Thank you.

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, यह पुरानी परंपरा है...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप यह सवाल इस वक्त कैसे उठा रहे हैं?

**श्री के.सी. त्यागी** : सर...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, आपने बुलेटिन वाली बात को रिपीट कर दिया है।...**(व्यवधान)**... सदन के जो नियम हैं, हम भी उन नियमों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी जनहित के मामले होते हैं, तो उठाने पड़ते हैं। हमने इस संबंध में लिखित में नोटिस दिया है। यदि कल ज़ीरो ऑवर होता, तो हम लोग इस मामले को ज़ीरो ऑवर में ही उठाते।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : देखिए, यह हाउस की प्रैक्टिस है कि जब...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती** : सर, जब कल ज़ीरो ऑवर था ही नहीं और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है, तो हम इस मामले को कब उठाएंगे और आज हाउस खत्म हो जाएगा। आपको हमारी यह परेशानी तो देखनी चाहिए थी। यह उत्तर प्रदेश का मामला है, कल ज़ीरो ऑवर नहीं था और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है, तो हम इस मामले को कब उठाएंगे?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : देखिए, यह हाउस कभी भी खत्म नहीं होता है। यह perpetual है।

**सुश्री मायावती** : तो ठीक है।...**(व्यवधान)**... आप चाहते हैं कि बीएसपी का हमको सहयोग मिलना चाहिए, तो हम तो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। हमने पिछली सरकार में भी आपको सहयोग दिया था और वर्तमान सरकार में भी हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम यह तो देखना चाहिए कि कल ज़ीरो ऑवर नहीं था और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है। यदि आज ज़ीरो ऑवर होता, तो हम अपनी बात ज़ीरो ऑवर में ही उठाते। अभी सत्ता पक्ष की ओर से वे मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन वे मुश्किल में हैं, क्योंकि उनको आपका सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, इसलिए वे गोलमोल कर गए हैं।...**(व्यवधान)**... क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी मदद चाहिए। वे बोल नहीं रहे हैं, जबकि वे विपक्ष में बैठकर सब कुछ कहते थे। यह तो अच्छी बात नहीं है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, now can we continue? ...*(Interruptions)*... I request you. ...*(Interruptions)*... Let us continue. ...*(Interruptions)*... Papers to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*...

---

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**I. Notification of Ministry of Health and Family Welfare**

**II. Report and Accounts (2012-13) of AIIMS, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of AYUSH) Notification No. G.S.R. 153 (E), dated the 5th March, 2014, publishing the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2014, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 15/16/14]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956:—

(a) Fifty-seventh Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, for the year 2012-13, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 13/16/14]

*...(Interruptions)...*

**श्री सभापति** : भाई, आप यह क्या कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**... This is not fair. *...(Interruptions)...* This is not fair.*...(Interruptions)...* The House is adjourned for ten minutes. *...(Interruptions)...*

The House then adjourned at twenty two minutes past eleven of the clock.

---

The House re-assembled at thirty-one minutes past eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

## PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Hon. LoP, do you wish to say something?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : माननीय चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश होगी और मैं रिक्वेस्ट करुंगा लीडर ऑफ दि हाउस से भी कि अगर सब की सहमति हो, आज हम सब की यही सहमति है कि यह दो दिन का सेशन है और समय बर्बाद न हो और दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और रूलिंग पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं। तो मेरी

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

रिक्वेस्ट है कि जो रूल-255 है, यह इन्वोक न किया जाए। यह खाली अभी तक बुलेटिन में है और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है invoking of rule 255 अभी यह बुलेटिन तक हुआ है और बुलेटिन में तो पहली दफा नहीं हुआ है, बुलेटिन में तो पिछले साल भी हमारे लोगों का भी कई दफा हुआ है और बाकी पार्टीज के साथ भी हुआ है। तो मेरी यह गुजारिश होगी कि रूल-255 हो इन्वोक न किया जाए।

**सभा के नेता (श्री अरुण जेटली)** : सर, लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वह एक रीजनेबल सुझाव है और अगर उसको स्वीकार कर लिया जाए तो सदन की कार्यवाही चल सकती है।

MR. CHAIRMAN: I thank the hon. Leader of the Opposition and the hon. Leader of the House.

Let me clarify, rule 255 has not been invoked. It has not been invoked. The Bulletin is only showing the proceedings of the House, something which is already on electronic record and televised. The practice of showing in the proceedings the names of those who are coming into the Well has been invoked for some time now. There are, at least, ten such instances covering different parties, as the hon. Leader of the Opposition has said. So, I think, there is a misunderstanding. I would request the hon. Members that two statements from the two sides of the House are clear enough. I emphasise that rule 255 has not been invoked in yesterday's proceedings. Thank you very much.

Now, the Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

---

## REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Two Hundred Sixty Third Report on the Functioning of Indira Gandhi National Open University of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

---

## REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and

Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture:—

(i) Fifty-ninth Report on Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-seventh Report on 'Cultivation of Genetically Modified Food Crops — Prospects and Effects' pertaining to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation);

(ii) Sixtieth Report on 'Pricing of Agricultural Produce' pertaining to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation); and

(iii) Sixty-first Report on 'Rashtriya Krishi Vikas Yojana — An Evaluation' pertaining to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation).

---

## REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour:—

(i) Forty-Fourth Report on 'The Building and Other Construction Workers Related Laws (Amendment) Bill', 2013;

(ii) Forty-Fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Thirty-Second Report Fifteenth Lok Sabha) on 'Welfare of glass and bangle workers of Firozabad — A case study'; and

(iii) Forty-Sixth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Thirty-Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Welfare of small weavers of Mau and adjoining areas — A case study'.

---

## REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Forty-sixth Report on the subject Implementation of Prime Minister's New

[Secretary-General]

15 Point Programme of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment.

---

## REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Thirty-first Report on the subject "Functioning of Delhi Development Authority particularly with reference to affordable houses in Delhi and its role in regularization of unauthorized colonies in Delhi and matter connected thereto" of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we shall now resume the discussion on the Motion of Thanks on the Address of the President of the Republic.

---

## CLARIFICATION OF GOVERNMENT CONCERNING APPOINTMENT OF ARMY CHIEF

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, I had informed of our intention to raise a very serious matter, and, with your kind permission, I would like to draw the attention of this august House and the Leader of the House about a statement which has been made, and, which we believe is now the accepted practice of the Government on Prime Minister's instructions that the Ministers must make statements using Twitter. Yesterday, there have been repeated tweets and statements made by a serving Minister of State of the Ministry of Development of North Eastern Region and the Minister of State in the Ministry of External Affairs, Mr. V.K. Singh, making unacceptable and highly objectionable statements on the appointment of the Army Chief and the persona of the Army Chief designate. We were worried when during the election campaign, this matter was sought to be politicized. The Indian Army has always been kept out of politics. The appointments of Generals, Chiefs of Army, Admirals, Air Force Chiefs have never ever been politicized. Therefore, we were reassured, given the understanding and maturity of the Leader of the House when he assumed the office also as Defence Minister. He made a very correct statement which was reassuring to the country and to the Army leadership. But Sir if a serving Minister is making such a statement, the Government ought to remove this Minister. The Prime Minister must clarify this issue. It is unacceptable.

MR. CHAIRMAN: All right. Thank you.

SHRI ANAND SHARMA: He cannot continue in the Government, he cannot be a Member of the Cabinet. He cannot hold his position when he has made this public statement. If he is an ordinary Member, that is a separate issue but he is a serving Minister.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI ANAND SHARMA: This is a very serious matter. ...*(Interruptions)*... It is not a small issue. I do not want to go into the details as to what the conduct of this individual has been. We have never commented, and, I shall refrain.

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI ANAND SHARMA: I will be correct but, at the same time, hon. Chairman, Sir, this is not a matter which can be lost over. This is not a matter which can be ignored. This is a very serious development. It does not augur well. It is ominous as to what is going to happen. The Leader of the House is here. If he says that he can keep on tweeting and making such statements demoralizing the Army, castigating the Army Chief designate, and, we should keep quiet about it, I don't think that would be a correct position, and, hon. Members may like to take a view.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I would like to say... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please do not start another debate on this. ...*(Interruptions)*... No, no. We are discussing... ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND UBRAN POVERTY ALLEVIATION AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, there are other ways of discussion. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : आप कुछ कह दीजिए, ताकि we can settle this issue. ...*(Interruptions)*... Would you wish to say something? ...*(Interruptions)*... One minute, one minute, please. The Leader of the House... ...*(Interruptions)*... Please one minute. ...*(Interruptions)*... The Leader of the House.

SHRI SITARAM YECHURY: My only appeal is that it is a serious allegation. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the Leader of the House speak. ...*(Interruptions)*... No, no. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, it is a serious matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is a very serious allegation. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : आप बोलिए। येचुरी जी, आप बैठ जाइए।...*(Interruptions)*... It is an established convention that when the Leader of the House speaks, we listen to him. ...*(Interruptions)*... No, no. Let us hear him.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS; AND THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the UPA Government had made the appointment of the next Army Chief some weeks ago. It's been a practice in this country that we keep some issues outside the realm of inter-party politics, and, therefore, keeping various standards of political maturity statecraft in mind, all of us, not only the Government but all of us, must keep the Army and its appointments out of this arena and stand by the appointment. The present Government also is fully defending that appointment. The issues, which are *sub-judice*, really cannot be discussed in this House itself.

As far as the comments against one of the Ministers is concerned, I would urge that this issue directly, indirectly or even collaterally may not be raised for the reason that if one of the major political parties chooses to attack a Minister, then the Minister may consider defending himself**.** Therefore, that area is which is wholly outside. But as far as the Government is concerned, the appointment is final and the Government fully stands for it.

SHRI K.C. TYAGI (Bihar): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no, that is enough. Let's now proceed. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, the Defence Minister should ...*(Interruptions)*...

**श्री के.सी. त्यागी** : सर।

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... Let us get on with the business of the House. ...*(Interruptions)*... I would like to draw the attention of hon. Members to Rule 238 (a) that procedure has to be completed if such matters are to be raised. In this matter, this procedure has not been followed.

SHRI K.C. TYAGI: Sir, I agree with you; I agree with the Leader of the House. But, Sir, इन्हीं की पार्टी के नेता...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : नहीं, वह बात खत्म हो गई।...(**व्यवधान**)...

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, इन्हीं की पार्टी के नेता *

**श्री सभापति** : अब आप उसका जिक्र यहां नहीं करेंगे।...(**व्यवधान**)... No, no, this will not go on record.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am afraid ...*(Interruptions)*... He is mentioning the name of the person who is not there in the House.

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. That is settled.

Now, Shri Jairam Ramesh to continue the discussion on the Motion. Thank you.

---

## MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks to the President's Address. I will be very brief and pointed. During the course of the Address, we also had the benefit of the intervention of the Leader of the House. So, my comments on the President's Address will also be interspersed with some responses and reactions to what the learned Leader of the House had to say.

Sir, the first point I would like to highlight is on para 4 of the President's Address. There is a reference to the mandate of the 2014 elections and very clearly and very succinctly the President's Address says that the 2014 mandate was a mandate, and I quote, "for development through good governance." Sir, I have no problem with this formulation whatsoever. I have also no problem with the various comments on the mandate that were made yesterday by the Leader of the House. But I wish to state that if the mandate of 2014 is seen only through the lens of development and good governance, we are not being realistic, we are not doing full justice to the nature of the mandate. Sir, the election campaign is over. This is a parliamentary forum. We are debating the President's Address. Therefore, I am forced to draw your attention to this fact simply because both the President of India and the Leader of the House raised this issue. Sir, the mandate of 2014 was not just development through good governance, but the mandate was also a consequence of deliberate communal polarization at the ground level in State after State. Sir, I do not believe that any

---

*Not recorded.

[Shri Jairam Ramesh]

of us who have taken part in the campaign, who have looked at the campaign, can be so simple-minded and so blind to the field-level realities that we saw in State after State, particularly in the northern parts and in the central parts of the country where deliberate polarization was sought to be engineered by the party that is now in power. Sir, I do not wish now to go back in time as to how it was done and why it was done. All I wish to state is that the mandate of 2014 at one level was development though good governance, but at the ground level, at the most fundamental level, it was the outcome, the consequence, of deliberate communal polarization. I can only hope, Sir, and my party and all the country can only hope that having reaped the benefits of communal polarization, the Government would learn the lessons from previous history, from previous regimes and govern from the Centre. It is no longer a time for polarization. Now is a time for good governance, and good governance means inclusive governance, good governance means taking everybody along. And I hope that the hopes that I have expressed come true, that having done the polarization as part of the campaign, to set it aside now and focus on good governance, forgetting the nature of the strategy that was adopted for getting this mandate.

Sir, the second point I wish to make is that the President's Address has necessarily to be selective. This Government is only 15 days old and therefore you are not going to be able to deal with all the issues in the President's Address, and it will only be in the Budget that the full agenda of the Government would get unveiled. Even so, Sir, I feel somewhat disappointed that this President's Address does not do adequate justice to the momentous economic and social changes that have taken place in the last ten years. The fact that we did not get the mandate does not deny the fact that these changes have taken place. The fact that we could not take political benefit from these changes does not mean that these changes have not taken place.

Sir, we have had a GDP growth of over seven-and-a-half per cent over a ten-year period. This is the fastest GDP growth in any democratic country in the world. This means a doubling of GDP over a ten-year period. One hundred and forty million people have been raised above the poverty line. Yesterday, the hon. Leader of the House kept saying that we had elevated poverty. No, Sir. We have elevated poor people above the poverty line. One hundred and forty million people have escaped the trap of poverty as a result of economic growth and various social interventions of the Government over a ten-year period. People have been empowered to an unprecedented degree. Sir, 13 lakh tribals have been empowered through the

Forest Rights Act. Every year four-and-a-half to five crore rural households find productive employment through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. I can give example after example whether it is the Right to Education Act or whether it is the Forest Rights Act. Of course, the Food Security Act is yet to become fully operational and the Land Acquisition Act is yet to become fully operational. But I think, Sir, the empowerment of the weaker sections of society through laws, through policies and through programmes of infrastructure, economic growth and education is a reality.

Sir, in 2004, only nine per cent of the college going population in India was actually going to college. In 2014, 20 per cent of those who can go to college are actually going to college. It is a doubling, it is more than a doubling of the gross enrolment ratio in higher education which the President's Address says is an instrument of empowerment.

Sir, take the health sector. Look at all the indices that we have had on infant mortality, on maternal mortality and on access to healthcare. Or you talk about rural connectivity where over 4,00,000 km. of rural roads have been built through the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana*. I think these are momentous changes. There is structural transformation that has taken place.

Sir, I am sensitive to the criticism that we may not have recognised the changing aspirations and expectations of the people; we became victims of our own success if I may be able to respond to the hon. Leader of the House. But for the Leader of the House to say that nothing has happened in the last ten years and for the President's Address to be completely silent on the fundamental social and economic changes that have taken place on account of legislative changes, on account of programmes and on account of policies, I think is being very unrealistic. Because Government ultimately is also a matter of continuity. I think to be honest to continuity, the President's Address should have recognised the large number of transformations that were created under the UPA regime although I reiterate we were not the political beneficiaries of these changes.

Sir, the third point I would like to make is that for a Government which is only 15 days old, it is but natural that the President's Address will reflect continuity. Because you do not have time to come up with momentous changes which hopefully will be unveiled perhaps in the Budget. But the President's Address largely is a reflection of continuity in Government. Therefore, Sir, all I can say is that a large number of programmes that are contained in this Address are, in fact, a continuation

[Shri Jairam Ramesh]

of what the previous Governments have started just as what the UPA Government did was a continuation of what the NDA Government had started. The *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* is a good example of a programme that was launched when Mr. Vajpayee was Prime Minister. And it was taken forward by the UPA Government and expanded by almost five fold.

Sir, this is not the first time that the project Ganga is going to be launched. This is not the first time that there is going to be a Himalayan Eco System Mission. I can quote examples. This is not the first time that a Skill Development Programme is going to be launched. So, in programme after programme, in priority after priority, my request to the Government, my request to the senior Ministers is do not reinvent the wheel. There is a lot that is already there. There is a lot of experience with the cleaning of the Ganga. There is a lot of experience with the protection of the Himalayan Eco System. There is a lot of experience in the building of the skills. There is a lot of experience in creating the rural infrastructure. There is a lot of experience in building new cities. There is a lot of experience in encouraging and incentivising the growth of labour intensive manufacturing. So, you are not starting on a clean slate. You are not reinventing the wheel. So, I would request the Government to recognise the continuity, build on the successes, and, of course, the Government of the day has a flexibility to bring about whatever changes it wants in laws and programmes.

Sir, the fourth point that I would like to make is the President's Address has some simple mantras. But I hope these simple mantras do not become simplistic mantras. "Minimum Government, Maximum Governance" sounds very good. "Ek Bharat — Shreshtha Bharat" sounds very good. We can't disagree with these mantras. But Minimum Government, we are all for better Government. We are all for a quality Government. We are all for a pointed Government. As my senior colleague said yesterday, Minimum Government can mean one-man Government. Minimum Government can also mean one-office Government. Minimum Government can also mean a Government run by a handpicked team of ten civil servants. That is also a Minimum Government. Minimum Government can mean repeal of laws that have provided the framework of our democratic edifice. So I would like to have some clarity. I am not against Minimum Government, Maximum Governance. We are all for Maximum Governance. We are all for better Government. We are all for quality Government, but this word "Minimum Government" raises more questions than it answers.

Similarly, "Ek Bharat — Shreshtha Bharat", who can disagree with this? But let us also recognise that India is an example of unity in diversity, not just unity in diversity, but unity through diversity. I hope that the Government doesn't want to impose uniformity in the name of the unity. We want unity, but we do not want uniformity. India is an example in which there is diversity of extraordinary kinds — religious diversity, linguistic diversity, caste diversity, regional diversity, diversity of thought, diversity of action, the great advantage of India is chaos, the great advantage of India is the fact that people are free to think, people are free to express their voice, people are free to dissent. I hope in the name of "Ek Bharat — Shreshtha Bharat" we do not quell dissent, we do not become intolerant of diversity, we do not accommodate different points of view, and we go on the assumption that whatever one person, or, one Government says is the ultimate truth. I hope that is not the meaning of "Ek Bharat", and, therefore, here also, Sir, we need some clarity on exactly what the Government needs.

Finally, I am very happy that the President's Address shows pragmatism on the part of the Government to abandon positions that were taken when they were not in Government. One of the fundamental rules of the parliamentary democracy is where you stand depends on where you sit; and those who are sitting on that side were sitting here. They took certain positions. My friend, Piyush Goyal, knows what I am going to refer to. Sir, GST was an idea of Mr. Yashwant Sinha. It was taken forward by Mr. Chidambaram and Mr. Pranab Mukherjee. But we could not implement the GST because of the opposition from a couple of members of the distinguished Government. Now, I am very glad, Sir, that President's Address recommits the NDA Government to the introduction of the GST. You will have full support. We will not go into the question of why you didn't support us for a five year period. But better late than never, and I hope that the GST will soon become a reality. Similarly, Sir, my senior colleague has already mentioned about the Paragraph, which was lucid to his ears, that is, Para 17, which is a ringing endorsement of the Ministry of Minority Affairs that was objected to when it was created in 2004.

Also, on the Nuclear Agreement, when the Government says, "We will take the Indo-U.S. Nuclear Trade forward", I am reminded of those days when our Government was berated, when Dr. Manmohan Singh was berated, for bartering away India's sovereignty to the United States. But I am glad that today this Government sees merit in the Nuclear Agreement and wants to take it forward.

[Shri Jairam Ramesh]

Now, about interlinking of rivers, there is a very small phrase that has been introduced on the interlinking of rivers which shows a welcome pragmatism and I commend the Minister of Environment who may, perhaps, have included this phrase. The position of the NDA Government is that there should be interlinking of rivers, that it must be there at all costs. But I am glad that two words have crept in into the President's Address. I do not know whether knowingly or unknowingly, it says, "Including linking of rivers 'wherever feasible'." I welcome this introduction because interlinking of rivers has environmental, social, political and ecological consequences. I am not saying that it should not be interlinked. But 'wherever feasible' is the operative term.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Are you opposing interlinking of rivers?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is not the time to discuss the issue of interlinking of rivers. I am not in the dock, but they are in the dock. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, let the hon. Member finish.

SHRI JAIRAM RAMESH: I am commenting on the President's Address. My views on interlinking of rivers are immaterial because right now you are in power. This is the Address of your Government. And, Sir, the freedom of the Opposition is to criticize, but we will also give constructive cooperation where there are areas of agreement. So, what I stand for on the interlinking of rivers is immaterial to this particular debate.

Sir, in short, what I want to say is that the President's Address reflects the priorities of the Government. The priorities of the Government reflect continuity of programmes. This is a new Government, just two weeks old, and I can only plead with my colleagues in the Government that they should seriously look at some of these programmes that have been there on the ground. The Swachch Bharat Abhiyan is nothing but the Nirmal Bharat Abhiyan. You can have nice packaging. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is nothing but the Accelerated Irrigation Benefit Scheme. I mean, you can package these schemes better; you can give nice sounding names. But I would request you, whatever is worth keeping, please keep it, do not abandon it. I will end with this example. When the UPA Government came to power, we inherited the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana at the level of Rs.4,000 crores per year. We have left the Government and bequeathed the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

**12.00 NOON**

to you at a level of almost Rs.20,000 crores per year. Five times' expansion in the Rural Infrastructure Programme! We did not ask who started PMGSY or who was behind PMGSY. But we were convinced that the PMGSY was a programme for the benefit of the people of India and we expanded it. And I would expect this Government to follow the same route, the same trajectory, the same path.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

If they do this, then, I am sure, as my senior colleague has mentioned, we will offer constructive co-operation, although to quote the hon. President, who always used to tell us, — not when he was the President, but when he was the Leader of this House and the Leader of the other House — "The job of the Opposition is to oppose, expose and depose." Thank you, Sir.

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for inviting me to present my views on the hon. President's Address to both the Houses of Parliament. The hon. President in his inaugural Address said something very significant. He said, in Para 4 and I quote, 'This has been an election of hope.' This is not only an election of hope. I would go so far to say what has happened thereafter — the establishment of a Government led by Shri Narendra Modi — has ensured that this is a Government of hope as well.

Sir, a lot of things has been said. I do not wish to dwell on all those details. My able colleagues on the Opposition benches have also made several points. The main point which they have stressed is they are accusing us of having copied their ideas and a kind of regurgitate them or tweak them around, translated them from English to Hindi and presenting it back to the people. Sir, this cannot be farther from truth. But, I will come to it a little later.

I come to the question of hope. Why I say that this is not only an election of hope, but a 'Government of hope.' Many decades ago — hon. Members here will recall — Dr. Martin Luther King Junior had used four words which shook the entire world and resonate in the minds of everybody, even now. He said, "I have a dream." मेरा एक सपना है। Sir, these are stirring words. These are stirring words if you see them in the context of the American Civil Rights Movement of the time and the fact that the kind of injustice that was meted out to people on grounds of race and colour and the transformational skill that Dr. Martin Luther King had in uniting people of the United States and transformed the American society for ever.

[Dr. Chandan Mitra]

Sir, I see, in the programmes outlined by the hon. President for his Government over the next five years, the same transformational quality. There is a promise of transformation. Transformation is promised on the basis of experience and on the basis of achievements. The Government, I think, embodies the fact that every Indian has a dream. Every Indian wants to see an India free of poverty, free of misery and free of all the social ills of casteism, communalism and various other things that are scourge on our society be removed and India become a leading country in the world and a developed country. But, today, 67 years after Independence, we are nowhere near achieving that dream. I don't want to politicise what I am going to say and I don't blame anybody. Various Governments have come and gone. Shri Narendra Modiji, the hon. Prime Minister, said in his speech the other day that everybody has contributed something or the other. Some have contributed a lot and some have not contributed that much. But, every Government has contributed something. So, I don't want to belittle or berate the contributions that have been made by those who are now in the Opposition benches or those who are not in Government and not in Opposition either. Many people have come and contributed. But the fact is, at the end of the day, today, in the words of Sahir Ludhianvi, for an ordinary person, for poor people of this country, they will still be saying, "माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं है। मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं।" Sir, that is the reality. And that reality has to change. How will it change? It can't change only by dreaming. But, dreaming is essential. To dream, Sir, is the basis, fundamental, on which the human society progresses. Sir, look at it. There was a time when novelist writing science fiction, Jules Verne, talked about journey to the moon. Man has been dreaming of going to the space or reaching the moon. It is on the dream that eventually man has gone to the moon. Even India, during Shri Atal Bihari Vajpayee's Government, it was decided to launch Chandrayaan. Now, we have launched Mangalyaan. India is now going to the mars, not just to the moon. This is the result of a dream. So, Sir, when I am saying that this a Government of hope, it is Government of hope based on dreams always nurtured by this nation of 1.25 billion people.

Sir, what are our dreams? I think, it is a shared dream across political parties, across States, across castes, across communities and everyone. The dreams, if I may just summarise, are equal rights, democracy, equal rights for women. If you see the President's Address, it has promised all of these in full measures. Even on the question of women's rights, it has been said by Government after Government, mostly

Governments led by my hon. Colleagues sitting on the other side that they would bring the Women's Reservation Bill. Sir, I was going through the Address of the then President, Madam Pratibha Devisingh Patil. It has been categorically stated in that Address made five years ago that women shall be given 33 per cent reservation in Houses of Legislation. Sir, five years have passed; it has not happened. I don't want to go into why it has not happened. This House has distinguished itself by actually getting it passed. I don't want to go into why it didn't happen there, but the fact is it didn't happen. But, now, we know it can be done and it will be done.

Sir, there is a question, somebody was saying the other day, that it is not only a question of dreaming, but it is a question of *niyat.* It is the *niyat* that distinguishes one Government from the other. I know, the *niyat* of this Government, which has been proved again and again in States ruled by the Bharatiya Janata Party. If there is *niyat,* the *neeti* can actually become a reality. *Sapna* can become *haqeekat.* So, that is the transformation. ...*(Time-bell rings)*... The transformation comes when *neeti* comes along with *niyat*. Sir, I have talked about equal rights, elimination of poverty.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only two more minutes.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, every time you interrupt. When I was sitting on that side also, within two minutes, you used to stop me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has only thirty minutes, and they have two hours. What can I do? The hon. Prime Minister has to reply at 5 P.M.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, have some mercy on me, because each time I have spoken in the House you have been in the Chair! That side and this side also!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Because I am your friend! Two more minutes, please.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, we have talked about elimination of poverty and this was discussed in great detail—what is the difference between alleviation of poverty and elimination of poverty? As I said, I don't want to politicise. I only want to just remind the Members of the other side. I am sure, they will remember very well. Way back in 1971, 43 years ago, our former Prime Minister and distinguished leader of the Indian National Congress, Smt. Indira Gandhi had coined the slogan, *garibi hatao,* remove poverty. 43 years ago! How come, Sir, poverty has gone up after that? Somebody has to take the bull by the horns and end it. The President's Address has categorically commented that this will be done; not just alleviation of poverty by doles, not just by charity, but elimination of poverty is the goal. Sir,

[Dr. Chandan Mitra]

about electrification of villages, the hon. Leader of the Opposition, yesterday, spoke at great length on electricity. He talked about the Rajiv Gandhi Gramin Vidyatutikaran Scheme, which is one of the four hundred schemes that are named after members of the same family; but I won't go into that.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): What do you mean by the 'same family'? They were the Prime Ministers of the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. There is no time for all that.

DR. CHANDAN MITRA: You know what I am doing. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; don't react to that. Dr. Mitra, your time is over. ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I am not reacting to that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has decided the time. So, you have to abide by the time.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, the hon. Leader of the Opposition said that one lakh villages have been electrified. Fine; I am not contesting his figures. But, he himself said that if you include hamlets, there are 8.5 lakh villages and hamlets in India, and only one lakh have been electrified! So, it is a huge target, Sir. How will it be done? In this context, I would like to point out also that...*(Time-bell rings)*... One of their leaders...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, you cannot do this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I will take a total of ten minutes, how much you... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. See, the Prime Minister has to reply at 5 P.M., so, I have to be strict to the time; otherwise, it will be difficult to conclude the debate. Your party has given me the time as to how much time I should give you, and I am doing that.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I want to point out that for the majority of times since Independence the Congress Party and its allies have been in power. In spite

of that, one Ms. Kalawati did not have electricity in her house only a few years ago. I wonder whether they should be able to inform me about that. I would like to know from the hon. Leader of the Opposition whether Ms. Kalawati has electricity in her house now or even now it is not there. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prakash Javadekarji... ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, please give me two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can I do justice to everybody then?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I must say that I was pained by the fact that there was constant talk that the BJP-led Government under Narendra Modiji has appropriated Congress programmes. In their enthusiasm, the Congress Members went on to say that the highway building programme was theirs and it has been going on very successfully. Sir, the fact is that the NHDP and the Golden Quadrilateral Programme were started in 2001, when Shri Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister. The pace of development was 11 kilometres per day, which came down to four kilometres per day. ...*(Time-bell rings)*... Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was started in the year 2000 by Atal Bihari Vajpayeeji. So, Sir, it is not a question of whether we are carrying on their programme. In fact, they had carried on with our programme.

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, he is speaking beyond his time. ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Very good, just now my friend, Shri Jairam Ramesh, said that do not throw out the good things; and continue with them. I entirely agree with him. But, then, we would not like to go back and take credit for certain things that they have done just as the Congress should not take credit for things which we have done.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Chandan Mitraji, you are my friend. Please help me.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I have a lot of points to make.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, when will you give me the time again? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will be there in the House. ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: But, Sir, every time I get up, you start saying, 'please wind up'. I think you do not like my speeches.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I like your speeches very much. But what can I do?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, out of deference to you, I am just concluding because I do not wish to question the Chair.

Sir, the last point that I would like to make is the question of industry, the revival of industry and the emphasis on the manufacturing industry. Sir, this is one of the most important points that have been outlined in the President's Address and it is a fundamental article of faith with the Government of Shri Narendra Modi. Here, I would like to draw my own Government's attention to a few issues which are pending in my State. Sir, in my State, in factories, like the world-renowned Dunlop, the world-renowned factory of the Hind Motors of the Ambassador Cars in which, I am sure, you also travel or used to travel till recently, the production has stopped. The Hind Motors factory is near Kolkata. It is, in fact, inside the constituency where I contested the Lok Sabha election.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): There is Jessop also.

DR. CHANDAN MITRA: Jessop has happened before. I am talking about very recent things. We all know what happened to Singur; the promise of Singur. So, Sir, Singur, Dunlop, Hind Motors factories are shutting down one after the other. All this has happened, and unfortunately no steps have been taken. We have to rebuild India's manufacturing base and manufacturing capability and this is a promise that has been made in the President's Address and would be followed to the letter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now conclude. ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: It is a stirring hope and confidence and the belief that 'हम होंगे क़ामयाब', that this Government is proceeding and we shall come back to you कि 'हम हुए हैं क़ामयाब।' Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Now I think for the benefit of Members, I want to tell how much time is available for each party. Indian National Congress has 2 hours 10 minutes; BJP has got 15 minutes; AITC has got 19 minutes; then TDP has got 13 minutes, Nominated have got 17 minutes, and then we have Others. This is the time. So, please try to cooperate. Otherwise, we will all be in difficulty. ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, what about time for BJD?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over. ...*(Interruptions)*... In 'Others' category it is coming. You will get time because it is in Others category. 'Others' category has got one hour 37 minutes. But there are 15 speakers. That mean you may get 7 or 8 minutes.

Now Shri Sukhendu Sekhar Roy. ...*(Interruptions)*... You have only 19 minutes, so stick to that. ...*(Interruptions)*... Today I will be strict with everybody and I have to be so with everybody. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, while participating in the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Mukhtar Abbas Naqvi yesterday, I would like to raise a few points on behalf of my party, All India Trinamool Congress, in addition to the points made by my distinguished colleague, Mr. Derek O' Brien yesterday. जनादेश के बारे में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। किसी ने बोला कि जनादेश, सत्ता और पैसा, ये तीनों ही बहुत कम्बख़्त चीजें होती हैं। हम यह नहीं मानते कि जनादेश कम्बख़्त चीज़ होती है। जनादेश को हम सिर्फ मानते ही नहीं हैं, बल्कि हम इसको प्रणाम करते हैं। जनादेश चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी के पक्ष में हो, लेकिन जनादेश हमारे लोकतंत्र का आधार है। And the will of the people is supreme in a democracy and all of us bow down before the will of the people. लेकिन जो जनादेश हमने इस बार देखा, गुजरात के अरब सागर से लहर उठी और वह लहर जब बंगाल की खाड़ी तक पहुंची, तो बैकवॉटर बन गई। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, गुजरात, मराठा, हर जगह एक तरह का जनादेश दिखाई दिया। द्रविड़, उत्कल और बंग, यहां हमने दूसरी ही तरह का जनादेश देखा, लेकिन दोनों ही जनादेश हैं और दोनों ही जनादेशों को हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।

Sir, now I shift to paragraphs 7, 14 and 25 together of the President's Address. पिछले दिनों में हमने गरीबी हटाओ, इन्क्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बहुत सुना। अब तो ये स्लोगन बन गए हैं। हिन्दुस्तान का चित्र आज क्या है? जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम पोवर्टी एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आजादी के 67 साल बाद हमारी असलियत क्या है? हिन्दुस्तान कहां पर खड़ा है? I would like to refer to UNDP's Human Report published last year. Sir, 53.7 Indians live in multi-dimensional poverty and another 16.4 per cent are vulnerable to multi-dimensional poverty. We share our position with Equatorial Guniea, a country the name of which is hardly known to the people. आज़ादी के 67 साल के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति यह है।

Sir, the Press-release of World Bank published on 10th of April this year says that the total number of the poorest of the poor who cannot earn even 1.25 dollar a day is 1.2 billion, that is, world's poorest of the poor and one-third of them, that

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

is, 40 crores of the world's poorest of the poor population live in India. That also constitutes one-third of our total population. यह हालत है हमारी As per State of the World's Mothers 2013 report, in India, 3,09,300 children die on the very first day of their birth. And, this is 29 per cent of the world's first-day mortality rate of the children. India ranks top among all other countries. सर, आजादी के 67 साल के बाद भी हमारी यह हालत है। This is what we have achieved in the 67 years of our Independence. While this is the situation, on the other hand, if we go through the report published in today's Times of India, the Boston Consulting Report, it says that India had 1,75,00 millionaire households in 2013, ranking 15th in the world, and is projected to become the 7th wealthiest nation by 2018. Millionaire, of course, is in terms of dollars. Such a huge economic inequality persists in our country, notwithstanding what has been stated in the Preamble of our Constitution — justice, social, political, economic. We have forgotten everything. We have given a goodbye to all these things. It has been established beyond doubt that the major share of the benefits of the so-called economic reforms, after the liberalization policy, has gone to the kitty of the richest people of this country and not to the poorest of the poor people of this country. This is a hard reality that we are confronted with. I think, the new Government has a duty, a paramount duty, to have a re-look, to re-visit the so-called economic reforms of the liberalization policy, which is being pursued since 1991, for almost 23-24 years. The Government must try to initiate steps to reform the reforms. Reforming the reforms is the only step that is required in the present economic situation of this country, and which has been adopted by some of the Latin American countries.

Sir, in Shakespeare's Midsummer Night's Dream, we have read about the carnival of aristocrats. Shakespeare has described the carnival of aristocrats. Here, we do not want to see the carnival of the crony capitalists. I am sorry to say all these things because this has been our experience, bad experience. We assure of our best cooperation to the new Government for all upcoming poverty elimination programmes and all programmes which are in public good. But whenever there is any attempt on the part of the new Government to adopt any policy which is otherwise anti-people, we shall oppose it tooth and nail. This is the role of a responsible opposition and we shall play that role of a responsible opposition for all days to come.

Sir, in para 9 of the President's Address, the 'RURBANIZATION' — the new nomenclature — is nothing but so-called 'Gujarat Model'. According to the statistics

of the United Nations, India's urban population forecast is 631 million, and it will account 41.8 per cent of our total population by 2030. But, what about the measures to be adopted in regard to pollution in the cities and towns? There is no whisper about it in the President's Address. In 2012, India was the third largest polluted country in the world. What measures would be taken by this Government in this regard? There is no mention about it. I would urge upon the Government to come out with a definite plan and programme on this issue.

Sir, in paragraph 20 of the President's speech, the slogan of cooperative federalism has been raised. We salute cooperative federalism. My Leader, Ms. Mamata Banerjee, is the champion for the cause of federalism in this country. As per Article 1 of the Constitution of India, India, that is, Bharat shall be a Union of States. Therefore, it is a Union of States, not a unitary State. We respect this Article. This is an article of faith to us. Sir, in the recent past, we have seen that the successive Governments at the Centre set up the Sarkaria Commission and the Punchhi Commission on Centre-State relations and no uncanny respect has been given to the recommendations of the Sarkaria Commission and the Punchhi Commission which submitted its Reports in 2010. We are in the middle of 2014. This report has been sent to cold storage. There is no murmur about it. I would urge upon the new Government to bring out the Punchhi Commission Report from the cold storage, go through it and try to implement the recommendations in letter and spirit. Sir, I would like to quote two, three lines from the report of the Commission on Centre- State Relations, that is, the Sarkaria Commission, and reiterated by the Punchhi Commission. I quote: "When the emphasis is on the social justice, there is no escape from realignment of resources in favour of the States because services and the programmes which are at the core of a more equitable social order come within the purview of the States under the Constitution." This is the recommendation of the Sarkaria and the Punchhi Commissions. Sir, this is a Constitutional scheme which must be taken care of. If you want to have cooperative federalism, my point in this context is whether the Government is thinking to eliminate the vintage-Gadgil formula. Whether this new Government will adhere to the demands of the States for 50-50 sharing of the resources and revenues. Sir, my point is, as per Articles 268, 269, 270, 275, 280, 282 and 293, Finance Commission is the only Constitutional authority to look into financial relations between the Centre and the States. But what has happened? The Planning Commission, which was set up by an executive order, has emerged as the most robust extra Constitutional centre of authority over the years. We demand that the Finance Commission must have a permanent status and, if necessary, an appropriate legislation should be made in this regard. This is my humble suggestion to the new Government.

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

Sir, in para 23 of the President's speech, black money has been talked about. There cannot be two opinions about it. But what about those big companies which have diverted 13,000 crores of rupees during the past three years violating external commercial borrowing scheme? What about the on-going inquiries by the Income-tax Department against 498 Indian entities, operating from the tax havens like British Virginia Island, Cox Island and Cayman Islands? Therefore, the entire net of the black money is to be unearthed and the money so recovered it should be possessed by the Government of India only and none else. Sir, paragraph 35 of the President's speech says that गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है, यह अच्छा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी गंगा एक्शन प्लान देखे हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए गंगा नदी में बह गए, ठेकेदार लोगों ने गंगा पूजा की और उन्होंने गंगा एक्शन प्लान के सारे पैसे खा लिए। दोबारा ऐसा न हो, यह हम सरकार को चेतावनी देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा हुआ है। हम कामना करते हैं कि यह सफल हो। अगर यह सफल होता है, तो हम कोलकाता से बनारस जाएंगे। हमारी स्टीमर सर्विस है। हम यह गाते-गाते जाएंगे, "*हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैवो, सइयां से कर द मिलनवा।*" यह अच्छा है, इसमें हमें कोई हर्ज़ नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सर, पैराग्राफ 26 में जीएसटी के बारे में बताया गया। जीएसटी लागू होना चाहिए, यह तो ठीक है, लेकिन केन्द्र ने राज्यों को काम्पन्सैशन का जो ऐरियर देना है, वह राज्यों को नहीं मिला है। उसके बारे में इसमें एक लाइन भी नहीं है। I want a concrete assurance from the Government that the compensation towards Central sales tax should be paid before implementing the GST in the country.

सर, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एफडीआई के बारे में बताया गया। जब ये लोग विरोधी पक्ष में थे, प्रतिपक्ष थे, तो इन्होंने एफडीआई इन मल्टीब्राण्ड रिटेल का विरोध किया। हमने भी विरोध किया, जम कर विरोध किया। अब ये सत्ता में आ गए और अभी भी एफडीआई बोल रहे हैं। हमने अख़बार में पढ़ा कि डिफेंस प्रॉडक्शन में भी एफडीआई लागू होगा। इससे हमारी नेशनल सेक्युरिटी काम्प्रमाइज़ नहीं होगी? What about the national security? What will be the role of the DRDO? I would like to know whether there will be any existence of DRDO because even the software will be manufactured by the foreign investors. It is reported in the newspapers. I don't know about it. That should be clarified.

सर, पैराग्राफ 28 में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताया गया। हम चाहते हैं कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जो सोच पिछली सरकार की थी, उसको दोबारा दोहराया जाए। सरकार इसका ऐलान करे कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। यह ऐलान सरकार की ओर होना चाहिए। यह हमारी मांग है, क्योंकि इससे सिर्फ पश्चिमी बंगाल को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे सात राज्यों - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को मदद मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से अर्ज़ करूंगा कि वह अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम को expedite करे।

In fine, Sir, I would like to quote the concluding sentences.. ...*(Time-bell rings)*... Two lines only. I am concluding. ...*(Interruptions)*... I will not even take two minutes.

Sir, in fine, I would like to quote the concluding sentences of the book titled 'Undercover Economist'. It is authored by internationallyfamous writer Tim Harford. It says in concluding lines and I quote, "Faced with the costs and risks of trial and error, should you and I try to experiment and adapt more than we do? What price would we pay in our quest to succeed?" Hence, the new Government must be very cautious in its quest to succeed. We wish it all success. But the Government must be very cautious in its quest to succeed because the road is not rosy as I have tried to emphasize the situation.

With these words, I conclude. Thank you, Sir, once again for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for adhering to time. Now Shri Y.S. Chowdary. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he saved one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has saved one minute, for which I convey my special thanks to him. Now, Mr. Y.S. Chowdary, you have only 13 minutes. You have to adhere to that. I believe you are the only speaker from your Party. There are other names here, but I won't call them. Do you agree to that? If you take 13 minutes, no other name from your Party would be called.

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): All right, Sir.

Sir, I thank the hon. President for his Address outlining the Government's hope for the next five years. Beyond doubt, it was an excellent speech made by the hon. President. In fact, the beauty of democracy was reflected in his speech again and again when he said 'my Government' though it is led by NDA. I feel very happy about all the promises made by the Government.

Sir, talking about elimination of poverty, historically, post-Independence, successive Governments have always measured poverty or the poverty line as a percentage, without giving any credence to the increase in our population. That always gave us wrong signals. Hence, I feel that the poverty elimination is a most welcome subject. I am confident that the numerous measures that they have adopted already would improve the standard of living of the common people. This would automatically eliminate poverty. Particularly, when economic growth takes place, it would generate employment

and that would definitely eliminate poverty. The focus on healthcare, education and employment, particularly in the manufacturing industry, would also help. So, all these are welcome initiatives.

As we are all aware, unfortunately, the last two terms led by the UPA Government have seen a downturn in our country's economic situation. In 2004, when they came into power after the NDA Government's rule, India was about to become a super power, whereas the two successive Governments led by UPA brought us down from a super power to 'zero power'. In such a situation, my Party feels that all the initiatives taken by this Government give out a lot of hope and confidence that there would be economic reforms and growth.

Sir, there is a mention about improving the quality of life in our villages through an empowered Panchayati Raj system. At this hour, I would like to remember our founder Party President and the then Chief Minister, Shri N.T. Rama Rao. In fact, he had abolished the Patel Patwari system and introduced the Mandal system that encouraged decentralization of powers, which is close to the common public and through which villages were empowered to collect taxes, use them and manage the Budget by themselves. This initiative would definitely help our rural India to grow extremely well.

Sir, increase in investments in agriculture sector, both public and private, especially agri-infrastructure, has been mentioned. It is a long-pending issue. Majority of our country's population is dependent on agriculture. Despite knowing this extremely well, successive governments never bothered to provide a level-playing field to our farmers by creating cold storage facilities, building food processing units near the crop fields, etc. Our Party is very confident that by providing this kind of support to the farmers, very soon we could hope that our farmers would go to their fields driving cars. That is what our Telugu Desam Party hopes to do. Most of our farmers don't want any freebies or doles. They want to live with pride producing their products. We welcome the initiative. Now, I come to National Education Policy. It is also, in fact, a very long-pending subject. In fact, in the last decade, if you see, our standard of education has gone down extremely. This National Education Policy will definitely maintain common standard and will also give an opportunity to students to get into international employment. Now, there is a New Health Policy. We welcome the New Health Policy where holistic healthcare like yoga, ayurveda, etc., is also introduced which is affordable by common people. Unlike allopathic medicines, these medications

don't have any side effects. So, we welcome it. In addition to that, we also expect Primary Health Centres to be revived, which help our rural India.

Now, I come to the welfare of the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and weaker sections. Though we have been giving reservations in a focused manner, successive Governments have failed to take up these initiatives with conviction. In fact, 80 per cent of the independent India was ruled by one party. They had introduced the slogan 'Garibi Hatao', but they always managed to maintain 'Garibi Banao' so that they can manage gullible people to vote for them. In fact, the initiative of the new Government will definitely make a lot of weaker section people to come out of the problem.

Now, I come to women empowerment. Thirty-three per cent reservation is a long-pending subject. Although it has been passed by this House, it is kept pending. Our Party welcomes the initiative of the new Government. We hope that women will get 50 per cent representation, their due share, soon in every institution. Now, specific development models for the special needs and unique problems of coastal, hilly and desert areas. Our Telugu Desam Party is grateful that Government is committed to addressing the issues relating to the development of Andhra Pradesh and Telangana States which recently were divided in an unscientific, autocratic and undemocratic manner. This initiative should help both the States and their people.

Now, I come to e-governance. As you are all aware, e-governance was originally initiated by our present Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu. He is known as modern architect for using Information Technology. Our e-Seva model was copied and followed by many States Governments in this country. This is a welcome situation. Then comes employment opportunities. We have no doubts that all these kinds of initiatives, particularly thrust on manufacturing industries, will help both private and Government employment. That will make all our youngsters to get into jobs. Then comes setting up of world-class investment and industrial regions. Our Telugu Desam Party appreciates and welcomes this initiative. That helps every industry to compete with the global market. We are in a global village environment. Then comes modernisation of the life-line of the country, that is, Railways. Railways are common platform for common people to move around. Particularly thrust on developing infrastructure and also improving the facilities of the Railways is a welcome decision. High-speed trains will help to grow economy in a much speeder manner. Then comes the National Energy Policy. As you are all aware, Sir, in the last ten years, the successive UPA Governments have spoiled entire our energy system. In

[Shri Y.S. Chowdary]

Andhra Pradesh itself, 4000 MW project is completed, but it is kept idle because of policy paralysis either for environment or for fuel clearance. This policy will definitely help. We hope to get a lot of support from our friend, Mr. Piyush Goyal, who is heading the Energy and Coal Departments, to remove the bottlenecks in Andhra Pradesh.

Regarding creating new world-class cities, as the House is aware, we were thrown out of the State by dividing it without even the capital city. So, we have got 13 districts. Out of 100 world-class cities that they intend to create in the country, we hope to create, at least, 13 cities in our newly-formed State. That is a really very good initiative that will decongest all metro cities. Instead of transporting water, power and everything and having a lot of congestion in cities, this will automatically decongest the metros and also lead to uniform development of the States.

Regarding integration of rivers, some hon. Member pointed out that they have mentioned 'wherever feasible'. I would like to say that without feasibility, in any case, we cannot integrate or we cannot use any of the rivers. That is a very good initiative wherein we can facilitate both transportation of goods and people. Particularly for the State of Andhra Pradesh, I am grateful to this Government for issuing the Ordinance for constructing the Polavaram Project immediately, which was being kept pending for the past six decades. I request hon. Finance Minister to definitely create some budgetary provision to start this and put a foundation stone immediately. That is our special request.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Regarding the role of science and technology, in the past, our country has always been lagging behind in investing in science and technology, particularly in research area. That is why, we have to pay heavily for the technology imported from advanced countries. So, they now want to put that as a thrust area.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Just three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No three minutes. Please conclude.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Let me complete. Sir, you have thrown us out by dividing the State. This is our maiden speech. At least, you must consider that.

Then, regarding Defence equipment, this is a very good initiative to start production by private sector. That is going to save a lot of our foreign exchange because import substitution can take place.

Finally, I am proud to say that our Party proved to be a reliable Party in coalition Governments. If we see, out of five times, four times, we were associated in forming non-Congress Governments in this country. So, Telugu Desam Party has always been reliable and also participated in building this big nation. ...*(Interruptions)*... And, the combination of Chandrababu Naidu*ji* and Modi*ji* is a great combination. A co-branding will take place and their initiatives will bring our nation and economy back on track.

Finally, we know, it is a long and arduous task but as the Robert Frost said, 'The woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and long to go before we sleep and long to go before we sleep'. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Miles to go. Now, Shrimati B. Jayashree.

**श्रीमती बी. जयश्री** (नाम-निर्देशित): उपसभापति महोदय, आपने इस ऑगस्त हाउस में माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया है, इस के लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है।

**श्री उपसभापति** : आपकी हिंदी बहुत अच्छी है।

**श्रीमती बी. जयश्री** : लेकिन मैं अपने मन की बात को इस ऑगस्त हाउस में रखने की कोशिश करूंगी।

महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना और समझा है। सरकार के सोच-विचार व आशाएं देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसका रोड मैप क्या है, बच्चों के भविष्य के सम्बन्ध में उसके विचार, जीरो टॉलरेंस इत्यादि सुनकर बहुत खुशी हुई। लेकिन महोदय, मैं आपके सामने यहां कलाकारों की आवाज बन कर उन लोगों के दु:ख, विचार इत्यादि आप तक पहुंचाने के लिए खड़ी हूं। माफ कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात न समझिएगा।

माननीय महोदय, इस पूरे अभिभाषण में देश की कल्चर, ट्रेडिशनल फॉर्म्स, फॉक फॉर्म्स, ट्रेडिशनल आर्ट्स, परफोर्मिंग आर्ट्स, इत्यादि के लिए एक भी योजना नहीं है और गलती से एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। देश की परंपरा और संस्कृति का हम बहुत सालों से पालन-पोषण करते आ रहे हैं। प्रहलाद नाटक, कृष्ण परिजात, बयलाट, नौटंकी, तोगल-गोम्बे अट्टा, मतलब सालों से जो प्रोफेशनल आर्ट, ट्रेडिशनल फॉर्म, फॉक फॉर्म, ऐसे बहुत से आर्ट्स फॉर्म्स चले आ रहे हैं, ये सब कहां जाएं? इसके कलाकार लोग इसके सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं और यह उन कलाकारों की रोजी-रोटी है। आजकल इस फॉर्म को देखने वाले भी नहीं हैं। इस कारण ये लोग अपने बच्चों को भी अपनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जब खुद का पेट नहीं भरता है, तो उस परंपरा को कैसे आगे ले जाएंगे और

[श्रीमती बी. जयश्री]

बच्चों को क्यों सिखाएंगे? सीख कर वे क्या करेंगे? बच्चे सीखें या न सीखें, बच्चों को सिखाएं या न सिखाएं, तात्पर्य तो यह है कि बहुत सारे आर्ट्स फॉर्म्स मरते जा रहे हैं और कुछ अंतिम सांस ले रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहती हूं कि अपनी संस्कृति, परंपरा को बचाने के लिए अभी तक इसका पालन-पोषण करते आए कलाकार लोगों के लिए भी आप कुछ योजना बना दीजिए। हमें निर्लक्ष्य मत कीजिए। हम बहुत साधारण, सिम्पल लोग हैं, लेकिन बहुत गर्व और मर्यादा से जी रहे हैं। मेरी विनती है कि हमारी तरफ भी आप मुड़ कर देखिए और हमारी संस्कृति, परंपरा को जिंदा रखने के लिए कुछ योजना बना दीजिए।

महोदय, इसमें कहा गया है कि हर स्टेट में आईआईटी, आईआईएम प्रारंभ करेंगे। आपके माध्यम से मेरी विनती है कि हर स्टेट में एक एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रारंभ कीजिए। इस ग्लोबलाइजेशन में हम खोना नहीं चाहते हैं और आप भी हमें खोने मत दीजिए। धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I take this opportunity to pay my tributes to the Constitution of India. The Constitution of India has been holding our great nation together in all the turbulences and turmoil of history. Dr. B.R. Ambedkar, very thoughtfully, stated that true independence came to the people of India with the adoption and enactment of this fundamental law of the country. Sir, it is because of the social and economic rights enshrined in the Constitution, the Parliament has been enacting legislations to empower people whose franchise is making, unmaking the Governments.

We need to protect this architecture of social and economic rights, without which our political democracy, again in the words of Dr. Ambedkar, would be a sham. Sir, when Shri Modi, the hon. Prime Minister, entered the Central Hall for the first time as a newly-elected Member of the Lok Sabha and addressed the elected Members of his party, he referred to the Constitution and our democracy, and emotionally stated that it is because of the Constitution and democracy that a person like him, who hailed from a humble background, could come to that level and aspire to become the Prime Minister of our country. It is heartening that he referred to the Constitution in the Central Hall where the Constitution was framed, adopted and enacted. Sir, our Constitution is a republican Constitution, not a theocratic one. Our democracy is a political parliamentary democracy, not a Presidential form, not a two-party system. Sir, for the benefit of the new Government, I would like to recall during the last NDA Government, when our hon. K.R. Narayanan was President, an attempt was made to review the Constitution. Sir, Dr. Narayanan, while addressing the nation in the Central Hall again, on the occasion of the 50th anniversary of our Republic, very pointedly asked, “Let us examine, whether Constitution has failed or we have

**1.00 P.M.**

failed the Constitution". That is what Dr. Narayanan asked. Sir, all those who talk about reviewing the Constitution must have cultivated or they have not cultivated what Dr. Ambedkar poetically said, 'The Constitutional morality'. By cultivating Constitutional morality in a very comprehensive manner, we can keep this country united and uphold its secular identity. Sir, in fact, our public life can be greatly disciplined or fine-tuned by cultivation of Constitutional morality. It is because of the absence of such Constitutional morality, the most of our problems, be it social, economic or political, are being generated. Sir, it is, therefore, extremely important to uphold the Constitution, I am telling the new Government, and the Constitutional morality. It assumes more significance in the context of raising counter culture based on religious fundamentalism, violation of women's rights; I do not mean only human rights, denial of economic rights of the poor, under-privileged, the minorities and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Sir, I would like to refer to the President's Address. The President's Address is supposed to be an outline of the vision of the Government of the day. But except a change in the political phraseology, a change in the political demagogue, I do not find a fundamental departure from any policy pursued by the previous Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, one second. There is a proposal that we will have only half-an-hour lunch-break today. If the House agrees, we will sit up to 1.30 p.m. and then take half-an-hour lunch break. I hope you agree.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, please continue, Mr. Raja.

SHRI D. RAJA: Sir, I very keenly listened to what Mr. Jairam Ramesh has said. In fact, he has confirmed that both the Governments, whether headed by the Congress or the BJP, have been pursuing the same policies be it their economic policy or foreign policy. Given the situation where the corporate capital and the international finance capital have tremendous influence and power on both these parties, I don't think we can alleviate or eliminate poverty in the coming years.

Sir, referring to the mandate, on the meaning of mandate, the Leader of the House, Mr. Arun Jaitley, tried to justify how people voted. I do not question the mandate of the people. In fact, I acknowledge, I accept the mandate of the people. But the interpretation given by the Leader of the House really makes it imperative

[Shri D. Raja]

that all the political parties must think of going for comprehensive electoral reforms. That includes proportional representation system. First-past-the-post system, which we have today, has exhausted all its potential. Now we have to think of proportional representation system which has been accepted by many countries in the world. In the interest of our democracy, I think the time has come to look at this issue.

Sir, on different problems, I am moving amendments. I do not want to take this time to explain those. But the Government has rightly identified agriculture as one of the priority areas. At the same time, the Government should have referred to the recommendations made by the National Commission on Farmers in the President's Address.

Sir, the HRD Minister is sitting here. The President's Address talks about a new National Education Policy. But the point is, Indian education is becoming more and more privatised and more and more commercialised. The Twelfth Five Year Plan talks about PPP model as far as higher education is concerned. What will happen to the students coming from poor, downtrodden and underprivileged sections of society? The previous Government also accepted the Twelfth Five Year Plan. The PPP model will be allowed in higher education. Now the present Government talks about the same thing. Will you have a relook at the Twelfth Five Year Plan?

Sir, there is no mention of a Central Legislation to govern the Scheduled Castes Sub Plan and the Tribal Sub Plan. And it is a demand across the country. The Central Government should have such a legislation. The previous Government did not do it and the present Government is unlikely to do it because there is no mention of it in the President's Address. There is no mention of the policy of reservation. How will it be implemented? People referred to the policy of reservation in promotions. The country is going for more and more private sector. Neoliberal policies are aggressively implemented everywhere. There is a need for reservation in private sector also. We will have to take a relook at all these issues.

I welcome the move to pass the Women's Reservation Bill. Now who is going to prevent you? You have your own absolute majority in the Lok Sabha. The NDA has absolute majority now. As per your commitment, you show your political will and determination to pass the Women's Reservation Bill. It is no use just talking about team India. The Government should really think of taking all the States together and try to solve the inter-State problems. You have rightly said that a drop of water is precious in India and water resources are precious for India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI D. RAJA: Sir, I am concluding. So, in order to sort out the water problems, river water problems including Cauvery, I think, the Central Government should have an initiative to take Governments in stride and find a solution.

Sir, there is no mention about the public sector, strengthening and expanding the public sector. My friend, Mr. Jairam Ramesh, talked about the 123 agreement. Yes, we opposed that agreement. On that issue, we had to withdraw support given to the UPA-I Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja.

SHRI D. RAJA: But, my point is, because of the strong opposition from the Left, the Parliament could enact a Civilian Nuclear Liability Act. There was pressure from the American Government, there was pressure from the French Government, to weaken the nuclear liability. Now, I am asking the new Government: Are you going to follow Mr. Jairam Ramesh and the Government in which he was a Minister or will you take an independent position? Otherwise, what will happen to the country?

Sir, finally, there are two issues. One is the question of fishermen and my good friend Dr. Maitreyan dealt with that issue. But, my only simple question is this. I asked the previous Government. I am asking the new Government — Katchatheevu agreement is a bilateral agreement — whether this Government is prepared to ask the Sri Lankan Government to reopen and renegotiate the Katchatheevu agreement or not.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That’s okay. That’s all right.

SHRI D. RAJA: Sir, unless you do that, the Government cannot protect the fishermen. Sir, the last point is, the foreign policy matter, in my understanding, cannot be the monopoly of one political party in the country. Foreign policy should evolve on the basis of a consensus, a national consensus. The foreign policy cannot be an abstract policy. It should be a policy which evolves in a concrete situation on the basis of concrete realities. Here, I think, the question of the Sri Lankan Tamils will have to be addressed and the Government cannot close its eyes to the sufferings of the Sri Lankan Tamils, and the Government should demand a political solution to the problems of the Sri Lankan Tamils as early as possible.

Sir, with all these things, I have given some amendments. The Government should take note of all these things. Sir, the President’s Address is the vision document

of the Government and that vision must be a proper vision which can help the country to move forward. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Ashwani Kumar.

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to speak on the President's Address and at the very outset, I would like to thank the hon. President for his Address to both Houses of Parliament.

Sir, the Address of the President is supposed to provide a roadmap and a charter for the future of the country and for the collective future of its people. It's also, Sir, a document around which we organise what has been described as the conversation of democracy. To that extent, it is, indeed, a solemn document and a document on which the august Houses of Parliament debate in all seriousness in order to enrich its contents and not necessarily to censure it. It is in that spirit, Sir, with your permission and with the permission of my leader, I rise to make some constructive suggestions.

Sir, I have had the privilege of listening to the Leader of the House, who said that there is no copyright on ideas. Indeed, I readily agree that there is never a copyright on ideas, but I would not have been faulted for saying that at least, in the very least, there should have been an acknowledgment in the Address that the Address builds on the grand edifice that was laid by UPA-I and UPA-II. To the extent that the Leader of the House acknowledged and, I would like to thank him for, albeit a grudging acknowledgement that the grand edifice which, armed with the mandate, he seeks to build for this country is to be upon the edifice laid down in the last ten years in a monumental expansion of the social empowerment programmes and what has defined the UPA-I and UPA-II. In the history of independent India and facts speak for themselves, and as somebody has said, one is entitled to one's opinion but one is not entitled to invent one's own facts, these facts have been solemnly recorded in the President's Address of 2013, which is a statement of the Government on record; and none has disputed the facts contained in that. I am building on those facts. To say and argue that had anything been done, we would not have lost the elections is an absolute travesty of argument. Elections are won and lost on the basis of a number of factors. They do not at all detract from the very substantial insignificant achievements that the UPA-I and UPA-II have to its credit.

Sir, I want to comment on two broad themes which pervade in my understanding the entire Address. The two themes are: (a) This was an election of hope; (b) That

this is an election that has deepened our vibrant democracy. These are pertinent themes for discussion. With your permission, I would like to make a few comments on these. It is true that every election raises hopes and every election is premised on the ability of parties to raise hopes in the minds of the people in the common future. I am not oblivious since it is of recent occurrence of the election campaign of the ruling party. The ruling party has certainly succeeded in selling tremendous hope to the people of India. I was waiting to see that promise of hope being translated into concrete action. When both the Houses met, because that is the first opportunity you got to indicate to the people of India in concrete terms what you intend to do to translate that hope into reality, on the very first day, when they talked of hope, they talked of the hope of healing the wounds of the past resulting from a fractious and contentious politics. Well said, I entirely endorse that sentence. I think the conversation of democracy can't be advanced in an atmosphere of perennial personalised conflicts. We have to rise above these conflicts because the magnitude of the challenges that we face, the gap between the magnitude of the challenges that we face and the smallness of our politics is staring us in our face, and people are judging us for what we represent in action, not what we represent in words. So, what do I see? We have heard the debate yesterday. A principal spokesman and intervener on behalf of the ruling party said that the Congress Party has been reduced to a status of a regional party. It was mocking us, in a manner that does not behove a party that has received such a large mandate. Magnanimity in victory was expected; and also humility. But I sense none of these. On the very second day of taking oath, an hon. Minister of this Government which seeks to bring the Kashmiri pandits back to Kashmir; talks of abrogation of Article 370. In a sensitive State like Kashmir. The first statement that permeates from the office of the Minister of State in the Prime Minister's Office is a contentious statement on Article 370. And this is a matter of great sensitivity not only for the State of Jammu and Kashmir but also for the country as a whole. And we are privileged to have with us today the leader of my party, the Leader of the Opposition, Shri Ghulam Nabi Azad. When he was Chief Minister, it was he who initiated the process of rehabilitation of Kashmiri Pandits with 25,000 houses made in Jammu and an equal number of houses in the Valley. ...*(Interruptions)*... I am being told now that there was a start of the construction but that could not be expanded for various reasons. But the fact remains that the initiation of that process was started earlier. I am not here to take an exclusive credit for my party. But it is a fact that it was our Government which started this process. I come from a district which adjoins Jammu and Kashmir. Sir, I know the feelings

[Shri Ashwani Kumar]

there. We were not unmindful of those sensitivities and we tried our best to do our best. The point which I am making here is that when you talk of hope, giving hope to the people that we would heal the wounds of a fractious politics, please, for heaven's sake, restrain yourselves from making statements which would have international ramifications and serious ramifications for the unity of our country.

Sir, I would also like to take this opportunity of talking about, what they call, the deepening of our vibrant democracy. How do we deepen our vibrant democracy? Elections are symptomatic reflections of the strength of our democracy. But our democracy does not end and begin. With elections our democracy is much more than winning and losing elections. And, as was rightly said by the Leader of the House and the Leader of the Opposition some win and some lose. Those who are on that side were here yesterday. We are here today and we may be there tomorrow. That is the glory of democracy. That is the strength of democracy. But the democracy is something more. We have given unto ourselves a constitutional democracy, a democracy that is anchored in the pillars of the Constitution. What are those pillars? These are the pluralist, liberal and secular India. I ask myself: "Is there anything in this Document that underscores it, underscores it in a manner that anyone, who reads it plainly, would say, "Here is a Government that truly understands the meaning of India's constitutional democracy."? Not a word, Sir, in the entire Document on the expansion of human freedoms. The idea of India is not just about the expansion of GDP. It is that, but it is much more than that. The idea of India is about the contest of ideas. It is about the relentless expansion of human freedoms. It is about liberalism. It is about the right to privacy, the right to reputation, the right to dignity and the right to be left alone. All of these were subject-matters in elections. Whether you talk of snooping incidents, whether you talk of investigative agencies, this is a constant wound on the soul of the Indian Republic, and it would require all of us to rise, above partisan considerations, to address these issues. These are issues which if, not addressed, would diminish the quality of India's parliamentary democracy. Therefore, the vibrant democracy, which the Ruling Party today talks of, completely misses the core of our democratic experiment. When we go through the Constituent Assembly debates, it was these subjects that were talked about. Of course, there is a mention about the disturbed balance between the institutions of our constitutional democracy, that is, between Parliament, Judiciary and the Executive. But not a word is indicated

on how you are going to restore that balance. We are with you. We will seek to help you restore this balance. It is critically important. A civilized society does not live only by the stomach, Sir. Civilised people and a civilized society live by fundamental human freedoms. This has been the lasting glory of India's democracy. The proudest achievement of the Indian State has been its persistent democratic resilience. It is the strength of the people of India that sustains our democracy. You have received a mandate to govern. I would ask you to work with the Opposition and Opposition will work with you as far as restoring this Constitutional balance and strengthening the pillars of India's democracy is concerned.

Sir, I want to make one major point about which I feel very strongly. India is perhaps the only civilized country in the world which does not have a law on privacy! Our private rights are protected under Article 21 of the Constitution. Our Government had initiated a privacy law. It is lying in the PMO's Office. When I was in the Planning Commission, I had constituted a Committee under the Chairmanship of Justice A.P. Shaw — now Chairman of the Law Commission — to talk of this law. Every encroachment on human rights and on individual rights is justified in the name of security of the State. This is the message of history. A civilized nation knows how to balance security and individual freedom. Somewhere that balance has been lost. And, I want to take this opportunity of stating the need to recreate a society, a country and re-establish processes of governance where individual dignity and integrity is not compromised at any cost. Sir, I have spoken about two basic themes.

I, now, want to talk about what the Address says in terms of social and economic empowerment. I have the verbatim Address of the hon. President in 2013. Everything has been picked up from what we had said. I can understand, as the hon. Leader of the Opposition rightly said, "नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है।" I don't mind you building on what we created. But, have the intellectual integrity to give us that credit, not for ourselves. Give credit to the people of India. Give credit to the country as a whole which realized its priorities. And, you are realizing those priorities; I am happy for it. I am not going to find fault with what you have stated. But, all I am saying is: If you want to start on a clean slate and if you want to promote constructive politics, have the generosity to admit the need of cooperation. You have talked of co-operative federalism. How can you have co-operative federalism if you don't have political co-operation? It is not only a question of State and the country. It is a question of an *inter se* co-operative attitude to make democracy work.

[Shri Ashwani Kumar]

Sir, on foreign policy aspect, I would say it is very important. It is very important because India is racing to find its place in the comity of nations. We are a trillion dollar economy. We are the 10th largest economy now in the world and we are supposed to be the 5th largest very soon. We need a place on the high table of global politics. Not a word on the reforms of the UN. There is not a single word on the reform of the Bretton Woods institutions established years ago! Not a word about the new geo-political architecture of global power! There is no reflection of this in the Address; It should have been. If you talk of looking at world leaders in the eye from a position of strength, at least, ask for the expansion of the UNSC Permanent Membership where India must legitimately find its place. Not a word about BRICS! Not a word about ASEAN-Indian relationship! In the Commemorative Summit held sometime ago between ASEAN and India, India's position was elevated to one of a strategic relationship with ASEAN. Sir, Japan, the most unique relationship that the earlier Government has been able to foster is the relationship with Japan. Never in the history of the world, never in the history of Japan, in the last several hundred years, did the Emperor and the Empress of Japan and the Prime Minister of Japan visit any country within one month. They signaled to the world that India meant a lot to them and even so the relationship with Japan has been dismissed in half a sentence! Come to China. We have a great relationship with China. We must continue to expand this relationship. It is our largest trading partner. But don't forget that China is your competitor. The strategic parity between India and China on defence is 1:8! I remember, having written to the then hon. Defence Minister on the need to correct this parity in air power, naval power, etc.

Even in the use of English by the Chinese where we were far ahead, they are catching up on us. The largest number of students from anywhere in the world who go to the U.S. to study in higher educational institutions are now from China. China is both a friend and a competitor. We need to be on guard.

I am glad, there is a mention of our traditional relationship with Russia. But, Sir, today, countries don't live in isolation. We live in a globalised world. Anything that happens anywhere in the world impacts us. I ask this question, Sir; Why such a perfunctory treatment of the considerable advances and the successes that the UPA-I and UPA-II achieved on the foreign policy front?

Sir, on science and technology, I have had the privilege and the honour of being in that Ministry. There is reference to certain Avante Garde areas of science and

technology. We all know that without innovation, without harnessing science and technology, India can't prove itself as a nation in the first lines in the comity of nations. But, not a word on supercomputing! I am amazed, whoever gave those inputs, not a word on supercomputing! Sir, we were up there much higher than China in supercomputing capabilities till 2006-07; we realised that we have slipped and I had initiated this programme of enhanced supercomputing capabilities. Our naval warfare, our air warfare, our space programmes, our nuclear medicines, everything depends on the capacity of supercomputing. Without supercomputing capability of a particular level, India can never aspire to take its place as a frontline nation. These are glaring omissions, Sir.

Sir, two more minutes and I am done. I heard the Leader of the House, Mukhtar Abbas Naqvi *sahab*, and others, explain what the mandate of 2014 was about. Sir, I don't want to spoil the party of the ruling party. I acknowledge that they have received the mandate of this country. I compliment you. I congratulate you. I am happy for it. But, please don't mistake knowingly what this mandate is about. A 31 per cent vote as distinguished from a 69 per cent vote does not give you the mandate of the majority of the people of this country. They have expressed reservations. It is, because of, the functioning of our Parliamentary democracy in action; you have got a far larger number of seats than the vote share. But, if you want to advance our democracy and deepen it, realise the fallibility of your claim; you don't represent the majority view in India. The Congress is still a party spread in every village throughout the country. It is a party that has risen from the ashes, and history testifies to that fact, and will do so again under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi.

Sir, in conclusion, on this last aspect, I can only refer in all humility to our decline in numbers. But, I want to tell you and you know it in your heart, you know the fragility of your position. It needs just a few issues that will catch the imagination of the people to upset the apple cart. As somebody said,

हमको मालूम है जन्नत की हक़ीकत लेकिन
दिल के ख़ुश रखने को 'ग़ालिब' ये ख्याल अच्छा है।

Don't confuse yourself, you have to be taken out of the vassalage of your delusions.

Finally, I would like to end by saying we may be down but we are not out. We will work as the custodians of national and public interest until our last breath. Sir, as someone said, 'ऐ मौज-ए-हवादिस', what it means is, Sir, when big waves come

[Shri Ashwani Kumar]

in the ocean, big ship are tossed down by those waves, but sometimes, even smaller boats can challenge the storms.

"ऐ मौज-ए-हवादिस बेकसों से जरा दूर ही रहना।
कि शिकस्ता कश्तियां अकसर उलझ जाती हैं तूफां से।"

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch to meet at 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at three minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

**श्री विजय गोयल** (राजस्थान): सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तीन बार लोक सभा का सदस्य रहा हूं, किन्तु राज्य सभा के सदस्य के रूप में पहली बार मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है। कल से मैं सारी डिबेट्स को सुन रहा हूं। मैं नहीं समझता कि किसी भी सदस्य का, जो यहां बैठे हुए हैं, 16 पेज के अन्दर 50 पैरों में आए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें छपे हुए एजेंडा से, उसकी नीतियों और उसके विचारों से विरोध है। वैसे भी इस सदन की परम्परा रही है कि हम सर्वसम्मति से, यदि कोई संशोधन आ जाए तो बात अलग है, किन्तु हम सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित करते हैं। बहस इस बात के ऊपर हो रही है कि ये जो बढ़िया से बढ़िया नीतियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई हैं, ये जो विकास का मॉडल पूरा का पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्दर झलकता है, उसका श्रेय कौन लेगा। इसलिए, जब गुलाम नबी आज़ाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो आपने हमारी ले रखी हैं। तब आपको तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का इतना उदार मन है कि अगर आपकी भी कोई चीज़ अच्छी थी, तो उसे लेने के लिए तैयार हैं।...**(व्यवधान)**... चारे की बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**... जिस समय आपकी सरकार आई थी और जिस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्दर हम उसका जवाब दे रहे थे, तब हमने भी यह बात रखी थी कि मानो आपने हमारा सारा का सारा एजेंडा ले लिया है। आप हमारे नेताओं के भाषण को देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा।

सर, मुद्दा यह नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक लम्बी फेहरिस्त गिनवाई कि ये-ये काम हमने किए थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की लाइनें हमने बिछा दीं, आरटीआई को हम लेकर आए, मनरेगा को हमने लागू किया, बिजली के क्षेत्र में हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया, सर्व शिक्षा अभियान को ले आए।...**(व्यवधान)**... आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी शायर ने एक बात कही है। उस शायर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने कहा

कि 'तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता फिर कारवां लुटा क्यों?' तो फिर आप हारे क्यों, इसकी विवेचना कीजिए। अगर गुलाम नबी आज़ाद जी ने इतनी बातों की पहले जाकर मार्केटिंग की होती, तो शायद कांग्रेस को आज 44 तक नहीं सिमटना पड़ता...**(व्यवधान)**... हां, मार्केटिंग। आप उसको कोई भी शब्द दीजिए। मैं आपको एक बात और बताता हूं। अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा न हो, तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के अन्दर विकास किया था, इसलिए पूरे देश के अन्दर उस बात की मार्केटिंग हो पाई।

**श्री शान्ताराम नायक** (गोवा) : मोदी प्रोडक्ट है क्या, यह बताइए।...**(व्यवधान)**...

**एक माननीय सदस्य** : इनको टोकिए मत प्लीज़।...**(व्यवधान)**... यह इनकी मैडन स्पीच है।...**(व्यवधान)**...

**श्री विजय गोयल** : सब जगह समस्याएं एक जैसी हैं। किसी की भी सरकार आ जाए,...**(व्यवधान)**... सब जगह समस्याएं एक जैसी हैं, चाहे वह नाली की हो या खड़ंजे, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आतंकवाद अथवा भ्रष्टाचार की हो। कोई भी सरकार आएगी तो उसे उनका सामना करना होगा। इस सरकार के आने से पहले जो पिछली सरकार गई, जो डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की वह सरकार जब आई थी, तो मुझे दुःख हुआ था, किन्तु जब डा. मनमोहन सिंह जी उसके मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने, तो मुझे सुकून मिला था कि एक ईमानदार व्यक्ति और एक अर्थशास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री बना है, चाहे कांग्रेस की यूपीए की सरकार बन गई है, लेकिन उसका स्वागत करना चाहिए। उनके ऊपर लोगों को बहुत विश्वास था। उनको विश्वास था कि अगर इन्होंने सौ दिन में महंगाई कम करने को कहा है तो शायद ये उस महंगाई को कम कर देंगे, किन्तु उनके इस विश्वास को धक्का लगा। हमने सोचा कि डा. मनमोहन सिंह जी बैठे हैं तो सारा देश ठीक चलेगा। उसी ईमानदार प्रधानमंत्री के नीचे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, यूपीए की सरकार के अन्दर हुआ।

मुझे याद है, पाकिस्तान की गायिका रेशमा एक बार मेरे घर में आई थीं। वे एक मशहूर गायिका थीं। उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था - 'लम्बी जुदाई'। वे कहने लगीं कि गोयल साहब, एक बार जब मैं लंदन में गा रही थी तो सामने एक आदमी सो रहा था। मैं गा रही थी और सामने वह आदमी सो रहा था। मैंने कहा कि मैं गा रही हूं और तू सो रहा है? तब उस आदमी ने मुझे कहा - 'बेबे, तू गाए जा, हमें पूरा विश्वास है कि तू ठीक ही गाएगी।' ऐसे ही मुझे भी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह पर विश्वास था, किन्तु वह विश्वास टूटा और आज अगर किसी ने उस विश्वास को जगाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश के सवा सौ करोड़ लोगों के बीच उसे जगाया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े आराम से आज श्री जयराम रमेश जी ने एक बड़ी बात कह दी। मैंने जब लोगों के भाषण सुने, परन्तु उनका भाषण सुन कर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे दुःख पहुंचा। मुझे इसलिए दुःख पहुंचा कि वे एक मिनिस्टर रहे हैं, वे कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। इस चुनाव को जीतने में कितनी ताकत लगी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 82 करोड़ वोटर्स में से 56 करोड़ ने वोट डाले। 21 करोड़ लोगों से श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने जीवन्त सम्पर्क किया और 18 करोड़ वोट हमने पाए। आपने एक झटके में कह दिया कि यह कम्यूनल पोलराइज़ेशन है।

[श्री विजय गोयल]

श्री नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने जात-पात को तोड़ दिया, धर्म को हटा दिया और पहली बार इस देश के अंदर लोगों ने जाति-पाति और धर्म से ऊपर उठ कर वोट किया। यह इस चुनाव की महत्ता है। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर मुझे एक इन्सिडेंट बता दीजिए, जिससे आपको यह लगता हो कि इस चुनाव के अंदर कहीं हम लोगों ने साम्प्रदायिक बनाने की कोई कोशिश की, किन्तु मेरे पास बहुत-से उदाहरण हैं, जिनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कम्यूनल पोलराइज़ेशन किसने किया है। इससे पहले जब छः राज्यों के चुनाव हुए थे, उन राज्यों के चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती, तो क्या वहां कम्यूनल पोलराइज़ेशन हुआ था? क्या हमने कम्यूनल पोलराइज़ेशन किया था? जिस समय मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, क्या वह स्टेटमेंट हमारी थी? जिस समय गृह मंत्री ने यह बयान दे दिया कि यहां पर हिन्दू टेरर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या वे बयान हमारे थे? जिस समय शाही इमाम को बुलाकर आपने उनसे यह फतवा जारी करवा दिया कि देश के सारे मुस्लिम एक तरफ वोट करें, क्या वह हमारा बयान था? जब सहारनपुर में इमरान मसूद ने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि मैं बोटी-बोटी काट कर भेज दूंगा, क्या वह हमारा बयान था? अभी जयराम रमेश जी ने खड़े होकर बड़े आराम से कह दिया कि यह कम्यूनल पोलराइज़ेशन था। आप एक बात बता दीजिए कि 12 साल से आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सवा सौ करोड़ जनता ने आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको क्यों बरी किया? इसलिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप बड़े आराम से जिस चीज़ को कह देते हैं, मैं समझता हूं कि उससे और ज्यादा कम्यूनल प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। मैं चांदनी चौक से दो-दो बार जीत कर आया हूं। मुझे गंगा-जमुनी तहज़ीब का पता है। मुस्लिम-मुस्लिम का ज़हन पता है। मैंने उनके बीच में विकास का काम किया है और वही विकास के काम का एजेंडा हमारे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के भाषण में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबका विकास और सबको साथ लेकर चलना है। अगर मदरसों के आधुनिकीकरण की बात किसी ने की, तो वह किसी और ने नहीं की, बल्कि वह हमारे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के अंदर हमारी सरकार ने की है। यह जो सरकार आई है, यह दो कारणों से आई है।...(**समय की घंटी**)...

**श्री विजय गोयल** : सर, यह मेरी मेडन स्पीच है।

MR. CHAIRMAN: Please stick to your party time. We are working on a very tight schedule.

**श्री विजय गोयल** : यह जो सरकार है, यह आप लोगों के कारण आई। मैं और बड़े उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। जिस तरीके से गरीब आदमी को आपने पूछना बंद कर दिया है, उससे आपने नाता तोड़ लिया है, जब कि कभी आपका नारा हुआ करता था, "कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ।" आप और दूर मत जाइए, बल्कि दिल्ली के उदाहरण उठा कर देखिए। आपने "राजीव रत्न आवास योजना" निकाली। उस योजना के तहत आपने तीन लाख फॉर्म भरवा लिए और आपको

जानकार आश्चर्य होगा कि तीन लाख में से एक भी आदमी को आप फ्लैट देने में समर्थ नहीं हुए। यह सीधा-सीधा गरीबों के साथ अन्याय था। आपने अनधिकृत कालोनियां, जिनमें 40 लाख लोग रहते थे, उन अनधिकृत कालोनियों को आपने गलत बोल कर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए कि हम आपकी कालोनियों को नियमित करेंगे। एक भी कालोनी नियमित नहीं हुई। यह जो दिल्ली का नमूना है, यह पूरे देश में लागू हो रहा है।

आपने यह राग अलाप दिया कि 100 दिन के अंदर आप महंगाई को कम कर देंगे, किन्तु महंगाई कम नहीं हुई, उलटे महंगाई लगातार बढ़ती गई और लोगों को अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया।...**(समय की घंटी)**...

आपने राइट टू एजुकेशन तो किया, किन्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर देना भूल गए। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत आप देखिए। वहां बच्चा अपनी आन्सर शीट पर लिख कर आता है कि हिम्मत है, तो फेल करके दिखाओ, बताओ पास हुआ कि फेल? वह पास हो गया। वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, किन्तु आपने कह दिया कि हम यहां पर राइट टू एजुकेशन करेंगे।

हम यहां एयर-कंडीशंड हाउस में बैठे हैं, किन्तु बाहर दिल्ली झुलस रही है। आज दिल्ली के अंदर जो बिजली की समस्या है, वह 49 दिन की "आप" गवर्नमेंट की कम और 15 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट की ज्यादा है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त करें, प्लीज़। अभी आपके पार्टी के और मैम्बर्स भी बोलने वाले हैं और आपका टाइम बहुत कम है।

**श्री राजीव शुक्ल** (महाराष्ट्र) : दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तब 10-10 घंटे की बिजली की कटौती क्यों नहीं हुई और आज क्यों हो रही है?

**श्री विजय गोयल** : आप दो बातों को समझिए। पहली बात यह है कि उस समय भी घंटों की कटौती थी और दूसरी बात यह है कि जमीन के दाम जो कि आसमान पर पहुंच रहे थे, वे उसी समय पर थे, इसलिए मुझसे वे सब चीज़ें मत खुलवाइए कि उस समय क्या-क्या हो रहा था। उस समय यहां तक हो रहा था कि आप लोगों ने बिजली कम्पनियों से * करके यह सब किया था। इतना भ्रष्टाचार था कि जो ट्रांसमिशन की लाइंस उनको समय से बिछानी चाहिए थी, वे उन्होंने नहीं बिछाई थीं।

सभापति जी, मैं कन्क्लूड करते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**... सर, मैं अभी इस पर बहस नहीं कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री विजय गोयल** : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस समय सदन में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सब लोग इकट्ठे हों। आज जो करोड़ों लोगों ने इस सरकार को अपना मत दिया है, वे नरेन्द्र मोदी जी की आंखों में एक सपना देखते हैं और वे हम सब लोगों की आंखों में देखते हैं कि हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, आतंकवाद हटाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर ही यह कर सकते हैं।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री विजय गोयल]

अंत में, मैं अटल जी की कविता की चार लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आज वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण संसद में नहीं हैं, किन्तु उन्होंने जो सपना देखा था, मुझे वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था:-

"बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं
पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं
निज हाथों से हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।"

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने ही नहीं बल्कि लाखों-लाख लोगों ने महंगाई, अत्याचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इस सरकार को वोट दिया है। आप सबका समर्थन अपेक्षित है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Gundu Sudharani; not present. Shri G.N. Ratanpuri; not present. Shri Rajeev Shukla.

**श्री राजीव शुक्ल** : सभापति जी, आज सम्माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे भी संक्षेप में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परम्परा यह है कि अभिभाषण सरकार तैयार करती है, मंत्रिमंडल उसको मंजूरी देकर भेजता है और फिर राष्ट्रपति पढ़ते हैं। मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि चुनाव प्रबंधन में जो लोग लगे थे और ऐडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लोग जो नारे बनाते थे, उनका अभी भी इस अभिभाषण को लिखने में बड़ा भारी योगदान है। इसमें इतने स्लोगंस दिए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। "एक भारत-श्रेष्ठ भारत", "सबका साथ-सबका विकास", "हर हाथ को हुनर", "स्वच्छ भारत मिशन", "वन बंधु कल्याण योजना", "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ।" एक तरह से इसमें स्लोगंस की भरमार है, जैसे चुनाव के पोस्टर्स में होते हैं। लेकिन, ठीक है, यह सरकार का अधिकार है।

मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जब कोई सरकार आती है, तो शुरू में उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसको काम करने का, परफॉर्मेंस देने का और अपने वादों को निभाने का अवसर देना चाहिए। इसलिए हम कोई उस तरह की आलोचना नहीं करना चाहते जिससे किसी किस्म की कड़वाहट पैदा हो। मैं तो कहता हूं कि जो वादे आपने चुनाव में किए, चुनाव में भाषणों के दौरान किए तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहे, उनको पूरा कीजिए। हम खुशी से उसका स्वागत करेंगे और उस पर अपना समर्थन देंगे। आपने कहा, हम गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। खत्म कर दीजिए, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। आपने कहा, सारे खेतों को पानी दे देंगे। बिल्कुल दे दीजिए, हम पूरी तरह से स्वागत करेंगे। आपने कहा, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। हम इसका स्वागत करेंगे और आपको इसमें पूरा समर्थन देंगे। आपने कहा, हम 24 घंटे बिजली देंगे। यह बहुत खुशी की बात है। आप 24 घंटे बिजली दीजिए,

हम पूरा समर्थन देंगे, हम स्वागत करेंगे। आपने कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। हम बहुत खुश हैं, हम पूरी तरह से इसमें आपको समर्थन देंगे और इसका स्वागत करेंगे। आपने कहा कि हम सब युवाओं को रोज़गार दे देंगे, यह बहुत अच्छा है। हम आपका समर्थन करेंगे और इसका स्वागत करेंगे और पेट्रोल, डीजल तथा गैस सब सस्ते हो जाएंगे। यूपीए सरकार के जमाने में दाम बहुत थे, तो हम सस्ते कर देंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे और इस पर आपको बड़ा समर्थन देंगे। मुझे लगता है कि यदि ये सारी बातें आ जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका पूरा स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे और पूरे खुश होंगे। ऐसा नहीं कि हम दु:खी विपक्ष रहेंगे, हम एक खुश विपक्ष रहेंगे, अगर ये सारी चीजें आप पूरी कर देंगे। हम देखेंगे और इसमें तो हम आपको पूरी शाबाशी देंगे। हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछते और अभी हमें पूछने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि शुरूआत में सब होता है और हमें पूछने का अधिकार ही नहीं है कि सरकार बनते ही डीजल पर 50 पैसे क्यों बढ़ गए। नहीं, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे और न पूछेंगे। हम आपसे यही भी नहीं पूछेंगे कि 15 दिनों में महंगाई में अभी तक कोई कमी क्यों नहीं आई है।

**श्री तपन कुमार सेन** : अब नया क्या हुआ?

**श्री राजीव शुक्ल** : वह पुरानी पॉलिसी थी, तो बदल लेना।

**श्री तपन कुमार सेन** : ये भी वह ही चलाएंगे।

**श्री राजीव शुक्ल** : हम अभी आपसे नहीं पूछेंगे कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई। हम आपसे यह भी नहीं पूछेंगे कि 10 घंटे का पॉवर कट अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी में है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। अभी हम यह भी नहीं पूछते हैं, बिल्कुल सवाल नहीं, इसमें कोई आरोप वगैरह भी नहीं है। हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपने कहा था - "हमारी सरकार आने दो एक हफ्ते के अंदर दाउद इब्राहिम भारत की जेल में होगा।" हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि एक हफ्ते में दाउद इब्राहिम लाए या नहीं लाए। हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्योंकि हम अभी आपको टाइम देंगे, ताकि आप वहां से आराम से लेकर आओ, इसलिए हम वह भी नहीं आपसे पूछ रहे हैं और न पूछेंगे कि आप उनको लेकर क्यों नहीं आए। जहां तक इस तरह के काम हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर सम्मानित नेता सदन ने कुछ बातें कही थीं, तो उसकी हम जरूर एक-दो चीज़ें सामने रख देना चाहते हैं। हमने जिस दिन सरकार छोड़ी उस दिन रुपया एक डॉलर के मुकाबले 58 रुपए 30 पैसे था। आज बढ़ गया है, 60 रुपए के करीब हो गया है। लेकिन हम वह भी नहीं पूछते। नहीं पूछेंगे क्योंकि हम अभी वक्त देना चाहते हैं, हम उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहते। जो सीएडी है, करंट एकाउंट डेफिसिएट, उसमें 60 परसेंट की कमी आई है। अगर आगे बढ़ता है तो हम अभी उस पर आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जब हमने छोड़ा तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का था, वह 312 बिलियन डॉलर पर हमने छोड़ा था। अगर आगे बढ़ता है तो हम आपको शाबाशी देंगे और अगर कम होता है तो अभी हम नहीं पूछेंगे। अभी 6 महीने, साल भर हम आपसे कोई सवाल नहीं कर

[श्री राजीव शुक्ल]

रहे हैं। जहां तक आप गंगा सफाई की बात कह रहे हैं, गंगा सफाई का अभियान हम सब के मन में है। राजीव गांधी जी ने इसकी शुरूआत की थी, आप उसको आगे बढ़ाइए। उमा भारती जी ने इसको एक एजेंडा के रूप में लिया था, जो बड़ी अच्छी बात है और उस समय मुझे याद है तीन साल पहले स्वयं उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे भाजपा के उत्तराखंड में जो मंत्री हैं वे सबसे बड़े दोषी हैं भाजपा के मंत्री वहां पर सबसे ज्यादा गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। उस समय वे बहुत नाराज थीं इस बात को लेकर।...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, she is not present in the House.

MR. CHAIRMAN: Fair enough.

SHRI RAJEEV SHUKLA: But I can always quote... ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: And he is attributing words to her. ...*(Interruptions)*... Can we hold her responsible? ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: No, she was on the record. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: No, I would like him to demonstrate the veracity of this comment. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Rajeevji, continue with your speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Please demonstrate the veracity where she has made this comment. ...*(Interruptions)*... Let us hear recording or a statement as to what she said. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Her statement is on record against one of the Ministers of the then Uttarakhand Government... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let us not enter into another controversy. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए, बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... राजीव जी, कंटीन्यू।...**(व्यवधान)**...

**श्री तरुण विजय** (उत्तराखंड) : सर, ...**(व्यवधान)**... उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Rajeevji, please continue. ...*(Interruptions)*...

**श्री राजीव शुक्ल** : मैं ऑन दि रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नाम भी ले दूं मंत्री जी का, जो उमा जी ने नाम लिया था। उमा जी का तो टेप चल रहा है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You know precious time is being lost in this. ...*(Interruptions)*...

**श्री पीयूष गोयल** : वह दूसरे सदन में हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री राजीव शुक्ल** : यू-ट्यूब पर चले जाओ, उमा भारती जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, पहले वह ही सुन लो। सर, प्रूव करने की बात करते हो, तो सदन में मैं टेप रख सकता हूं। इसलिए शांत बैठो। इसलिए हम छः महीने नहीं पूछेंगे।

MR. CHAIRMAN: Continue Rajeevji. Please continue.

**श्री राजीव शुक्ल** : मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप बिना वजह भिड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हम आपसे छः महीने तक नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए गंगा मैया की सफाई करो तो यमुना मैया की भी करो। आपको यमुना जी से क्यों ऐतराज है। यमुना जी को भी शामिल करो, यमुना में भी बड़ी गंदगी है। तो गंगा मैया के साथ यमुना मैया को भी इसमें शामिल करो। येचुरी जी ने कावेरी की बात कही थी। अगर दक्षिण भारत से आपको प्यार है, तो कावेरी की सफाई कर सको तो बहुत अच्छा है। लेकिन गंगा मैया के साथ यमुना मैया को क्यों छोड़ रहे हो, उनको भी लो साथ में। इसलिए मेरी मांग है कि इसमें यमुना मैया को भी शामिल करो। जो बात कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने कही थी कि भाषण में बहुत अच्छी बात कही गई, अल्पसंख्यकों के लिए कही गई, लेकिन अगर हम कुछ दें तो तुष्टिकरण की नीति है और आप बस लेटकर साष्टांग दण्डवत् हो जाओ, वसीम अकरम को मिठाई खिलाओ, इसमें सारे मदरसों को सुविधाएं दो, वह तुष्टिकरण नहीं है।

हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाएं, उनसे बात भी कर लें, तो नवाज* और आप बुलाएं तो नवाज शरीफ। तो ये दो मापदंड कैसे चल सकते हैं? मुझे याद है, ये बयान थे कि जब तक उनके 7 सिर कलम कर के न आ जाएं, तब तक पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की वार्ता तो दूर, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अब 7 सिर तो आए नहीं, हम उनके आशीर्वाद से, उनकी सरपरस्ती में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, हम उनकी शुभ-कामनाएं लेकर अपनी सरकार बना रहे हैं।...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। हम अगर पाकिस्तान की तरफ देखकर मुस्करा भी दें, तो यह एकदम गलत बात है और आप साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वह गलत नहीं है। ये आपके दोहरे मापदंड हैं, लेकिन हम अभी इस पर भी कुछ नहीं करेंगे। हम तो 6 महीने, साल भर भी इस की कोई आलोचना भी नहीं करने वाले हैं।

आपकी तमाम योजनाओं का ब्यौरा कल नेता विपक्ष ने दिया है और अगर सचमुच में उन तमाम योजनाओं को देखा जाए, तो वे तमाम योजनाएं यूपीए गवर्नमेंट की हैं। आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, चला रहे हो, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से दिया है - हस्तकौशल, कुशलता, हुनर, ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जिन के लिए 5 हजार करोड़ रुपए डा. मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने पहले से दिए हुए

---

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री राजीव शुक्ल]

हैं। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बन रहा है - दिल्ली मुंबई कॉरीडोर और कोलकता तक का कॉरीडोर पहले से चल रहा है, अब आप उसे बढ़ा रहे हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। "बेटी बचाओ अभियान" पहले से ही चल रहा है, यह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन और रूरल डेवलपमेंट मिशन को मिला दो, तो जो आपका अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वह बहुत अच्छा है और यह भी पहले से चल रहा है। इनके निर्मल ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन व शौचालय के प्रोग्राम्स आप आगे बढ़ा रहे हैं, हम इस से खुश हैं। ये सारी योजनाएं, जिन्हें आप आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर हम बहुत खुश हैं। इसलिए सभापति महोदय, हमें कोई आलोचना नहीं करनी है और न हम इनसे ये सब सवाल पूछ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे प्रोग्राम्स लागू करो। देश से बेरोजगारी एकदम खत्म हो जाए, महंगाई एकदम खत्म हो जाए, लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगे, भ्रष्टाचार का समूल नाश हो जाए, गरीबी देश से बिल्कुल खत्म होकर एक स्वर्णिम भारत बने, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इस का स्वागत करते हैं।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जी.एन. रतनपुरी** (जम्मू और कश्मीर) : चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट के दोनों एवानों से राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, यह विश लिस्ट लगती है जिस पर यकीन नहीं आता कि सही हो सकती है। यह इतनी लंबी विश लिस्ट है, लेकिन मैं खासतौर से उन बातों का जिक्र करूंगा कि इस में उन कंटेनशियस इश्यूज का कहीं जिक्र नहीं है, जो लोक सभा इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान हुक्मरान पार्टी ने वोट हासिल करने के लिए उठाए, जिनकी वजह से हमारा समाज कम्युनल लाइनों पर पोलराइज हो गया और इसे पुरानी सतह पर लाने में काफी टाइम लगेगा। अगर सच में यह ह्रदय परिवर्तन है कि उन इश्यूज का नई सरकार के पहले पॉलिसी स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं है, तो यह बहुत खुशी की बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि नारद मुनि फिर धरती पर आए हों, इन से मिले हों और यही ह्रदय परिवर्तन का सबब बना हो। लेकिन पोलराइजेशन बहुत संगीन हुआ है, जैसा कि सरदार पटेल जी ने आजादी के फौरन बाद कहा था कि यह कैसा खौफ है कि लोग खौफ के इज़हार से भी डरते हैं। देश में आज मुसलमानों की तकरीबन वही हालत है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि मुजफ्फरनगर के फसादात में जिन लोगों की तबाही हुई, उनसे वहां सेकुलर सरकार ने या रियासती सरकार ने लिखकर लिया कि वे अपने घर, अपने होम को वापस नहीं जाएंगे, उसके बाद ही वे क्वालिफाइ करेंगे, ताकि सरकारी मदद हासिल कर सकें।

जनाबे आला, मुझे खुशी इस बात की है कि इस सरकार ने सदरे जम्हूरिया के भाषण में कश्मीर का जिक्र किया और उस दौरान 370 का मसला नहीं उछाला, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ग़ालिबन पहले ही दिन ऐसा बड़ा तनाज़ा खड़ा कर लिया था कि वे गलतफहमियां दूर करने में भी काफी वक्त लगेगा। हम एक ऑप्टीमिस्टिक व्यू लेंगे, हम यकीन करेंगे कि यह सरकार सच में इलेक्शन का जो माहौल बना था, जिसमें बड़ी तलखियां

पैदा हुई थीं, उसको भुलाकर कर इन्क्ल्यूसिव सरकार देना चाहती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। हम इस पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक यकीनदहानी आनी चाहिए कि दफा 370 में यूनिलेटरली कोई भी तब्दीली नहीं होगी, कोई भी कोशिश नहीं होगी। जब तक यह नहीं होता, शक-ओ-शुबह दूर नहीं होंगे। रियासती सरकार ने और यूपीए सरकार ने पहले ही पंडितों की वापिसी के लिए कई स्कीमें बनाई हैं और कश्मीरी पंडितों का उनके हमसाए, उनके दोस्त, उनकी धरती, उनके घर और हमारे दिल बड़ी बेताबी में इंतजार कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों में, हमारे स्कूलों में, हमारे हमसायगी में, हमारे देहातों में उनकी कमी महसूस की जाती है और हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए रियासती सरकार की तरफ से और रियासती आवाम, जो वहां अक्सरियती तबका है, उनकी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हमें कहा जाएगा करने के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं।

सर, 1990 में जब मिलिटेन्सी शुरू हुई, तो क्या हालात थे? उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन यकीनी ऐसा माहौल था कि कश्मीरी पंडित, जो एक इंतिहाई मिनिसक्यूल माइनोरिटी थे, पांच फीसदी से भी कम, तकरीबन तीन फीसदी थे, वे इंतिहाई गैर-महफूज महसूस करने लगे और निकल आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 238 Kashmiri Pandits were killed और दूसरे वहां से निकल आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 हजार से ज्यादा कश्मीरियों की फैमिलीज, जिनमें मुसलमान भी हैं और जो रिलीफ कमिश्नर हैं, उनके पास 38119 फैमिलीज एज माइग्रेंट दर्ज हैं, जिनमें तीन हजार कश्मीरी मुसलमान फैमिलीज भी हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त पिछले बीस-बाइस साल से रहते हैं और वे सिमिलर सर्कमस्टांसेज़ में, ऐसे ही हालात में वहां से अपने घर छोड़कर आए थे। इसी तरह जम्मू के उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ, जहां डेढ़ हजार के करीब गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा लोगों ने घर नहीं छोड़े, वे वहां डटे रहे, मगर कोई चंद सौ फैमिलीज वहां से भी माइग्रेट होकर जम्मू और उधमपुर में आ बसी हैं, जो वहां बीस-बाइस साल से हैं। सरहदों में भी उन दिनों में ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि सरहदी देहात में खानदान के खानदान सरहद पार गए, एलओसी पार कर गए। ऐसे खानदानों की तादाद तीन हजार से ज्यादा है और तीस हजार लोग पाकिस्तानी मक़बूला कश्मीर में निहायत बदतर हालात में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो भी पैकेज बनता है, आप दें। ये सब डिस्प्लेस्ड लोग इज्जत के साथ और सलामती के साथ सिक्युरिटी और डिग्निटी की गारंटी के साथ अपने घरों को आने का हक रखते हैं।

जनाबे आला, जम्मू और कश्मीर एक सियासी इश्यू है, जिससे हम इंकार नहीं कर सकते। इस पर पिछले 1947 से ही बात हो रही है। यह बात हम भूल नहीं सकते कि रियासत-ए-जम्मू और कश्मीर का इलहाक़ स्पेशल सर्कमस्टांसेज़ में हुआ था, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क तकसीम हुआ था, लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम ने, वहां के मुसलमानों ने दो कौमी नजरिया मुस्तदे कर दिया और अपनी किस्मत भारत के साथ जोड़ दी। आज कुछ लोग इस इलहाक़ में जम्मू और कश्मीर की आवाम का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको निगलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि महाराजा ने दस्तावेज इलहाक़ पर दस्तख्त कर दिए और बस। लेकिन अगर सिर्फ दस्तावेज़ इलहाक़ से बात चलती, तो शायद हैदराबाद और जूनागढ़

[श्री जी.एन. रतनपुरी]

आज भारत का हिस्सा नहीं होते। बात अवाम की थी, इस इलहाक़ को शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की कयादत में अवामी ताईद हासिल थी और जम्मू और कश्मीर के अवाम ने इस रिश्ते को इतनी बरसों में निहायत साबितक़दमी के साथ तहफ्फुज़ किया है। 1947 में अपने गैर-मुस्लिम भाइयों को तहफ्फुज़ फराहम किया, हालांकि बदकिस्मती से वैसे हालात जम्मू में नहीं रहे। जम्मू में मॉब वॉयलेंस में हज़ारों मुसलमान मारे गए। दस्तावेज़े इलहाक़ जो जम्मू और कश्मीर का हुआ था, वह बाकी रियासतों की तरह नहीं था, इसीलिए एक खुसूसी दर्जा दफा 370 के तहत यह एक आईने ज़मानत थी। हमारी रियासत के उस वक्त के जो नेता थे, उन्होंने चाहा था कि यह मुस्तकिल बने, लेकिन मुस्तकिल नहीं बनी, लेकिन इसमें ऐसे तहफ्फुज़ात हैं कि रियासती आवाम की मर्ज़ी के बगैर इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर आप सच में यूनिटी चाहते हैं, तो आप कभी इसका ख्याल भी मत लाइए कि आप यूनिलेट्रली इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त जयराम रमेश जी ने कहा है, अगर आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, तो पता नहीं फिर मुल्क का क्या हाल होगा? आप कितने महाज़ खड़े करेंगे और फिर कितने संभाल पाएंगे, यह वक्त ही बता सकता है।

सर, हम मफाहमत में यक़ीन रखते हैं और चाहते हैं कि मफाहमत के साथ सारे मसले हल हों। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कश्मीर का मसला इंसानियत के दायरे में हल करेंगे, कोई कैद नहीं होगी आईने हिन्द की, इससे बाहर भी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी स्पिरिट के साथ आप वे धागे उठाएंगे जहां वाजपेयी जी ने छोड़े थे। जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने दफा 370 को एब्रोगेट करने का प्रोसेस शुरू होने का बयान दिया, तो मुझे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से एसएमएस और टेलिफोन कॉल्स मिले, स्टूडेंट्स की तरफ से, जो जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स इस वक्त हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क में हैं और कुछ जर्नलिस्ट भी हैं। तो वे हंस रहे थे और कह रहे थे कि यहां सब लोग हमसे पूछते हैं कि डल लेक के इर्द-गिर्द ज़मीन के भाव क्या हैं?

**श्री सभापति** : अब आप खत्म करें।

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : दफा 370 में जो दिलचस्पी है एब्रोगेट करने की, यह सिर्फ इस बात तक महदूद है कि डल के किनारे पर एक मकान हो, एक रेस्ट-हाउस हो, तो इस ख्याल को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको डल में रहना है तो अंग्रेज़ों की तरह हाउस-बोट भी बना सकते हैं, जिसके लिए दफा 370 हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट में, उसकी तरक्की में कहते हैं कि यह कोई रुकावट बन रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। दफा 370 कोई रुकावट नहीं बना। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए ज़मीन हासिल करने में कोई पाबंदी नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : जनाबे आला, मैं चन्द मिनट और लूंगा। हमें यह मौका बार-बार नहीं मिलता है।

**श्री सभापति** : वक्त की कमी है।

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : अगर आप चाहते हैं कि अमन हो, तो अमन के लिए मफाहमत ज़रूरी है और मफाहमत के लिए अमन। दोनों के लिए यह ज़रूरी है कि इंसाफ यक़ीनी बनाया जाए और इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि हम सच कबूल करें, सच से मुंह न फेरें, सच जानने की कोशिश करें। जम्मू और कश्मीर और मरकज़ी सरकार के दरमियान दस्तावेज़े इलहाक़ से लेकर आज तक कई मुआहिदे हुए हैं, लेकिन उनमें हमेशा एकतरफा तौर पर मरकज़ ने तब्दीली की और उनको अंडरमाइन करने की हमेशा कोशिश की।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : हमें जम्मू और कश्मीर के अवाम को यक़ीन दिलाना होगा कि हमारे रिश्तों में यूनिलेट्रली ताकत की बुनियाद पर, क्योंकि एक जो फरीक़ है, वह कमज़ोर है, दूसरा ताकतवर है, उसमें ताकत के बल पर कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर इन रिश्तों पर बातचीत की जाएगी, तो मफाहमत के तौर पर। आज मुझे यक़ीन है कि इन ट्रेज़री बैंचों पर वे लोग बैठे हैं ...(**समय की घंटी**)... जिन्होंने मसले कश्मीर के हल को कहा कि यह हल सिर्फ इसलिए हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर का डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज किया जाए। मुसलमानों की अक्सरियत को अकल्लियत में तब्दील किया जाए लेकिन इन बैंचों में वे लोग भी शामिल हैं, जो...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : जो आज बैठे हैं और चाहते हैं कि जेनुइनली कश्मीर का मसला हल हो। वहां की अवाम कौमी धारे में सच्चे तौर पर शामिल हो और मुझसे कहा जाता है कि आप सजेस्ट कीजिए कि क्या किया जाए, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर में एक नई शुरुआत हो, लोगों को हुकूमत का भरोसा हो।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : जनाब-ए-आली, बस मैं एक मिनट और लूंगा।

**श्री सभापति** : नहीं, अब नहीं। बस अब आप खत्म कीजिए। आपका वक्त पूरा हो चुका है।

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : हमारा वक्त तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। थोड़ा सा वक्त आज दे दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत की शुरुआत की थी, जम्मू और कश्मीर के जो इक्तसादी मसाइल हैं, उनके बारे में एक फॉर्मल बातचीत शुरू हुई थी, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लैवल पर हुई थी, जिसमें हाइडल प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने का मामला था, लेकिन वह बात...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, we have no time. Please use another occasion.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : इस तरह वर्किंग ग्रुप्स बने थे। उनकी सिफारिशात आपके पास हैं। आप कहीं से शुरुआत कीजिए। बात करने के बजाय कुछ डिलीवर कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please cooperate. ...*(Time-bell rings)*...

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : आप डिलीवर करने से शुरू कीजिए, बातों में उलझाए रखने के बजाए यकीन दीजिए कि आप कुछ देने में यकीन रखते हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Ratanpuri, please cooperate.

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : जनाब मैं आधे मिनट में कनक्लूड करूंगा।

**श्री सभापति** : बस, अब समाप्त कीजिए, प्लीज़।

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यह सरकार वाकई कुछ करना चाहती है, जो कुछ इसके बस में है, जिसमें कोई कान्सेंसस की जरूरत है, जो कोई कॉन्टेंशियस ईशूज़ नहीं हैं, इंटर रीजनल कनेक्टिविटी की बात सदर-ए-जम्हूरिया ने अपने भाषण में की है।

MR. CHAIRMAN: No, no. You cannot go on to a larger debate. Please conclude now. ...*(Interruptions)*... Your time is over. I will call the next speaker. ...*(Interruptions)*...

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हमारी सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। एक पैकेज सड़कों की हालत बेहतर करने के लिए मरकज़ी सरकार दे दे। इंडस वॉटर ट्रीटी के जो नुकसानात हुए हैं, जो 95.4 परसेंट हमारा पानी आपने पाकिस्तान को दिया था, उसकी तलाफी कीजिए...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Next is Shri Satyanarayan Jatiya. ...*(Interruptions)*... Please conclude now. ...*(Time-bell rings)*...

**श्री जी.एन. रतनपुरी** : इसी तरह जो हाइडल प्रोजेक्ट एनएचपीसी के साथ हैं, जितना उन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया है, उससे कहीं ज्यादा वापस लिया है। वह ट्रांसफर करने की बात कीजिए। शुक्रिया।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mr. Jatiya is not here. Now, Shri V.P. Singh Badnore.

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, I rise to thank the hon. President of India for the Address and I support the Motion of Thanks moved by my colleague, Naqvi sahib, and, seconded by Nadda ji.

Hon. President's Address to both the Houses outlines the blueprint of hope and aspirations of the people in general of development through good governance. It is no exaggeration when I say that the elections of 2014 were looked upon by the whole world, and, with a sort of interest developed in all the countries, they were looking at our country and they were watching with interest as to what the results were going to be. It was just amazing that the whole world focused on the elections and the results.

A Party with a history of 125 years, a Party who claimed that they got the country Independence, a Party which boasts of their dynastic roots, which thought that they were invincible, was totally routed.

SHRI SHANTARAM NAIK: I object to the word 'claim'. It is a reality. ...*(Interruptions)*...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: It is okay. Claim is claim. And the arithmetic is that they were decimated; you cannot go wrong on that. But the irony of the whole thing is that the Leader of the Opposition while making a speech yesterday, and it is really unbelievable that instead of the introspection that he and his Party should be doing, was trumpeting the achievements of the UPA Government. I do not know when the realization will dawn on him and his Party, the Congress Party, and, he will stop basking in the glory of having done so much.

Sir, the results have been shameful for them. The LoP said that the UPA Government leaped forward in electricity and the energy sectors. Does he know that the position is dismal even in the Capital of our country? Does he know that after 67 years of independence, we do not have electricity in all the villages? Sixty-seven years and we do not have electricity in the villages. He was talking about the Rajiv Gandhi Grameen Yojna. They may have put together the infrastructure but most of the villages do not get electricity more than eight hours a day. Is it not a shame? Does he know that the World Energy Report of last year talking about installed capacity per million people says that USA has 2826 megawatt, EU has 1733 megawatt and India has a dismal record of 130 megawatt, with over ten crore people still in this country which do not have access to electricity? Does he know that thousands of crores of rupees have been spent on the Bawana Gas Power Plant exclusively for Delhi and it is lying idle for so many years? There is no gas and that is the reason that Delhi today has no electricity. The Bawana plant has 1500 megawatt capacity. Why could you not give them gas? If you knew that there was no gas, why did you spend so much money on it? It is lying vacant now. The UPA Government trumpeted their Ultra Mega Power Projects. The scheme was started in 2005 and after ten years, although it was a good scheme, out of the nine projects, only two projects, Sasan and Mundra, have come about and have been synchronised. But we had not been able to get full electricity from them and it is not commissioned. Sir, the Ultra Mega Power Projects should have been there and there would have been 45,000-50,000 megawatt capacity. They are of super critical technology but where and why and how did you go wrong? And when you have trumpeted and said that it was such a great scheme, have you really

[Shri V.P. Singh Badnore]

introspected, have you really thought what is the reason that they have not come about? Does he know that the private sector has not invested in this sector for the simple reason that there is no escrow account? That is the reason that most of the private investors are not coming in this sector. Does he not know that the SEBs have been given a bail-out programme 2-3 times, and every time they do that, the same thing happens — the SEBs go into the red? Recently also, one-lakh-crore bail-out programme was given to them and I think it could be repeated. Does he know that these subventions have never been fully paid by the Government to the SEBs? That is the reason that the SEBs are in the red. And it is because many projects have not taken off and the NPAs are rising in the banks that the banks have stopped giving loans to power projects. This is one of the big reasons why the private investors are not coming into this field.

MR. CHAIRMAN: I am afraid your party time is over and it has gone into minus.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Thank you very much, Sir.

In the end, I will just say that there are regulators in this field. The CERC and SERCs need to be really re-modeled so that they are more transparent and they do more regulations than what they are doing today. Thank you very much.

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (गुजरात) : सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा इस हाउस में बोलने का यह पहला मौका है। वैसे सुबह से मैं इस मौके की तलाश में था कि मुझे यह मौका मिले। मैं वाकई दो दिन से इसकी तलाश में हूं। सर, मैं प्रेजीडेंट के भाषण के ऊपर अपने कई मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा पहला प्वाइंट यह है, हालांकि अभिभाषण में ऐसा कहा गया है कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और जो लोग इलेक्शन के दौरान मारे गए हैं, उनके प्रति तथा उनकी फेमिली के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। जो इलेक्शन conduct हुआ है, मैंने इस इलेक्शन में बहुत सारी shortcomings देखी हैं। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि मैं तीन लोक सभा इलेक्शन लड़ चुका हूं, जिनमें से दो जीता और एक हारा हूं। इस बार मुझे प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और मैंने यह चुनाव लड़ा। लोग मानते थे कि मेरी डिपॉजिट चली जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। लोग यह भी मानते थे कि वे पूरा नेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे, वह भी नहीं बना। ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर केंडिडेट थे और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे, ये दोनों चीज़ों पर successful नहीं हुए।

सर, मैंने तीन इलेक्शन्स में ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार मैंने यह देखा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो lacuna है, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर का key role है। The Returning Officer was highly biased. I found he was not independent at all.

MR. CHAIRMAN: Would it be appropriate to comment on the Election Commission here?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I said it. But I will have to do it because this is the only House where we will have to draw the attention...*(Interruptions)*... This is a written complaint. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is preferable to exercise restraint. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not accusing...*(Interruptions)*... I am just saying something about the conduct of elections in the entire country. It is a very important constitutional institution. In fact, we have to express our views if it is going wrong. I found that it was literally wrong in that sense. You look at the way elections are conducted. You take the machinery from the State. The State machinery is a key, in fact, in conducting elections. When somebody who is there for 15 साल से 20 साल से जब कोई एक सरकार वहां पर रहती है और पूरी मशीनरी उसके influence में जब आ जाती है और दो महीने के लिए that entire machinery is transferred under the Election Commission, तो उसका impartial रहना बड़ा मुश्किल होता दिखाई दिया है और वह भी जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक केंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हों और वे तो प्राइम मिनिस्टर केंडिडेट भी थे।...**(व्यवधान)**...

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** (उत्तर प्रदेश) : सर, ...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, it is my maiden speech and I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: He is not conceding, Naqvi sahib.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, this is my maiden speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Mr. Mistry, one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I will not yield. ...*(Interruptions)*...

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : आज चुनाव आयोग को पूरा देश सराह रहा है...**(व्यवधान)**... पूरे देश ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्ष चुनाव कराया है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Naqvi sahib, please sit down. ...*(Interruptions)*... He is not conceding. ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: They have no right to intervene....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He is not conceding. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, they have no right to intervene. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, this should not go on record. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, allow the debate to continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, it should not go on record. ...*(Interruptions)*... That's it. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, it should not go on record. ...*(Interruptions)*...

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : ये चुनाव आयोग पर...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, it is only you who can instruct me not they. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

Please sit down. आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... Please continue.

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं...**(व्यवधान)**... आप चुनाव हारे हैं, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : मेहरबानी करके आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... जो मैंने महसूस किया...**(व्यवधान)**... जो मैंने खबरों में देखा...**(व्यवधान)**... वह मैं कहता हूं...**(व्यवधान)**... इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के अंदर ...**(व्यवधान)**...

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : सभापति जी...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... देखिए, आप जितना समय इसमें ले रहे हैं, उसका आपकी बारी पर असर पड़ेगा...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am not making an allegation. I am simply giving whatever has transpired on me. Sir, with the RO, two criminal cases were filed. In fact, I received three notices in that. So, I have seen the entire machinery. ...*(Interruptions)*... Please sit down. Don't disturb me. It is none of your business to disturb. ...*(Interruptions)*... Let the Chair do it. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... This is my maiden speech. ...*(Interruptions)*... You have no right to intervene.

MR. CHAIRMAN: One minute, Mr. Mistry. I think there is an established procedure about these matters. If something has to be said about a constitutional authority, there is a procedure for it. The Election Commission is an institution of the State. If there is a valid point to be made, please do it through appropriate process. Nobody would interfere with your right.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am not making any allegation on them. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no, but, it would amount to that. What you are saying amounts to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am simply stating the conduct. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, it is rule 238(5).

MR. CHAIRMAN: I am aware of it. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I think, he is not mentioning about any person in general and it is not an individual or any person who is in high authority.

MR. CHAIRMAN: Institution in higher authority is always covered. ...*(Interruptions)*... देखिए, आप अपनी बात कह चुके हैं...**(व्यवधान)**... आप अपनी स्पीच कंटीन्यू कीजिए...**(व्यवधान)**... Please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, how do we speak when these people don't have tolerance to listen? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please continue with your speech.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, the point I am making is this and I am making a very valid point in the sense that in the conduct of elections, I feel that the Government machinery should be transferred from one State to another State in order to give a chance for fair election. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It requires an institutional review.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, the second thing is the ugly face which I saw for the first time is this. मैं तो इसकी सिलेक्शन के अंदर था। मैंने जो देखा है, वह यह है कि अभी तक जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट हाउसेज वगैरह थे, वे सब पार्टियों को चंदा देते थे, लेकिन इस बार पूरा माहौल ऐसा बना जिसके अंदर पार्टी को छोड़कर पर्सन में इन्वेस्टमेंट हुआ। पूरे इलेक्शन का खर्चा, मीडिया के अंदर जिस तरह से एडवरटाइजमेंट वगैरह

[Shri Madhusudan Mistry]

**3.00 P.M.**

दी गई, it is casting a very sad picture or a very sad scenario for the future. The corporate houses will be controlling the entire electoral process in due course if the Election Commission is not equipped to control the money which is being spent in the election. हमने पार्टी के ऊपर ऐसा कभी नहीं देखा। अगर मीडिया के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर, किसी भी चैनल के अंदर किसी भी चीज़ के स्लॉट खरीदे जाएं, उसके अंदर एडवरटाइजमेंट खरीदी जाए, पूरे देश के न्यूज पेपर्स के अंदर फ्रंट पेज पर एडवरटाइजमेंट दी जाए, तो सवाल यह आता है...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One minute, everyone. This is a discussion on the Address of the hon. President of India. ...*(Interruptions)*... Let us confine ourselves to that. ...*(Interruptions)*... I know that. ...*(Interruptions)*... I am aware of it. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not out of the purview of the Address. I am very much in this. ...*(Interruptions)*... I am just sharing my experience for future. मीटिंगों के लिए, पूरे कैम्पेन के लिए, कॉरपोरेट लोग और अन्य लोग, जो जहां कहीं से भी इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस बार का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैटर्न दिखाई दिए हैं, वे हिंदुस्तान के आज तक के किसी भी इलेक्शन में दिखाई नहीं दिए हैं।

[**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए।]

सिर्फ एक आदमी के अंदर वह इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिसका रिवार्ड आप ले रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, देखते जाइए कि सब औद्योगिक घर, सब कॉरपोरेट आपसे मांगेंगे। मेरा दूसरा प्वाइंट है।...**(व्यवधान)**... Mr. Deputy Chairman, Sir, will you listen to me please? सर, मेरा दूसरा मुद्दा है, जिसे यहां पर मिश्रा साहब ने, if I am not wrong, उठाया था, जो यहां पर पैराग्राफ नं. 4 के अंदर बताया गया है। यह गुजरात मॉडल के बारे में है। यह गुजरात मॉडल क्या है, वह तो बताओ। मैं आपको बता रहा हूं। मैंने गुजरात मॉडल को बहुत नजदीक से देखा है, हम उसके विक्टिम भी हैं। विक्टिम नहीं हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, अगर कोई भी हों, तो मेहरबानी करके वह मॉडल यहां पर इम्प्लिमेंट न हो। सर, वह मॉडल क्या है? गुजरात के उस मॉडल के अन्दर चीफ मिनिस्टर के अन्दर सभी अथॉरिटीज़ वेस्ट हुई हैं। उसके अलावा कोई निर्णय नहीं कर सकता है। यानी अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, उस वक्त जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वे अभी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उन्होंने आपको एक बार कह दिया कि आप जाइए, आप अपना काम शुरू करिए, आपका प्रोजेक्ट है, तो कोई भी मशीनरी कोई भी ऑब्जेक्शन लेकर उसको मना नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि चिन्ता मत करिए, शायद पूरी कैबिनेट वक्त आने पर पूरी रबड़ स्टाम्प न हो जाए। Let me tell you, you will have no voice, whatsoever, before the Prime Minister.

सर, दूसरी बात यह हुई कि पूरा कंसेंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ एक व्यक्ति में हो गया। जैसा अभी मेरे मित्र जयराम रमेश जी और हमारे लीडर बोल रहे थे, They were casting aspersions, but that is not so. It is going to be true in this country because entire powers will be vested only in the Prime Minister and the PMO. सर, पीएमओ को स्ट्रेंग्थेन करने की जो बात आई है, मैं आपको बताऊं कि वह इसलिए आई है, क्योंकि गुजरात के उस मॉडल के अन्दर जब चीफ मिनिस्टर कुछ तय करता है, तो उसके बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकता। यहां पर इतनी सारी मशीनरी है, इतने सारे लोग हैं। उनके अन्दर इंडस्ट्रियलिस्ट्स या कॉरपोरेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स डिलेड न हों और उनको सीधे पीएमओ से ही परमिशन मिले, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उसके सामने कुछ न कह सके, ब्यूरोक्रेट्स सीधे पीएमओ के साथ डीलिंग करें। सर, आपने अभी इसका परिणाम देखा कि एक हफ्ते पहले सभी सेक्रेटरीज़ की मीटिंग बुलाई गई और उनसे कहा गया कि आप सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, आपको कैबिनेट मिनिस्टर की कुछ भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसका रेपिटिशन इसलिए हो रहा है कि जिन्होंने इस इलेक्शन के अन्दर पैसे इंवेस्ट किए हैं और जो इस देश के नेचुरल रिसॉर्सेज़ के ऊपर, फाइनेंशियल रिसॉर्सेज़ के ऊपर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उनको पूरी सहूलियत हो। इस वजह से बात आई थी कि हर स्टेट में पीएमओ का ऑफिस होगा। आप तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर आप पीएमओ को स्टेट के अन्दर क्यों ले जा रहे हैं? आपको पीएमओ को वहां ले जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वहां पीएमओ एफिशिएंसी के लिए नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि वहां पीएमओ इसलिए ले जाया जाएगा कि जिन लोगों ने अपने पैसे इंवेस्ट किए हैं, उनको उनका रिवार्ड वापस मिले, उनकी इंडस्ट्री डाली जाए। सर, क्या होगा? मेरे स्टेट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हजारों एकड़ जमीन एक रुपए मीटर पर दी गई। मेरे स्टेट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 0.01 परसेंट पर 20 साल तक एक कार का कारखाना डालने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया गया और 20 साल के बाद उसका भुगतान करने के लिए उसको समय दिया गया। सर, पोर्ट्स दिए जाएंगे। यह यहां पर गुजरात का रेपिटिशन होगा।

सर, एक बात और है। मेरे यहां बड़े पैमाने पर एसईजेड खोले गए - स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी को हजारों एकड़ जमीन दी गई कि आप इसके अंदर एसईजेड खोलिए। सर, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन, जिसके सामने आज भी किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, आज भी वहां की सरकार को 2-3 सड़क के एनाउंसमेंट्स वापस खींचने पड़े।...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए न, भाई साहब, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मिश्रा साहब आपको एडवाइज़ दे रहे हैं, ज़रा आप उनको भी सुन लीजिए। मिश्रा साहब का मैं आदर करता हूं।...**(व्यवधान)**... आप सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

सर, किसान is at the receiving end, उस गुजरात मॉडल के अंदर...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No time now, please.

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, उस गुजरात मॉडल में किसान रिसीविंग एंड पर हैं।

सर, मैं यह भी बता दूं, जरा इनको सुनने में इन्टॉलरेंस होगा, वहां पर फोन टेपिंग होगी। पावर ऑपरेशन में स्टिंग ऑपरेशन होंगे। हमारे पीएम जब सीएम थे, तो बोलते थे कि जो गुजरात

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

के अंदर आतंकवाद फैलाएंगे, उनको मैं चुन-चुन कर मारूंगा। सर, चुन-चुन कर मारने का प्रोसेस गुजरात में हुआ, लेकिन फेक एंकाउंटर हुए। सर, ये गुजरात का वह मॉडल है, जिसमें होम मिनिस्टर तीन महीने जेल में रह कर आए हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा** (हिमाचल प्रदेश) : ऑब्जेक्शन, सर, ऑब्जेक्शन, सर।...**(व्यवधान)**... ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं?

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : यहां पर ये गुजरात को डिस्कस कर रहे हैं या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को?

**श्री जगत प्रकाश नड्डा** : इनके घाव अभी हरे हैं। शायद चोट गहरी लगी है।

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : यह 'चुन-चुन कर' शब्द सही नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the President's Address. ...*(Interruptions)*...

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? Why are they getting upset? This is a fact which I am talking about. ...*(Interruptions)*... I don't understand why they are not having tolerance. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the President's Address. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, you control them. I need your protection. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If all of you speak, what can I do? Let anyone of you speak. ...*(Interruptions)*... Okay, one of you stand up and say. I am ready to listen to you. One of you stand up and say what your problem is. ...*(Interruptions)*... If all of you speak, I cannot hear you. ...*(Interruptions)*... Now, what is your problem?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, he has used the words "चुन-चुन कर मारेंगे". This sentence, which has been made, should be expunged. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the record. If the words 'चुन-चुन कर' is unparliamentary, then, I will expunge it. I will look into it.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, let me tell you something. These people may not know it. They have no idea about it. Everybody talks about the Gujarat model. They have their perception of seeing it and we have our own perception of seeing

what the Gujarat model is. So, why are they disputing it? Please have patience. Kindly listen to us. You should have tolerance since you are in the Ruling Party.

सर, यह गवर्नेंस का ऐसा मॉडल है, जिसमें आज 30 से ज्यादा आईपीएस और दूसरे ऑफिसर्स जेल में हैं। आज भी वे जेल में हैं, वे बाहर नहीं निकले हैं। वे फेक एंकाउंटर के केस में अंदर हैं। सरकार ने कुछ नहीं कहा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mistry, you have taken 16 minutes. You take another four minutes more.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: This is my maiden speech. But I am not using that right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For maiden speeches, the outer limit is twenty minutes.

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, गुजरात मॉडल की यह स्थिति है कि वहां पर 'Use and Throw' policy है, आप उपयोग करिए और फेंक दीजिए। उनमें ये लोग भी शामिल हैं। आप अपनी जाति को सलामत मत मानिए, पांच साल ही हैं। आपके लिए भी 'No repeat' का एरिया आएगा। आप चिन्ता मत करिए। गुजरात में यही हुआ है, आप किसी से भी जा कर पूछ लीजिए। गुजरात के अंदर जितने भी सीनियर आदमी थे, आज नहीं हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, आज नहीं हैं। इस मॉडल के अंदर ये हालात हैं।

सर, यह मॉडल ऐसा है, हमारे यहां साबरमती के अंदर रिवर फ्रंट बनाया गया, उसका ज्यादा नहीं, 25% काम पूरा हुआ है, लेकिन उस 25% काम को 'इंडिया के सिंगापुर' के नज़रिए से बताया जा रहा है। हमारे यहां साबरमती नदी सुभाष ब्रिज से आगे अभी भी वैसी ही है, उतनी ही गन्दी है, उसके अंदर कुछ सुधार नहीं हुआ है। दस-बारह किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, सिर्फ उसके अंदर रिवर फ्रंट बना है। उस रिवर फ्रंट को आज गंगा नदी के किनारे ले जाने की बातचीत चल रही है। न जाने कब और कितने सालों के अंदर यह पूरा होगा।

**श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल** (गुजरात) : मिस्त्री जी, आप थोड़ा तो सच बोलिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, यह वह मॉडल है...**(व्यवधान)**... यह वह मॉडल है कि जिसमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर दावे किए गए थे कि 1,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आएगा। एक करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। यह 2003 से शुरू हुआ था। 2012 तक हमारे आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के दायरे के अंदर वह किया गया था। सर, एक करोड़ लोगों में से साढ़े पांच लाख लोगों को ही नौकरी मिली है। आज भी गुजरात के अंदर इम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 9 लाख लोग एजुकेटेड अनइम्प्लॉयड हैं। वे कम नहीं हो रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... आज यह स्थिति है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, गुजरात में पानी का नेशनलाइजेशन हुआ है।...(**समय की घंटी**)... आप वहां जमीन में कुआं नहीं खोद सकते। अगर आपको अपनी जमीन में कुआं खोदना है तो आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे। आप वहां लाइट नहीं ले जा सकते, आप वहां पानी नहीं निकाल सकते, यह ऐसा मॉडल है। मैं आशा करता हूं कि इस मॉडल का यहां पर या कहीं और उपयोग नहीं होगा। सर, इस मॉडल के अंदर और क्या है? In social indicators, we are way behind when compared to all other Stats, even Bihar and Jharkhand! Sir, take health, education, agriculture, malnutrition, we are far behind in all. Even on the investment front the Gujarat Government tries to prove that it is number one. We are not number one; it is Odisha which is number one. It is not we. इन्वेस्टमेंट की जो बात आज पूरे देश के अंदर चलाई जा रही है, उस मॉडल का एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistryji, please conclude. Please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sorry, Sir. My party has time. My party people are not asking me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has a number of names also.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I know, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has a half-a-dozen names.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I know it. Please; I am finishing it. Please hold on a minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are so many names in the list. You give number of names. What can I do? Either you withdraw the names or...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we are not withdrawing the names.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, Mr. Mistry, please conclude.

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, इसके अंदर करप्शन को कर्ब करने की बात कही गयी है, करप्शन को weed out करने की बात नहीं कही गयी है। आप करप्शन को बिल्कुल हटा देंगे, यह बात इसके अंदर नहीं कही गई है। सर, पंचायत के रोड्स वगैरह सब बनाने की बात इसमें की गई है। हमारी स्टेट में 2005-2006 में फाइनांस कमिशन की रिकमेंडेशन पर जो रिसोर्सेज़ स्टेट को डिवॉल्व करने थे, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, वे पैसे उनको डिवॉल्व नहीं किए गए, वे पैसे उनको नहीं दिए गए और as a result इससे वहां कितना इम्प्लायमेंट हुआ होगा, वह पता नहीं।

सर, मैं अपनी बात येचुरी जी की बात से जोड़ना चाहता हूं। Please give me three minutes, not more than that. एग्रीकल्चरल लेबर में, फॉरेस्ट लेबर में जो किसान जंगल की जमीन सालों

से जोतते आ रहे हैं, इस अभिभाषण में उनको जमीन देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और उनका जिक्र तक नहीं है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सर, अंत में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो मैं क्लीनिंग ऑफ गंगा के बारे में कहना चाहता हूं। सर, मैंने प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध वडोदरा से चुनाव लड़ा। मैं बहुत अरसे के बाद वडोदरा गया था। हमारे यहां पार्टी के सारे लोग बोल रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, जब वे वहां से कंडीडेट थे, तो वहां पर जो विश्वामित्री नाम की एक नदी है, उस वक्त उस नदी को क्लीन करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वह विश्वामित्री नदी आज तक कभी क्लीन नहीं हुई और न ही साबरमती क्लीन हुई। मैं आपके माध्यम से पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ज़रा प्रधानमंत्री जी को ध्यान दिलाइए कि आपने वडोदरा की सीट जरूर छोड़ दी और आप वाराणसी चले गए।...**(व्यवधान)**...

**श्री तरुण विजय** : साबरमती नदी तो हरी-भरी हो गई है।...**(व्यवधान)**... आप उसे देख नहीं पाते।...**(व्यवधान)**... सारी दुनिया में उसकी चर्चा हुई है।...**(व्यवधान)**...

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : आपको क्या कहना है?...**(व्यवधान)**... आप बैठिए...**(व्यवधान)**... आपको क्या दिक्कत है?...**(व्यवधान)**... आप क्यों ज़रा-ज़रा सी बात पर उछल-उछल कर खड़े हो जाते हैं?...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun Vijay, we are short of time ...*(Interruptions)*... Mr. Mistry, don't look at them. ...*(Interruptions)*...

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : सर, मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को ध्यान दिलाइए कि साबरमती नदी और विश्वामित्री नदी को भी बिल्कुल साफ करवाएं। यदि वडोदरा में यह काम किया गया, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी।

सर, मैं लास्ट प्वाइंट यह कहना चाहता हूं कि नक़वी साहब ने धर्म निरपेक्षता की बहुत बात की। उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत डिफेंड करने का प्रयत्न किया। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि जरा प्रधानमंत्री जी को आपकी टोपी पहना दीजिए। उन्होंने आज तक नहीं पहनी, वे मस्जिद में कभी नहीं गए। 2002 तक वे कभी मरने वालों के घर पर आश्वासन देने के लिए नहीं गए। आप उनको अपनी टोपी पहनाइए, इससे हमें बहुत खुशी होगी। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, unless each Member adheres to five minutes or a maximum of seven minutes, we can't finish the discussion. I know, 'others' have time, the Congress party is left with more than one hour but it has six speakers. Everybody may please stick to five-seven minutes. Then only can we finish it by 5 p.m. That is my request. I will be very strict and after the seventh minute I would say, 'nothing would go on record'. I have to follow this uniformly. Now, Shri Rajeev Chandrasekhar.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Jharkhand): You should not be that strict. We are here to discuss the President's Address. You can't dictate like this. I am sorry to say this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry. If you feel that I have dictated terms, I withdraw the words.

SHRI PREM CHAND GUPTA: More parties and individual Members should be given due time. Let me be very clear.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will explain it to you. ...*(Interruptions)*... Please cooperate with me. Maitreyanji, please. I will explain. ...*(Interruptions)*...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Let me put it before you. Before we could speak, you direct us that we can't speak for more than five minutes! Then what is the use? ...*(Interruptions)*... You can delete my name if you are going to do like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you ready to listen to me now?

SHRI PREM CHAND GUPTA: No, no; what do I listen? I have been listening to you for so many years now. ...*(Interruptions)*... This should not be done. If you feel you are going to interrupt me, please delete my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Guptaji, now please listen. I have not curtailed anybody's time. I will explain that. In 'others' category, there are 13 names remaining. If you divide the total time available, one Member can get only five or six minutes. I said seven minutes! Keep that in mind. Otherwise, only five to six minutes' time is due. I said seven minutes! But, for Congress, the available time is 1 hour 10 minutes time. There are six Members. Each Member would get 20 minutes. I have reduced their time with the consent of the Congress. I am told that their time could be reduced. They would be affected by this. Then I said, seven minutes. In 'others' category, nobody is affected. In fact, from the Congress kitty, Members from 'others' category are getting two more minutes, as I said earlier. You are speaking without understanding. ...*(Interruptions)*... No, I have explained; no discussion on that. It is my ruling. Please sit down. ...*(Interruptions)*... I have not taken away a single minute from 'others' category. I am giving more time. I am more than fair. So, without understanding, you are alleging. I have reduced the time of the Congress only after they gave their consent. They said that their Members would speak for five-seven minutes. For others, I have not reduced the time; in fact, I have increased. The BJP has already taken more time. For others, I have given more time. Seven minutes means more than your requirement. Now, Shri Rajeev Chandrasekhar.

SHRI K.C. TYAGI: Sir, he is a senior Member of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have said that I would withdraw if I have used the word 'dictate'. I said I would withdraw. We are friends, I have nothing against them. I have already explained the position.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, out of 12 Members in the 'Others' Category, how many have already spoken?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will find out. I will come back to you, and tell you.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, would l get two extra minutes for making me stand here for two minutes?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take a maximum of seven minutes.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to support the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, let me say, at the outset, that I too, like millions who voted this Government in, am deeply enthused about the prospects of a transformation of our country's governance and politics, and make no bones about either my optimism or high expectations from this Government over the next 60 months.

Sir, even the most generous amongst us will admit to the country facing serious and challenging times — a headwind selfcreated by many years of profligacy, poor governance and brazen corruption.

The tasks, therefore, for this Government are neither easy nor simple. The problems can't be wished away or tackled through statements and announcements alone, but with months and years of hard and decisive governance action and management of the economy.

Sir, I believe the President's Address is a good first step, and this, along with the forthcoming Budget could provide the necessary stimulus for our economy to recover and transform it to a sustainably growing, investing and a job-creating economy.

Sir, I listened to the Leader of the Opposition during his response. With greatest respect, I think he was trying to make a disingenuous case that there was nothing new in this President's Address, but he should excuse us for not being terribly enthusiastic about his claim. Here is why. Sir, let me quote to him the President's Address in 2005 — "My Government is committed to the reform of Government,

[Shri Rajeev Chandrasekhar]

making it more transparent, responsive and efficient. A model code of governance is being drawn up". Sir, this was in 2005. So, while the promise of good governance was being made, and I accept his argument that that is similar to this President's Address, the reality was a governance deficit in subsequent years, that has caused despair and shame that we all know. The focus, therefore, Sir, is execution and outcomes. This would then be the litmus test for this Government over the next 60 months. And all of us look forward to the Budget reflecting and further strengthening our confidence.

Sir, while I support the Motion, let me put forth a few suggestions to the Government. First of all, Sir, I hope that regardless of the majority or strength in Parliament, this Government adopts an approach of consensus and is sensitive to all sensible opinions made by Parliamentarians — big or small. Humility and consensus is more consistent with the notion of public service that Prime Minister Modi has described politics to be. This in itself would be a big departure from the arrogance of the last ten years, where it seemed that opinions of small parties and individual MPs didn't matter in any discourse.

Sir, I have a few more suggestions. Some colleagues in the Opposition have talked about 'maximum governance and minimum government'. I believe, Sir, that the call to 'maximum governance and minimum government' is absolutely the right thing, both in terms of the cost of the Government and the effectiveness of the Governance *vis-à-vis* the citizens they serve. The *per capita* cost of our Government is surely amongst the highest in the world, and, if adjusted for governance effectiveness, is probably amongst the least efficient in the world.

Sir, I would argue that the concept of minimum government is not just about Ministers with multiple Ministries, unless these are bound together with cost-saving and efficiency synergies. Some of the combinations currently do not pass that test, and such bundling could actually end up slowing down the decision making.

Sir, maximum governance, on the other hand, apart from a harder working Government, Ministers and bureaucracy, must also be expanded to mean rebuilding or creating new independent institutions like regulators and equipping them with budgets and capacity. The maximum governance theme needs to be expanded into deep, decisive governance reforms; that hinges around improving throughput and responsiveness of Government, and, at the same time, creating transparent, independent, credible institutions of governance; not some symbolic effort like the previous Administrative

Reforms Commission, but a deeply felt need to modernize and make more effective performance of Government and its institutions.

Sir, this re-architecting and change in our Governance is critical to the future of our country. The capture and corrosion of our institutions by politics and vested interests has to be reversed. Sir, we are a trillion dollar economy. That was also mentioned by some friends in the Opposition. But the size of the economy and the statistical newsfeed we have been fed over the last few years cover up the serious structural flaws. These flaws have come home to roost with 12 quarters of GDP decline, an almost full stop of investment and Government finances that have taken us to a fiscal precipice and is now resting there, thanks to some adept book keeping and accounting in recent times. It is critical to address these structural issues in our economy and Government finances if we are to set the economy back on a sustainable high growth path. Let me quickly summarise these structural issues.

Sir. The first one is the fiscal responsibility and the whole architecture of Government spending. The second one is the structural problem relating to the financial and banking sector. The financial sector which was for many, many years seen as a clean and well-regulated one is today plagued with allegations of money laundering and other perceptions that make investing in India high risk investment.

The other big worry is the health of PSU Banks which are owned by the people of India but seem to have been run like some people’s personal fiefdoms with lakhs of crores of NPAs dominating their balance sheets and writing off taxpayers equity. Regulatory competence, here again needs to be examined which allows 9 to 10 industrial groups in this country to borrow almost 90 per cent of the Indian banking systems net worth and creating the not ‘too big to fail’ syndrome putting the banks and taxpayers on the hook rather than the promoters. The basic principle of fairness and equity stands turned on its head when home owners and two wheeler owners have their assets seized on default of their loans, when multimillionaire businessmen who owe Indian banks end up with little or no pain. This situation is neither tolerable nor acceptable, and the Indian PSU Banks have to stop becoming piggy banks for politically friendly businesses. I look forward to hearing from the Government its approach to big business defaulters and a strategy to restructure and restore the health of PSU banks, and indeed all PSUs that are owned by the taxpayers.

Sir, the last structural issue is about PPPs. The role of private capital in infrastructure sector is vital and inescapable. The last decade has seen very flawed PPP models that have raised more questions about windfall returns to private investors

[Shri Rajeev Chandrasekhar]

at the cost of public and Government equity. A new approach to PPPs and fair balanced contracts or regulation that ensures consistency is the need of the hour. The current model, Sir, of cost-based regulation that has been used or misused for airports, gas and many others is deeply flawed and is being misused by many private investors and used to pad costs and pass them through to the consumer without any motivation to be efficient. Getting the PPP model of regulation and contracts right is critical to ensuring large FDI flows and investments into long-term investments. And in turn, a successful PPP model is critical to ensuring large scale FDI and domestic capital flows into infrastructure. ...*(Time-bell rings)*... I will end quickly. Sir, in the end, let me thank the Government for including a commitment to build and construct the National War Memorial soon. I had been pursuing this with the UPA Government since early 2008 and no progress was made apart from endless meetings of Committee of Secretaries and Ministers. I hope this Government moves fast on this and complete it in the next two years. Actioning this along with 'one rank one pension' announcement would be doing the right thing for millions of veterans and their families.

Sir, let me end by saying this. I don't claim to be a political pundit, but having campaigned during this election extensively and having interacted with many young and old Indians, I can safely say this. The people of India are anxious to change the discourse in politics from the old, divisive discourse of caste and religion to opportunity, dignity and governance. In the President's Address in 2009, there was a quote, "The dreary sand of dead habit must be left behind." It has been five years since that statement, and I hope this Government, and indeed all of us, can live up to that expectation. Thank you and Jai Hind.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now Mr. Tiruchi Siva wanted to know something. See, there are 11 speakers from 'Others' category and you have got one hour and two minutes left, one hour and two minutes less. That means nearly six minutes each and that is why I said seven. So, I was not unfair to anybody. In fact, Congress has got more than one hour. But their time I am reducing. That is why I said it. ...*(Interruptions)*... Now, Prof. Soz. Sozji, you will also take seven minutes.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Sir, I will try to complete within the given period of time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Very good.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Deputy Chairman, Sir, there is in my mind a situation of relief and satisfaction that India has given one more proof of being a very vital, very great democracy having inner vitality; otherwise, the kind of euphoria created through paid news aiming at sectarian polarization, if it had happened in any other country, that country would have collapsed. But India is a strong democracy and our institutions have become strong. And only India could bear this burden. It is a major question for the people who think about future, for the days to come. Now, I will give a positive response to what I heard from the hon. President of India. This is despite the fact that the Cabinet did not apply its mind seriously in preparing the Address. To my mind, it is a disjointed document of assertions and we shall see how these assertions will be realized in the days to come. Mr. Deputy Chairman, Sir, I welcome the assertion that they will generate hope, they will reform the Public Distribution System and they will give agricultural production a fillip. I wish this Government well in achieving these goals. Mr. Modi is, by way of vote, the Prime Minister of this country. We accept that fact despite the kind of polarisation that took place unfortunately. But this is also an assertion that they will give more fillips to agriculture and improve Distribution System. We have been aspiring to do that and as for generation of hope, this is also an assertion; we wish them well. Sir, I have some broader questions in my mind and I am skipping the things I have to say. It was an electoral euphoria. They have talked of growth and they have also talked of Gujarat model in the Address that the hon. President presented. Gujarat model was not explained and they are not clear about the growth. If they were clear about the growth, they would say, Dr. Manmohan Singh brought it to five per cent and in one year they would carry it to seven per cent. There is a hazy thinking on this. They know it is always easy to say things but very difficult to do things. We give them a chance. God willing, we shall be here and we shall see how much growth rate increases with this Government actions. In the Hon. President's Address, depending on what the Cabinet thought about, there is not a single expression saying it will be an inclusive growth. They are very shy of talking about inclusive growth. What are they going to do to this country if they are not clear on the inclusive growth? In the entire Address, this expression is not there. This expression is missing. This is very unfortunate. And, as for growth, they have not given any assurance that they have a model or they have a roadmap for that. I am sorry to tell this august House that they have no roadmap for increasing the growth rate in India and they have no contours to tell us how they will achieve a higher level of growth.

[Prof. Saif-ud-Din Soz]

Then, Mr. Deputy Chairman, they talk of zero tolerance for extremism and terrorism, and they have brought in crime and violence. Both UPA-I and UPA-II Governments were very clear on this question. This is nothing new. This Party is not clear about violence in this country. मुझे इन की नीयत पर शक हो रहा है। There are some brainy people in that Party also, but it is a major question for them. Are you clear? बीजेपी ने पुणे के हादसे पर कोई राय नहीं बतायी है, जैसे कोई इंसान मरा न हो। It is a major question for this country. मुझे ख्याल आता है कि क्या हम महफूज़ रहेंगे? अगर बीजेपी की हुकूमत होती, तो भी दिल में एक इत्मीनान था, लेकिन यह एक शख्स की हुकूमत है, जिसके दिमाग में यह है कि मैं इन्हें लाया हूं। जैसे यह एक रेवड़ है।

It will be a question for the BJP, much before it will be a question mark for this side, for the Congress party. इनकी नीयत पर मुझे शक हो रहा है क्योंकि पुणे में ऐसा हादसा हो गया कि राह चलते, रास्ते में चलते हुए आदमी को असेसिनेट किया गया और बीजेपी उस पर कुछ बात नहीं कर रही है। अगर यह बीजेपी की हुकूमत है, तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपकी पार्टी को क्यों यह गम और सदमा नहीं है? आप कहते हैं कि हम एक्सट्रीमिज्म को फाइट करेंगे। एक्सट्रीमिज्म तो आपकी गोद में पल रहा है और यह भारत के लिए, जो सेकुलर मुल्क है, एक बहुत बड़ा सवाल अगले जमाने में होने वाला है।

†[ان کی نیت پر مجھے شک ہو رہا ہے کیوں کہ پونے میں ایسا حادثہ ہو گیا کہ راہ چلتے، راستے میں چلتے ہوئے آدمی کا اسیسینٹ کیا گیا اور بی‌جے‌پی۔ اس پر کچھ بات نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ بی‌جے‌پی۔ کی حکومت ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو کیوں یہ غم اور صدمہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرزم کو فائٹ کریں گے۔ ایکسٹرزم تو آپ کی گود میں پل رہا ہے اور یہ بھارت کے لئے، جو سیکولر ملک ہے، ایک بہت بڑا سوال اگلے زمانے میں ہونے والا ہے۔]

Mr. Deputy Chairman, Sir, hon. President talked about minorities. And, they have done a big lip service to the minorities. It is an insult to the genus of the Muslims, who were freedom fighters, who brought this country up at this level of progress. The Muslims have contributed a lot. आप अभी वहां जाइए, वह कोठियां देख लीजिए, जहां काला-पानी में लोगों ने जेल काटी और वे वहां मर भी गए। वहां उस बोर्ड पर मुसलमानों का नाम भी लिखा है।

[آپ ابھی وہاں جائیے، وہ کوٹھیاں دیکھ لیجئے، جہاں کالا پانی میں لوگوں نے جیل کاٹی اور وہ وہاں مر بھی گئے۔ وہاں اس بورڈ پر مسلمانوں کا نام بھی لکھا ہے۔ ]

---

†[Transliteration in Urdu Script.]

And, you are talking about *madrasa* modernization. It is an ongoing scheme. Even when Dr. Murli Manohar Joshi was HRD Minister, he tried his hand on that and I welcomed him in this House. They are not going to do anything; they are not going to do anything for the Muslims of this country. The Muslims are the second-largest majority in this country, though they are in a minority. And, they say that they will modernize *madrasas.* I ask them to withdraw this. The Muslims will not be annoyed. What is the level of their participation in the political system? Do you give the tickets to the Muslims to come to Parliament of India? How many Muslims are representing their community in Gujarat? These are major questions for Mr. Modi and his colleagues. You have insulted the Muslim community by saying that you will modernize *madrasas.* Ask Dr. Murli Manohar Joshi. Let him talk to me. He is a Member of Parliament. We go to the Central Hall. I congratulated him that he was continuing that scheme. That Madrasa is needed because you do not set up a Government school. That is not a compulsion for the Muslims. They want a share in the economic governance of the country. They want a share in the political system. You do not understand the contours and the definition of *bhagidari*. Do you want to insult that community? Is it fair? ...*(Time-bell rings)*... Can you build a strong India without that community? ...*(Interruptions)*... That is a major question for the BJP. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...*(Interruptions)*... Soz*ji*, please conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I am concluding, Sir. They have left out the State of Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*... And, in the document, they say they will do something for Kashmeri *Pandits.* What are you going to do? Jammu and Kashmir has already given a package for the rehabilitation of Kashmeri *Pandits.* The majority of them are outside Kashmir. Of course, some Kashmeri *Pandits* are living there. But those who are migrants within their own country, they have to go back to their homes and hearth with dignity. But, what is your scheme? It is merely a lip service. Accept the proposal that has been given by the State of Jammu and Kashmir. Dr. Manmohan Singh had assured; the record is there, get the file and pass the orders and give a package. ...*(Time-bell rings)*... I am finishing, Sir, within two-and-a-half minutes. What about refugees from Pakistan? You did not mention in your document even a word about refugees from Pakistan, from the PoK. You have not mentioned even a word for the internally displaced refugees. Not even a single word has been said about the *Jats*. Jammu and Kashmir has totally been left out. You don’t talk anything about Zojila Tunnel Project. ...*(Time-bell rings)*... That is a project on. ...*(Interruptions)*... And, Laddakh region is separate. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You said only five minutes.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Finally, before I offer a couplet through them to Mr. Jaitley, I would like to say they are very weak in asserting that they will improve the functioning of the Judiciary. They say...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot say everything today.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Deputy Chairman, this is very important. The President's Address says that they would reform the criminal justice system to make dispensation of justice simpler, quicker and more effective. How can you do it? I remind this House that it was in 2003 that I had brought a Bill here. Thirty-eight people spoke on that Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please, Prof. Soz.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Jaitley was the Law Minister then. He left his seat and came to me, congratulated me. Let me just quote three lines of what he said in this House, "Mr. Soz, don't insist on putting this Resolution to vote. Thirty-eight people have spoken, cutting across Party lines." Mr. Sibal and others spoke. He told me this in 2003. "And we, in the Government, are seriously concerned with this issue. I am grateful to Prof. Soz who raised this issue, and to a large number of other Members who have spoken on this subject in a dispassionate..."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. Now, Shri Tiruchi Siva.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Then, he says finally, "Prof. Soz should wait to hear what the Government is going to do within some weeks."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is enough. Okay.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Within some weeks! This was in 2003.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Now, Mr. Tiruchi Siva.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: This was the NDA telling us, in 2003. And now, you don't even talk about judicial reforms.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. You may start, Mr. Tiruchi Siva.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: The judiciary needs reforms. Only then can you make things simpler.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot bring everything here today.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: You can make Judges decide on cases on time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Your time is over.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, since you have not given me time, let me offer a couplet to Mr. Jaitley. Unfortunately, you don't understand Urdu. I can translate it if you have time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should teach me. You are not teaching me!

**प्रो. सैफुद्दीन सोज़** : "बने हैं अहले हवस" मतलब एनडीए ने उस वक्त 2003 में कहा था कि चन्द हफ्तों में होगा।

†[**پروفیسر سیف الدین سوز** : "بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی
کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں]

**श्री उपसभापति** : आप कप्लेट बोलिए।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Now, so many years later, they don't make even a proper assertion in this document on what the President spoke.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed you time just for the couplet.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Now, I am saying, "बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ़ भी" मतलब ये दावा भी खुद करने वाले हैं और जज भी खुद ही बने हैं।

"बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ़ भी,
किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें।"

शुक्रिया।

†[**پروفیسر سیف الدین سوز** : "بنے ہیں اہل ہوس، مدّعی بھی، Now, I am saying, منصف بھی" مطلب یہ دعوی بھی خود کرنے والے ہیں اور جج بھی خود ہی بنے ہیں۔

"بنے ہیں اہل ہوس مدّعی بھی منصف بھی،
کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں"

شکریہ۔]

---

†[Transliteration in Urdu Script.]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

Associating with other Members of this august House, I am deeply grateful to the hon. President for the Address that he has been pleased to deliver to a Joint Session of both the Houses of Parliament.

Sir, Article 87 of the Constitution prescribes that the President will address the House of the People at the commencement of the first Session after the General Elections and at the commencement of the first Session of each year. As per what is prescribed in the Constitution, this is not an Address made by the President at the commencement of the first Session of the year; this is after the General Elections. And, in the concluding part of the Address, he has said, "The people of India have given a clear mandate. They want to see a vibrant, dynamic and prosperous India. In sixty months from now, we should be able to say with confidence and pride that we have done it". Yesterday, the Leader of the House, the former LoP and also the hon. Finance Minister, told us the same, that this is not the roadmap for just one year; this is for the next five years. Sir, doubts arise only at this point. When this is the future roadmap for the ensuing five years, some core issues which solicit the immediate attention of the Government have not been mentioned in the President's Address. I would not go into all those issues. Realizing the constraint of time, I do not wish to go into the issues of insurgency, infiltration, cross-border terrorism, the Maoist menace, and so on. I want to confine myself to issues of my State.

Sir, there are many issues which are prevailing in Tamil Nadu. Particularly, we have been raising an issue now, and then that is perennial, which has been continuing forever and which has not been addressed by any Government, the plight of our Tamil Nadu fishermen. Usually, when they go to sea, their families wait at the shores thinking that they would return with a good catch. But nowadays, they wait at the shores without knowing whether the fishermen would come back alive or not. Sir, this has been a repeated occurrence; we have raised it on many occasions, but nothing happens. The Sri Lankan Navy arrests Indian fishermen and sometimes, as a genuine or gentle gesture, releases some of them. But again they arrest some fishermen! Sir, we have not found any mention in the President's Address of this very, very important issue. So also is the case about the sad conditions of the Sri Lankan Tamils who have been butchered by the Government of Sri Lanka, who are still living in exile in their own soil, displaced, without food and shelter. No mention has been made of that. Also, no mention has been made about the river water disputes, which is concerned with two other States.

The verdict given by the Constitutional Bench of the Supreme Court is being disobeyed by a State, and the Central Government has no say in it. Another State wants to obstruct anything that has been pronounced as a verdict by the Supreme Court; the Central Government is a mute spectator.

Sir, I should go further to say that a responsible Union Minister who has to consider all the States as 'one' is pleading for one State. Excuse me, Sir, no Minister is listening to us. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ministers, please pay attention.

SHRI TIRUCHI SIVA: I think, we are making our speech to take it to the knowledge of the Government. They are all very serious issues.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Ministers should listen.

SHRI TIRUCHI SIVA: A responsible Union Minister, instead of doing his job for the entire nation, is pleading for one particular State and another Minister comes to his rescue and says that for the Cauvery Water Management Board, there is no proposal with the Central Government! This is in favour of one State and not in favour of another State. Sir, the people of Tamil Nadu, who are known for their agitations in a peaceful manner to achieve their ends are still awaiting it. The farmers in delta are starving. We are to face a famine. If Cauvery water does not reach the Delta area, the future of Tamil Nadu will be totally in despair. So, no mention has been made in the President's Address about the Sri Lankan Tamils, about the Tamil Nadu fishermen who are being treated very badly every time in Indian water itself — not crossing the borders; even in Indian water — and so also about the water disputes, Cauvery water, Mullaperiyar dam, etc. On all these things, they have not said anything.

So also, Sir, India has got no specific policy for refugees. The UN Charter has specified something which has not been followed by the Indian Government. I would urge the new Government, at least, to derive a policy for the refugees, Sri Lankan refugees, who are in Tamil Nadu. So, it goes on like that, Sir. There are so many issues. We have been repeatedly raising them. One gentleman, Father Alexis Prem Kumar from Tamil Nadu, a Christian missionary, who was in Pakistan, has been abducted by the Talibans in Afghanistan. His whereabouts are not known for the past ten days. Representations have been made by our leader in various quarters, and the affected family is suffering like anything. But, so far, there is no response from the Central Government. So, a new Government should act more responsibly. When they are very proud, happy and boast themselves of a clear mandate, what is it that a clear mandate

says? The people, the electorate, through their clear mandate, say, 'we want a Government that will serve us and not the one that will harass us. We want a Government to be a facilitator and not an obstructor. We want a Government to create opportunities for the greater sections of the people and not to a select few.' In this case, when you boast of this clear mandate, they start mocking, they start laughing at those who have lost. Only in schools we have seen children behaving like that. When they are playing or when they are running, if another boy falls down, they laugh at it. We are all matured people. We are in politics. Sir, in politics, 'ups and downs' are common. In election process, the person who is on top has to come to the bottom and one who is down may go to the upper level. This is quite common. Sir, hon. Dr. Manmohan Singh, whom we saw a few months before in the Treasury Bench, is sitting on the other side. I have seen Shri Atal Bihari Vajpayee in the other House. He was the Prime Minister for two weeks. Then, he sat in the Opposition side. Moreover, he chaired the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, and he acted like that. So, this is quite common. 'A party winning or a party losing an election' is not static. If they say it is a massive victory, they are just nine Members more of that magic number of 272. I would try to recall 1984 when Congress had a sweep — 400 seats — and when BJP had only two seats, nobody mocked at them. ...*(Time-bell rings)*... Sir, my course of speech was designed in another manner. But now I am compelled to say certain things. My esteemed friend whom I take the liberty of calling an esteemed friend for I consider that difference of political ideologies ... ...*(Time-bell rings)*... Sir, kindly excuse me. Do not stand in the way of friendship. I call Dr. Maitreyan my 'esteemed friend'. He spoke yesterday very eloquently and very elaborately that how they won the elections. ...*(Interruptions)*... You spoke yesterday and I am replying. If that is given, then I should also be given a chance. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't bring this. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: No, it is not an accusation. It is not an accusation. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is your friend. Don't bring this. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: It is not an accusation. I want to elaborate something. In eulogizing his leader, he went to the extreme of accusing us. ...*(Interruptions)*... We were recipient.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): I only said the facts. There was no accusation in it. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Okay. Okay. I welcome this. ...*(Interruptions)*...

They even went to the extreme of belittling their founder leader MGR. I can understand that because he is not that much associated or affiliated with MGR as his senior colleagues.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, kindly bear with me. I should say that this victory has been by hook or crook, by manoeuvers and manipulations. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): The downfall of the Congress is because of them. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But your time is over. ...*(Interruptions)*... Your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Speak on the President's Address. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*... Your time is over. ...*(Interruptions)*... Anyhow, your time is over. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am speaking on the Motion of Thanks. ...*(Interruptions)*... Sir, my time should not be taken away. ...*(Interruptions)*... These interruptions should not take away my time. ...*(Interruptions)*... I should be allowed to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: They should have the patience to listen to me. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Speak on the Motion of Thanks. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the President in his Address very very proudly said that ...*(Interruptions)*... Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... They should have the patience to listen first. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Don't accuse. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am not accusing any individual. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't waste time. ...*(Interruptions)*... You sit down. ...*(Interruptions)*... Why are you worried? ...*(Interruptions)*... Your leader is here. ...*(Interruptions)*... Why are you worried? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am not pointing to any individual. ...*(Interruptions)*... I am generally speaking. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You conclude please. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: The President's Address mentioned that it was a matter of great satisfaction that the recent general elections were smooth and largely successful and peaceful. So, I am speaking on the President's Address.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: One who was responsible for conducting the elections in a fair and free manner did not behave like that. ...*(Interruptions)*... Whatever we witnessed was total partiality and prejudice by the Election Commission. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: It is a Constitutional body. This is an allegation against the Election Commission. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I know. ...*(Interruptions)*... I didn't mention anything. ...*(Interruptions)*... I didn't mention anything. ...*(Interruptions)*... I know rules better than anyone else. ...*(Interruptions)*... I am not pointing out any individual person. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir. Coming to the very, very important point. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My request is to conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I have something to compliment them and some more issues to present to them. They are very, very important. Kindly forgive me. I don't plead that this is my maiden speech ...*(Interruptions)*... When I am giving some good points, kindly give me two more minutes. ...*(Interruptions)*... Sir, the President's Address says very much about the PDS. It says, "I will reform the Public Distribution System incorporating best practices from the States." I appreciate that. If, at all, you have to incorporate best practices, there is no other example than Tamil Nadu because Tamil

Nadu was the only State or the only State even now which has introduced Universal Public Distribution System. ...*(Interruptions)*... Kerala is having. ...*(Interruptions)*... But we started first, and now Kerala is going on. In all other States, there is a slab of APL and BPL. In Tamil Nadu, there is no such slab; it is only universalisation. We started giving rice at a price of Rs.3.5 per kilo, and we reduced it to Re.1, and now something has been done also. ...*(Interruptions)*... Take the liberty. ...*(Interruptions)*... We started that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Kindly, Sir, it is a very, very important issue. ...*(Interruptions)*... Give me two more minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please cooperate. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: The Government want to revive and reform the MSME sector. But they forget that the FDI in retail comes under the MSME sector. There is no mention of that in that. Shrimati Nirmala Sitharaman, hon. Minister, goes to the media and says that there won't be any FDI in retail sector. But there is no mention of it in the President's Address. Sir, FDI in retail sector will be a predator. That will kill the retailers in our country. So, this Government should explicitly come out whether FDI will be allowed or not.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is okay. ...*(Interruptions)*... Siva*ji*, please cooperate. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am not pleading for maiden speech. ...*(Interruptions)*... Kindly be considerate. ...*(Interruptions)*... You have given fifteen minutes to another Member. ...*(Interruptions)*... I am not asking for fifteen minutes. ...*(Interruptions)*...

I am pleading. I am not speaking in another manner. I am raising a very important issue. Sir, justice delayed is justice denied. This has also been taken up and the Government is planning to implement fast-track courts and we welcome it.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Sir, we hope that we will be treated equally and we will get the same time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? I can only divide the available time among Members.

SHRI TIRUCHI SIVA: I would say to this Government that they have been given a clear mandate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: And, Sir, for a larva to become a butterfly, we need certain time...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; that is enough.

SHRI TIRUCHI SIVA: We give you some time, but, at the same time, I would like to say, our mentor leader, Anna, carry on, but remember, this country is not for one particular religion or people; this is a nation of diverse culture, diverse linguist and diverse religions and everyone must be treated equally.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more will go on record. Shri Pramod Tiwari.

SHRI TIRUCHI SIVA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is all. It is over. Now, what Mr. Pramod Tiwari speaks will go on record.

SHRI TIRUCHI SIVA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give me a lot of tension. Mr. Tiwari, please take only ten minutes.

**श्री प्रमोद तिवारी** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह नहीं करता हूं, लेकिन यह एक ऐसा चुनाव था, जो ब्रांडिंग, प्रचार, विज्ञापन और लम्बे-चौड़े वायदे के साथ हुआ है। दीवारों पर लिखा रहता है कि 'हर मर्ज का शर्तिया इलाज,' कुछ इसी अंदाज से यह चुनाव लड़ा गया है।

मान्यवर, जो सरकार आई है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से तो यह जरूर जीती है, लेकिन आज अगर आप इस अभिभाषण को देखें तो यह यूपीए की मॉरल विक्ट्री है, नैतिक विजय है। इसकी एक-एक लाइन में वही लिखा है, जो यूपीए की सरकार कर रही थी। आज चुनाव के बाद यह साफ हो गया है कि हमारा रास्ता सही था और ये सरकार बनाकर भी उस रास्ते से अलग चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हम पूरी तरह से यह साफ करना चाहते हैं कि यह हमारी मॉरल विक्ट्री है। ये गिनती के आधार पर जरूर यहां बैठे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा कि जिस गुजरात मॉडल का बड़ा जिक्र हो रहा था, उस गुजरात मॉडल का सबसे पहला असर हमारे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव की शुरूआत में ही ट्रेलर के तौर पर मुजफ्फरनगर में देखा है। जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, अगर वही गुजरात मॉडल है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हिन्दुस्तान को इस गुजरात मॉडल से बचा

*Not recorded.

लो। जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ है, वह दोबारा उत्तर प्रदेश की धरती पर या देश की धरती पर कहीं न हो। उसी की चाशनी में यह चुनाव लड़ा गया है। मैं चाहता हूं कि गुजरात मॉडल का और नजारा हमें देखने को न मिले।

मान्यवर, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हमारी सारी नीतियों को स्वीकार किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो हम करते थे, वह नहीं हो रहा है। जो सबको साथ लेकर चलने की बात थी, यह सरकार इसको नहीं कर रही है। मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और देश के सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर सबको साथ लेकर चलने की बात थी और उस प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 71 या 72 इनको मिली हैं, तो उनमें से एक भी अल्पसंख्यक नहीं आया, तो यह इनकी फेल्योर है, पूरी तरह से उनकी असफलता है। ये कहते हैं कि ये पूरे हिन्दुस्तान को साथ लेकर चलेंगे, मुझे तो यह लगता है कि ये मुजफ्फरनगर मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए किसी अल्पसंख्यक को इन्होंने आने नहीं दिया और जो आया भी, उसे मंत्री नहीं बनाया। मैं तो कहता हूं कि अगर हो सके, तो मुख्तार भाई, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, उन्हीं का दिल देख लिया जाए। उनसे ईमानदारी से कहा जाए कि वे कसम रखकर कह दें कि वे इसका समर्थन करते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्तार भाई, आपका दर्द तो मैं समझता हूं। आप उत्तर प्रदेश से अकेले अल्पसंख्यक एम.पी. थे, लेकिन इन्होंने आपको भी नहीं लिया। शायद आपका गुनाह सिर्फ इतना था कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के थे और आप मंत्री एवं एम.पी. भी रह चुके थे। मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा उदाहरण मुख्तार भाई हैं। मैं आपसे यह उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि ये सबको साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे। मान्यवर, मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि वहां पर बीस प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है और वहां से अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना साफ़-साफ़ जाहिर करता है कि इनका आगे क्या कदम होगा।

मान्यवर, मैं अभी परसों ही दिल्ली के एक हिस्से में गया था। वहां दीवार पर नारा लिखा था, पोस्टर लगा था, "अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार बनने वाली है।" मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अंधेरा था। शाम का टाइम था। हर्षवर्धन जी से ज्यादा बेहतर वहां के हालात कोई नहीं जानता होगा। वहां पावर कट था। मैंने पूछा कि क्या हो गया है, क्या कोई लोकल फॉल्ट है? कहने लगे कि नहीं साहब, अच्छे दिन आने वाले थे, मोदी साहब की सरकार आ गई है, अब अच्छे दिन आ गए हैं,...**(व्यवधान)**... सुन तो लीजिए। अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब रात में भी यहां बिजली नहीं आती है। चूंकि अब अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, इसलिए अब बिजली की जरूरत ही क्या है? अब या तो अच्छे दिन आ जाएं या बिजली आ जाए, दोनों अच्छी चीज़ें एक साथ कैसे रह सकती हैं? मैं समझता हूं कि हालात बदलेंगे और आप उस पर कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। परंतु यदि बिजली पर भी यही गुजरात मॉडल है, तो यहां गोयल साहब जी हैं, मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिजली के जो हालात यहां के हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती किसी ने

[श्री प्रमोद तिवारी]

की है, तो वह भाजपा की सरकार ने की है। यहां की सरकार ने की और जब आप उत्तर प्रदेश में थे, तब भी की। मैं आपको याद दिला दूं कि जब-जब आपकी सरकार बनी, आपने बनाया तो कुछ नहीं, हम जो बनाकर गए थे, टांडा थर्मल पावर, ऊंचाहार थर्मल पावर, वे सब आपने बेच दिए। आपकी बेचने की आदत है। आपने जो उत्तर प्रदेश में किया है, उसको देश में मत कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा पावर प्लांट लगाइए, जिससे बिजली आ सके। आप उत्तर प्रदेश को कोल लिंकेज दीजिए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वहां रहती है।

[**श्री सभापति** पीठासीन हुए।]

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजली के मामले में, खास तौर से जहां कंटीन्यूअस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अमेठी, रायबरेली आदि क्षेत्र हैं, यहां पर कंटीन्यूअस राउंड दि क्लॉक बिजली की सप्लाई हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों जगहों पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं कि अगर बीच में बिजली चली जाए तो उद्योग रुक जाते हैं।

मान्यवर, इन्होंने सिर्फ यही ज्यादती नहीं की कि ऊंचाहर पावर प्लांट बेच दिया, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। मैं तो सीधे-सीधे कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए। जब आपकी सरकार थी, तो आपने उत्तराखंड बनाया था। इसका स्वागत है, लेकिन हाइडल की जितनी बिजली बन सकती थी, उसका पूरा का पूरा अधिकार आपने उत्तराखंड को दे दिया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया, इसीलिए आज हमारे पास हाइडल नहीं है। अगर आज उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है, तो यह आपकी पार्टी की देन है, आपकी सरकार की देन है और इसका प्रायश्चित आप इस तरह से कर सकते हैं कि केंद्र से उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए।

एक नारा और था। कहा जाता है कि ये जो कहते हैं, वह करते नहीं और जो करते हैं, वह कभी कहते नहीं। इन्होंने कहा था कि हम अपराधीकरण के खिलाफ लड़ेंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, हो सकता है कि जो अखबार मैंने पढ़ा हो, वह गलत हो, लेकिन जिनको आपने टिकट दिए थे, जो सम्मानित लोग हैं, आप जरा उनका बायो-डाटा निकलवा कर देख लीजिए कि उनका आपराधिक इतिहास कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना भरा-पूरा है। शायद ही इंडियन पीनल कोड की कोई दफा बची हो, जो उन पर न लगी हो। अगर आपका अपराधीकरण दूर करने का यही रास्ता है, तो मैं समझता हूं कि यह रास्ता देश के लिए अच्छा नहीं है, आप उसको बदलिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप आतंकवाद की बात कह रहे थे कि आप आतंकवाद से लड़ेंगे, आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, आपमें इच्छाशक्ति तो है ही, पर आपके साथ हमारा अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। जहां हम इस पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, वहां आपकी सरकार में ही आतंकवादी हमले हुए थे। मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस इनसे हाथ जोड़ रहा हूं कि अब की बार बचाए रखिएगा, क्योंकि पिछली बार तो मैं

लखनऊ में था, अब दिल्ली आ गया हूं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कह रहा हूं कि कम से कम पार्लियामेंट सुरक्षित रखिएगा। आप ही के टाइम में आतंकवादी लाल किले तक पहुंचे थे और जहां के सहारे से आप बात कर रहे हैं, शुरूआत तो उसी अक्षरधाम से हुई थी। मैं समझता हूं कि इस मामले में आतंकवाद से लड़ने का अगर कभी किसी ने राजनैतिक और प्रशासनिक हौसला दिखाया है, त्याग किया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, तो इधर बैठी कांग्रेस पार्टी ने दी है, जिसके दो-दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हुए हैं। जरा आप अपने किसी एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए, जिसकी उंगली का एक बूंद खून भी आपने आतंकवाद से लड़ते हुए बहाया हो। मैं समझता हूं कि आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद से लड़ने में अभी तक आपके वादे असत्य रहे हैं। अब जरा हिम्मत दिखाइए और हिम्मत के साथ लड़िए।

बहुत अच्छा हुआ कि आपने शपथ ग्रहण के समय हमारे पड़ोसी को बुलाया, अच्छा किया। लेकिन जब हम बुलाते थे, तो आप कहते थे कि वे हमारी गर्दन कलम करते हैं और आप उन्हें बुला कर बिरयानी खिलाते हैं। मुख्तार भाई, आप यही तो कहते थे। सबसे ज्यादा आप कहते थे, इसी की सजा आपको मिल रही है, क्योंकि आप प्रवक्ता थे। आप कहते थे कि वे हमारा सर काटते हैं और आप उनको बिरयानी खिलाते हैं। मैंने खास तौर से उनका मेन्यू देखा। इस बार बिरयानी आपने भी खिलाई।...**(व्यवधान)**...

**डा. चंदन मित्रा** : मेन्यू में बिरयानी नहीं थी।

**श्री प्रमोद तिवारी** : आप गलत कह रहे हैं। आपको नहीं मालूम, आपको उसमें नहीं बुलाया गया था। अगर आपको बुलाया गया होता, तो आप मंत्रिमंडल में होते। जिन लोगों को बुलाया गया था, उनसे पूछ लीजिए। बिरयानी थी। चंदन भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आपकी समझ में कुछ तो आएगा कि यहां बैठ कर बोलना और वहां बैठ कर बोलने में कितना फर्क होता है। आप यह दोस्ती निभाइए, चलाइए, हम स्वागत करेंगे। हम तो आपसे यह भी नहीं कह रहे हैं, आप पर कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको जुम्मा-जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, पर जो एक-दो खतरे हो सकते हैं, हम उनकी तरफ आपका ध्यान जरूर दिलना चाहते हैं।

सर, इनके जो दो-तीन वादे हैं, इनको याद दिला दूं, वरना ये भूल जाएंगे। सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं और आप तो इतने बड़े हैं कि 5-10 मिनट इधर-उधर कर ही देंगे।

**श्री सभापति** : बड़ी मजबूरी है, वक्त बहुत कम है।

**श्री प्रमोद तिवारी** : हां, मुझे मालूम है, सर, लेकिन आपके आगे वक्त की क्या मजाल है। आप तो 5-10 मिनट दे सकते हैं।

**श्री सभापति** : हाउस को वक्त की जरूरत है।

**श्री प्रमोद तिवारी** : आप तो वक्त के मालिक हैं।

आपने रोजगार के बारे में कहा था। आपने रोजगार का इतना प्रचार किया कि निस्संदेह जो बेरोजगार नौजवान था, आपकी तरफ बड़ी अच्छी नजरों से देख कर उसने आपको वोट भी दिया होगा, इसीलिए आपने सरकार बना ली, लेकिन इतना याद रखिएगा कि यह नौजवान है,

[श्री प्रमोद तिवारी]

इसका खून गर्म होता है। वादे तो आप करते हैं, आपको जो आदत पड़ी हुई है, वादे करने की, मत करिएगा, वरना अभी तो इस चुनाव में यह फूल लेकर दौड़ा था, अगली बार क्या होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।

मुख्तार भाई, आप इतराइए नहीं कि हम तो 44 पर आ गए, हमने तो वह पार्लियामेंट देखी है, जहां आप दो पर थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लौट कर आएंगे। आप फिर यहां बैठेंगे और आप तो दिल ही दिल में मना ही रहे होंगे कि जिसने हमको नहीं लिया, किसी तरह वह जितनी जल्दी चली जाए, तो अच्छा है, पर हम लोग यहां बैठ कर सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री प्रमोद तिवारी** : जी, मैं बस कंक्लूड ही कर रहा था। कंक्लूड करने में दो मिनट और लगेंगे।

मान्यवर, इनकी तो फेंकने की आदत है। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, फेंकने की आदत है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप रोजगार कैसे देंगे, उसका जवाब आप प्रधानमंत्री जी से दिला दीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे? यह अधिकार तो हमारा है, हम जान तो लें, ताकि लोग हमसे पूछें, तो हम कहें कि हां, हमारी सरकार यह करने जा रही है।

जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई से हर कोई परेशान है। आप महंगाई रोकने की बात कर रहे हैं, पर आज तक पिछले 14-15 दिनों में हमें महंगाई कहीं कम होती नहीं दिख रही है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं और यह मेरी आखिरी बात है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

आप जो संविधान की धारा 164 का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ खास तौर से आपकी तवज्जो चाहूंगा। सभापति जी, मैं खास तौर से आपकी तवज्जो चाहूंगा। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है। इस देश का बड़ा खूबसूरत इतिहास है। लोकतंत्र में लोक सभा और राज्य सभा में जो सांसद चुन कर आते हैं, वे मंत्री बनते हैं। उनके साथ जनता का विश्वास होता है और वही इस सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। आपने अपने शुरुआती दौर में ही सचिवों को बुला कर अपने नंबर दिए और उनसे कहा कि सीधे हमसे बात करो। अगर सचिव आपसे सीधे बात करने लगेंगे, तो आपके ये मंत्री क्या बेचेंगे! इन मंत्रियों की हैसियत क्या रह जाएगी! अगर आप सचिव से सीधे बात करेंगे और मंत्रियों की कोई पूछ नहीं होगी, जिस दिन उनको मालूम हो जाएगा कि यह मंत्री हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो ये भारत की बर्बादी के आसार होंगे। सच कहूंगा कि यह लोकशाही नहीं, बल्कि आपका कदम तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और इस तानाशाही को रोकना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Tiwariji, thank you very much.

**श्री प्रमोद तिवारी** : इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, मेरा तो प्रमोशन हो गया है। मैंने अपना भाषण उपसभापति जी से शुरू किया था और अब वह सभापति जी तक पहुंच कर समाप्त हो रहा है।

अंत में सिर्फ एक बात कह कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने जो कुछ कहा था, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। हम अभी तो यह नहीं कह सकते कि आप असफल रहे हैं, लेकिन यह अवश्य कह सकते हैं कि आपका रास्ता गलत है। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में खुशहाली नहीं है, बरबादी है। अगर आप बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तो हम भी खामोशी से नहीं बैठे रहेंगे। हम आपको हिन्दुस्तान को बरबाद नहीं करने देंगे। पूरी आवाज़ से हम आपका विरोध करेंगे। अगर आपने इसकी धर्म-निरपेक्षता पर आवाज उठाई, तो हम आपके खिलाफ संघर्ष करेंगे।

मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि राष्ट्रपति जी का यह जो अभिभाषण है, जो हम पहले से कर रहे थे, पूरी तरह इसमें आपने वही किया है। लेकिन आपने जो नकल की है, हमारे नेता के शब्दों में, नकल के साथ थोड़ी अकल लगा लेते और शब्दों का जो चयन आपने किया था, उसको थोड़ा ठीक कर देते, तो अच्छा था। अब आप मेरी सिफारिश लगा दीजिएगा। मुख्तार भाई अकेले हैं, अगर उनका कुछ भला हो जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Pyarimohan Mohapatra. I will be constrained to restrain time consumption.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I will not take 12 minutes like my friend from...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It will be much less than that.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Nor like Shri Tiruchi Siva who took 15 minutes. They have been allowed that much of time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Five minutes is the maximum as per the present schedule that I can allow.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, just before this, Shri Tiruchi Siva has been allowed 15 minutes.

MR. CHAIRMAN: He was but since then we have derailed...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I will try to be as brief as possible.

Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address. I welcome the correct emphasis on e-governance, digitisation, manufacturing sector, tourism, agro industries, agriculture and also the emphasis on development according to our own tradition and culture. The Gujarat model of development is being bandied about and it is being criticised without being understood. Let us not talk about that model. India is not Gujarat. In fact, when we were sharing the dais together in April, 2010 at Surat, I told Modiji that he was a Prime Minister material, he should not confine himself

[Shri Pyarimohan Mohapatra]

to Gujarat and he should look at Delhi. He said, "Is it because you appreciate Gujarat model?" I said, 'No, there are plenty of models in different States. What I appreciate is your style of governance." Governance is his strength. He has a firm grip on governance and on the entire situation. This was what I noticed in detail and this was what I appreciated. Hopefully, Modiji will have a firm grip here contrary to whatever apprehensions are being expressed. In the name of democracy you may keep on saying that this is a Cabinet form of Government and a Prime Minister should only be one among equals. It is in theory. With Indiraji, it was not theory. Indiraji did the same thing. Rajivji did the same thing. It was the Prime Minister who was ruling. It is only when there is not a stable majority, the Prime Ministers behave in a weak manner. When democracy gives a stable majority to somebody, it also gives him authority and that authority has to be exercised. And a decisive person is needed for the country right now. It has been too much of indecision and it has destroyed the Government. But I must also put a note of caution. India is not Gujarat. Unless you make structural changes, for which there has been no reference in the President's Address, you cannot develop it. Structural change has to go down to culture and tradition. Our culture and tradition say, give the governance to the village. Let every village be a panchayat. Let them decide what is good for them. Models have been thrown at the country by them. Don't throw models at the country. Don't throw schemes at the country. Let every State, and not only every State, but every village, decide its future. You are talking of elimination of poverty and it is criticised. They said it is BPL and you want to take them to APL. Let us forget poverty. Your elimination of poverty is not going to help anybody. Please fix a minimum prosperity level, MPL. Remove poverty, put prosperity. Let us ensure altogether that we head towards prosperity. That should be the *mantra.*

Now, I come to job creation and strategic labour intensive manufacturing sector. Sir, manufacturing sector is not going to be labour intensive at all now nor in the future. It was not so in the past decade or so. They will not create jobs. Corporates will look for smaller and smaller work force. They will cut manpower. Once you say in the Address that for becoming global, scale ought to be increased, jobs will be few and far between. So, please look at micro. Look at MSMEs – micro, small and medium enterprise and particularly, small industries, village industries, artisans and craftsmen. You have skill development programme. What will you do with it? If people are unskilled or semi-skilled, you will make them skilled and there will be no jobs in the manufacturing sector.

On the issue of corruption, the UPA stopped or slowed down investigations against those who promised outside support. There are plenty of cases where even the Supreme Court monitored CBI investigations had been slowed down deliberately. God knows, they were in trouble in the Lok Sabha and you are in trouble here for a majority. To get a majority, to get support, heaven forbid, you do not also do similar things of slowing down investigations against a few high and mighty ones who have numbers in this House.

MR. CHAIRMAN: Seven minutes over.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, please give me a minute because I am coming to a vital point relating to my State. In the Address, it is mentioned that special attention will be given to Telangana and Andhra Pradesh. I don't want to bring up the controversial issue of Polavaram which has been ignored by that side and it has been ignored by you today. But, Polavaram will be opposed by Odisha, Chhattisgarh and Telangana and you will have trouble. Why Odisha has been lost in the definition of Eastern States when Telangana and Andhra Pradesh are mentioned. There is no mention of special category for Odisha. It is one of the poorest States. In respect of poverty, we are at the bottom. We give Rs.14,000 crores to the Railways. We get a little less than Rs.3,000 crores. Royalty rates have been kept low. So, we cannot develop on our mineral resources. So, please look at those points.

Out of 50 tourism circuits which are mentioned in the Address, please give five to Odisha because Odisha is a place of heritage and cultural tourism as well as anthropological tourism. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Shantaram Naik.

SHRI SHANTARAM NAIK: Mr. Deputy Chairman, Sir, I will mention two or three things from the President's Address.

I would like to stress on article 51A of the Constitution which speaks of the scientific temper. Considering the Government and the party which has come to power it was their duty to clear the apprehension in the minds of various communities that this party which is ideologically close to the RSS and the VHP believes in scientific temper, and that they will not do anything which will harm article 51A of the Constitution. This commitment should have been given in the President's Address.

Secondly, there was a talk about development and other aspect. As my colleague, Shri Jairamji has said, they have stressed on the development but omitted certain things.

[Shri Shantaram Naik]

The President of India should have used his discretion to see that the text of his Address was true to the communal aspect, which is a reality, which should have been reflected. In fact, the achievements of the UPA-I and UPA-II in the last ten years should have been mentioned in the President's Address without fail because not mentioning these achievements makes the Address incomplete.

Thirdly, there are a number of pending Bills. Some Bills were introduced in the other House; and some Bills were introduced in this House. Therefore, the President's Address should have made a commitment that Bills introduced in Lok Sabha would be revived and Bills introduced in Rajya Sabha would be carried forward. This commitment is not there. There has been a mention in the Address that there will be four layers by which administration will be done. What are those four layers? Nowhere has it been mentioned. Unless you amend the rules of the business of the Government of India where several layers of the administration have been mentioned, you can't speak of four layers. Actually, as has been pointed out by other colleagues of mine, there are no four layers of administration. In Gujarat there is only one layer, and that layer is the former Chief Minister of Gujarat. If the former Chief Minister wants to implement the same one layer principle at the Centre, then, that should have been mentioned.

Fourthly, they have given a commitment of 33 per cent reservation for women. It is very good. But when this Government is guided by the principles of the RSS where there is no place for women, and without green signal from the RSS, you can't go ahead, how will you attain 33 per cent reservation for women in Parliament and State Legislatures? Let it be cleared. First, your guiding agency, guiding satellite organisation, must give clearance, only then you can mention about it. Otherwise, by not mentioning it, our doubt will remain.

Fifthly, how are you going to modernise hundred cities in this country? Modernisation of hundred cities requires crores and crores of rupees. Unless your NRI friends, who have promised to make investment and help you, and you want to help them, fine, hundred cities would not be improved.

Sixthly, bullet train network and development of hundred cities mean what? These works require ten times of the Government of India budget. Wherefrom this budget will come?

I would like to mention another aspect with respect to the State of Goa. The Chief Minister of Goa, Mr. Parrikar is also ideologically called as Modi of Goa. We

have no problem. He came and met Shri Narendra Modi. I would like to know whether Mr. Parrikar has mentioned two points to Shri Narendra Modi, which he has promised to the people of Goa. He said that he will have special provisions under article 371 of the Constitution. He has mentioned it time and again. And I had also taken up this issue, at least, five times in the House. He has repeated that several times, and I welcome that. But I would like to know whether he mentioned about it to the Prime Minister when he met him recently.

Another aspect is about the All India Services Cadre. This Cadre does not have a good rapport with the Chief Minister of Goa and hence he wants a separate Cadre. It is welcome and it is my submission as well. I would like to know whether these two crucial points had been raised before the Prime Minister, Shri Narendra Modi, during their last meeting. I ask this all the more because these were the crucial points taken up as election issues by the State.

Another aspect relates to the High Court of Goa. I would like to know whether this was mentioned anywhere during their meeting because the Chief Minister had said that he would be taking up these crucial issues, affecting Goa, with the Prime Minister of India. Now, if these three crucial issues were not taken up in this meeting, then, it is most unfortunate for the State and the country as such. I heard that the Prime Minister is coming to Goa to inaugurate some project on defence. He is most welcome. He is also coming to Goa to inaugurate the new Mandvi Bridge. That is a welcome thing. But let us know the source of money for the Mandvi Bridge because we know that the Mandvi Bridge will be on the National Highway and the funds have to come from the Central Government kitty. I would like to know whether the State Government is spending for this or it is the Central Government. Thank you, Sir.

**श्री बिश्वजीत दैमारी** (असम) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का जो यह अभिभाषण है, इसमें हमारे देश को बदलने के लिए, उन्नति करने के लिए कुछ नीतियों और कुछ परिकल्पनाओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ-साथ, भारतवर्ष का जो उत्तर-पूर्वी सेक्टर है, उसको भी प्राथमिकता देने का जिक्र इसमें किया गया है। यह सिर्फ आज की ही बात नहीं है, बल्कि हर समय और हर सरकार के टाइम में जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा जाता है और उसको पेश किया जाता है, तो उसमें इसका जिक्र होता है। चाहे वह जनरल बजट हो या रेल बजट, उनमें भी उत्तर-पूर्वी सेक्टर के लिए कुछ न कुछ परियोजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन आज तक उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आज नॉर्थ-ईस्ट में सबसे बड़ी जो समस्या है, वह उग्रवाद की समस्या है। इस उग्रवाद की समस्या को किस तरह से हल किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। मुझे पता नहीं कि आज भारत सरकार नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं को छोड़कर किस तरह से इस देश की उन्नति की परिकल्पना कर सकती है या

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

वह नॉर्थ-ईस्ट को छोड़ने के बाद बाकी जगहों को डेवलप करने के बाद खुद कैसे गौरवान्वित महसूस कर सकती है?

आज वहां केवल डेवलपमेंट की समस्या नहीं है, बल्कि वहां कुछ राजनीतिक समस्याएं भी हैं। वहां नये-नये राज्य बनाने की डिमांड्स हो रही हैं। जब वहां के डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तब वहां एक-एक राज्य बनाने की डिमांड शुरू हो गई। जैसे, आज वहां की पृथक बोडोलैंड की समस्या बहुत पुरानी है और वहां के लोगों को इस समस्या के कारण आज भी बहुत ही कठिनाई से जीवन-यापन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। इसके लिए आज बहुत सारे उग्रपंथी संगठनों का जन्म हुआ है। आज नागालैंड की जो समस्या है, उसमें एनएससीएन (आईएम) और खापलांग ग्रुप के साथ लगभग 15 सालों से भी ज्यादा समय से बातचीत चल रही है, लेकिन आज तक नॉर्थ-ईस्ट वालों को यह पता नहीं है कि उस बातचीत के ज़रिये क्या हुआ या उससे इस समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। जब तक आप इस समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक आप नागालैंड जैसे राज्यों में कोई डेवलपमेंट नहीं ला पाएंगे। इसी तरह, असम में ऐसे बहुत सारे उग्रवादी संगठन हैं, एक्सट्रिमिस्ट संगठन हैं, जिन्होंने कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण जन्म लिया है। और वे ही लोग आज सरकार के साथ दो साल से भी ज्यादा से बात कर रहे हैं। जैसे आदिवासियों ने वहां पर खुद को एस.टी. स्टेट्स देने के लिए आंदोलन किया है और इसके लिए आदिवासी ग्रुप संगठन बातचीत कर रहा है, - आदिवासी कोबरा मिलट्री ऑफ आसाम, बिरसा कमांड फोर्स, आदिवासी नेशनल लिब्रेशन, आर्मी, सन्ताल टाइगर फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी और नेशनल आदिवासी लिब्रेशन आर्मी, इन सब से बात करने के बाद आज तक उन लोगों को एस.टी. स्टेट्स मिलने की मांग है। इस समस्या के समाधान का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी तरह अपर आसाम में Moran जाति के लिए, Motak जाति, Tai Ahom, Koch Rajbongshi, Adivasi-Tea tribes और Chutiya इसी तरह सभी जातियां एस.टी. स्टेट्स के लिए वहां पर संग्राम कर रही हैं और हर समय वहां पर बंद वगैरह किया जाता है, गाड़ी-घोड़ा जलाया जाता है, जिस कारण बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण वहां पर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, वे अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी दो साल तक इस समस्या का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। इसी तरह मेघालय में भी हमारे गारू भाईयों की समस्या है। जो कि वहां का एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप भी बात कर रहा है। लेकिन आज तक इसका भी समाधान नहीं हो पाया है। समस्त उग्रवादी संगठनों द्वारा सरकार से बात करने के बाद वहां पर जो काम हो रहा है, खुलेआम बंदूक लेकर सारे नॉर्थ-ईस्ट में घूमता रहता है तथा बाजार व अन्य जगहों में भी जा सकता है। इस बार हमारे संसद में भी उल्फा का एक नेता बिना शस्त्र समर्पण किए आज एम.पी. बनकर आया है। नॉर्थ-ईस्ट में एक ऐसा माहौल है, शायद वह एस.टी. कांस्टीट्यूंसी से आया है। इसलिए सारे भारत में इस बात की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर उग्रवादी बनने के बाद बंदूक लेकर, बंदूक सरेंडर किए बिना, वह अगर एम.पी. भी बन सकता है तो कल इस पार्लियामेंट में कितने उग्रवादी नेता आएंगे? वह भी सोचने की बहुत

जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सरकार इस ओर ध्यान देगी और नॉर्थ-ईस्ट का डेवलपमेंट करने के लिए और वहां की उग्रवाद की समस्या का समाधान करने के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह जो बोडोलैंड की समस्या है, यह बहुत पुरानी समस्या है। इसके लिए पूर्व सरकार ने एक कमेटी बनाई है। मैं अनुरोध करता हूं इस कमेटी को जितना जल्दी हो सके उनको कार्यवाही करने दो और इसके ऊपर अगर वह कोई एडवाइज देती है तो उससे एक समाधान निकल सकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्दी हो सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री बिश्वजीत दैमारी** : बाकी जो आईआईएम और आईआईटी और इसी तरह एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई है, नॉर्थ-ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं, मैं अनुरोध करुंगा कि हर स्टेट में ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ऐसा न हो कि नॉर्थ-ईस्ट में केवल एक ही इंस्टीट्यूट हो और आप कहें कि हमने उसको दे दिया।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री बिश्वजीत दैमारी** : एक-एक आईआईटी, एक-एक आईआईएम और एम्स जैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी यह सरकार इसको अवश्य कर पाएगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Satyavrat Chaturvedi. Not present.

**श्री रणवीर सिंह प्रजापति** (हरियाणा) : धन्यवाद सर, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस लोक सभा चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को और एनडीए को प्रचंड बहुमत देने का काम किया। इसके लिए मैं अपनी पार्टी आईएनएलडी की तरफ से इनको बधाई देता हूं। सर, जब देश के लोगों ने जिस तरह से जिस उत्साह से रिकॉर्ड वोट करने का काम किया है, लोगों की उम्मीदें भी उस सरकार से बढ़ जाती हैं। मैं सरकार की तरफ से जो अभिभाषण महामहिम राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, उसका स्वागत करता हूं और सरकार ने हर वर्ग को, हर क्षेत्र को टच करने का प्रयास किया है। सरकार से देश को उम्मीद है कि सरकार कृषि, स्वास्थ्य और खास कर लॉ एंड आर्डर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए उचित कदम उठाएगी। महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित है। हमारे किसान बगैर संसाधनों के भी कड़ी मेहनत से पूरे देश के लोगों का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण, उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, जिस कारण किसान निरंतर कर्ज में डूबता चला गया। महोदय, काफी अनाज पैदा करने के बावजूद किसान अपने बच्चों सहित भूखे पेट सोने पर मजबूर हुआ।

अभी लीडर ऑफ अपोजीशन ने कहा कि हमने एमएसपी निर्धारित की। लेकिन एमएसपी निर्धारित करने वाली संस्था में कृषि वैज्ञानिक होने चाहिए, किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए, ताकि किसान को उसकी लागत का मूल्य प्लस उसका लाभ मिल सके, तभी उसे एमएसपी का फायदा मिलता है। इस के साथ ही उसकी फसल की खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया कि किसानों को उचित मूल्य देने के लिए एमएसपी निर्धारित की जाएगी।

[श्री रणवीर सिंह प्रजापति]

मैं निवेदन करूंगा कि उस संस्था में किसानों के नुमाइंदे और कृषि वैज्ञानिक शामिल किए जाएं। उसे फसल की लागत प्लस लाभ दिलाया जाना चाहिए। साथ ही उसकी फसल की खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। पिछली सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दी, लेकिन कई फसलों की एमएसपी तो लागत मूल्य से भी कम निर्धारित की गयी। फिर उस लागत मूल्य पर भी उसकी खरीद नहीं हो पा रही थी, जिस कारण किसानों को बड़ी दिक्कत व परेशानी हुई और किसान व किसानी निरंतर गर्त में चली गयी। महोदय, खासकर जब हम यूरिया व डीएपी की उपलब्धता के आंकड़े मांगते हैं, तो सरकार आंकड़े देती है कि जिस राज्य में जितनी जरूरत है, उस से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में वह स्टेट में है। लेकिन जब किसान को जरूरत होती है, जब बिजाई का टाइम आता है और वह बाजार के अंदर खाद लेने के लिए जाता है, तो उसे कहा जाता है कि अभी रैक नहीं आया है। फिर उसे वह सब ब्लैक में लेनी पड़ती है और जब वह उसे यूज कर लेता है, तब जाकर खाद आती है। महोदय, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि किसान के ऊपर इस तरह की दोहरी मार न पड़े।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप ने इस में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का समावेश किया होता तो बहुत अच्छा होता। सरकार को इस के बारे में भी विचार करना चाहिए। महोदय, इसमें सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात कही गयी है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरियाणा का एसवायएल का बहुत पुराना मुद्दा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद अधर में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सरकार एक साल में बनाकर दे और अगर वह नहीं बनाती है तो बीआरओ उसे बनाकर दे। महोदय, यह हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा को इस का पानी दिलवा कर उस के किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

महोदय, इस अभिभाषण में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात कही गयी है। यह बहुत अच्छी बात है।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त करें।

**श्री रणवीर सिंह प्रजापति** : इस से हमारी बहनों, बहुओं व बेटियों को आगे बढ़ने का और ज्यादा मौका मिलेगा। इस के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा व एससी एसटी तथा बैकवर्ड क्लास के लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना की ओर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं खासकर हरियाणा प्रदेश की बात कहूंगा। वहां पिछले समय में इस वर्ग के लोगों पर अत्याचार बढ़े हैं। महोदय, यह केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि एससी एसटी आयोग ने भी अपने दौरे के समय यह बात कही कि अगर दलित व बैकवर्ड्स के लिए आज सब से ज्यादा कोई असुरक्षित प्रदेश है, तो वह हरियाणा प्रदेश है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो।

**श्री सभापति** : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री रणवीर सिंह प्रजापति** : पिछले कुछ सालों से वहां कांग्रेस की सरकार है। मैं पुन: विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वहां बैकवर्ड क्लास व एससी, एसटी के लोगों के अंदर असुरक्षा का

माहौल पैदा हो गया है। इसके साथ ही विशेष तौर से मैं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने जो वायदे किए हैं, उन वायदों पर ये खरे उतरें, इसमें हम इनका यहां भी और लोक सभा के अंदर भी अपना सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री मोहम्मद अदीब** (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया, जनाब। मैं जब प्रेजिडेंट साहब के एड्रेस पर यहां बोल रहा हूं, तो मैंने पहले उसको पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि यह बीजेपी के मैनिफेस्टो का कोई दूसरा एडिशन आ गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को अभी यह यकीन नहीं आया है कि ये सरकार में आ गए हैं, ये अभी इलेक्शन मोड में हैं, जबकि इनके सहयोगी मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर तो समझ गए हैं कि ये सरकार में हैं। इसमें तो आपने इस तरह के वायदे किए हैं कि आसमान ले आएंगे, तारे जमीन पर दे देंगे, सूरज ले आएंगे। आपके लिए तो यह ऐसा वक्त था कि आप कुछ करके दिखाते। मैं समझता था कि ऐसा कुछ आएगा, आप बताएंगे कि आप ऐसा कैसे करेंगे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ख्वाब बेच कर आए हैं, इसमें जिम्मेदारी इन लोगों की भी है, जो आज इधर हैं। इनके किले को तोड़ने के लिए यह कहा गया कि एक लाख पचहतर हजार करोड़ रुपया खा लिया गया। टीआरएआई के एक चेयरमैन साहब ने 66 हजार करोड़ और कितने लाख का कहा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर जवान तक सबके जेहनों में यह बात बैठ गई कि यह सरकार पैसे खा गई। जिस ऑफीसर ने यह प्रोग्राम बनाया और कहा कि यह ऑक्शन नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर होगा, वह आज कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है और कानून के खिलाफ बनाया जाता है, ऑर्डिनेन्स लाकर बनाया जाता है। अगर तारीख देखी जाए, तो हिन्दुस्तान में कभी किसी एक ब्यूरोक्रेट के लिए ऑर्डिनेन्स नहीं लाया गया। उस वक्त जिस मिनिस्टर ने यह किया, वह तो जेल पहुंच गया। मैं जब इस पर सोचता हूं, तो यह समझ में आता है कि पर्दे के पीछे कुछ और था। यह जो एक लाख पचहतर हजार करोड़ की कहानी थी, वह आज तक समझ में नहीं आई और हमारी सरकार की नींव उखाड़ दी गई। लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ? यह एक साजिश के तहत हुआ था। आज वह ऑफीसर कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है और कानून के खिलाफ, क्योंकि कानून यह कहता है कि वह नौकरी नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए ऑर्डिनेस लाया गया। हमारे साथियों की समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है।

सर, यह कहा गया कि हम घर-घर में बिजली पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाओगे? जो नदियां हैं, वहां तो सिल्टिंग हो गई है, हाइड्रो पावर कम हो रहा है और जो कोयले से लाओगे, तो वहां तो कोयले का घोटाला हो गया, ऑक्शन होगा। अब कोयला कितने का खरीदा जाएगा, बिजली कितने की लाई जाएगी? एक और तरीका था कि एटॉमिक एनर्जी लाई जाए, तो उस वक्त कहा गया कि अमेरिका के हाथों बिक गए हैं। अब ये लोग इधर से उधर पहुंचे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिका के हाथों अब आप कितना बिकेंगे? आप यह तरीकेकार बदलिए। अब आप बताइए कि बिजली कहां से लाएंगे? चूंकि जब आप बिजली लाएंगे, तभी आप घर-घर को देंगे। सिर्फ नारों से काम नहीं चहेगा। हमारे फॉरेन अफेयर्स पर बात की गई थी। अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, हम बेपनाह खुश हुए। हमने सोचा कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, तो दाऊद इब्राहीम भी पीछे हथकड़ी लगाए चला आ रहा होगा, हाफिज सईद भी आ रहे होंगे, वे लोग, जिन्होंने हमारे फौजी जवानों के कत्ल किए थे, उनके कटे हुए हाथ आ रहे होंगे, मगर पता लगा कि यह तो नहीं हुआ बल्कि कुछ शॉलें एक दूसरे को दी गईं, एक-दूसरे के मां-बाप को पैसे भेजे गए। यह

[श्री मोहम्मद अदीब]

क्या सियासत है? यह कैसी सियासत है? जिस वक्त मनमोहन सिंह जी ने यह कहा, मैं इस बात का गवाह हूं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ताल्लुकात ठीक हो जाएं, तो कहा गया कि गर्दनें चाहिए। क्या इस सीट से उठकर उस सीट पर जाने का अलग निजाम होता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई नक़वी जी ने भी यह कहा, बड़ी खूब बात कही, मेरे दिल में जगह बन गई थी, उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मुसलमान आज भी मुस्तवा और मशकूक है। दाढ़ी और टोपी वाले पकड़े जाते हैं। मुझे अच्छा लगा था कि मेरे भाई ने मेरे दर्द को महसूस किया, लेकिन आई.बी. का वह ऑफिसर, जिसने यह प्लान किया था कि मुसलमान नौजवान, बच्चे जेलों में जाएं और पकड़े जाएं, तब दस साल के बाद अदालतों ने उनको बाहर किया, आज उसी ऑफिसर, अजीत डोवाल का दूसरा अपॉइंटमेंट हुआ और वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गया। इससे हमारे दिल को धक्का ज़रूर लगा।

सर, हमारी बड़ी बहन बैठी हुई हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि माइनॉरिटी अफेयर्स को कायम रखा गया है और यह बात बार-बार कही जा रही है कि "एक्सक्लूसिव ग्रोथ" करेंगे, सबको लेकर आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसी ही कि रेस के घोड़े इक्के और तांगे के घोड़ों के साथ दौड़ाए जाएंगे, इसलिए कहेंगे कि आपको दौड़ाने को दिया। जब इस सरकार को यह पता लगा कि ये जो घोड़े हैं, ये इक्के और तांगे के घोड़े हैं, कमज़ोर हैं, इनके लिए कुछ प्रोग्राम लाए गए, उन प्रोग्रामों का क्या होगा, आप खत्म करेंगे या रखेंगे, इस पर कोई बहस नहीं है, "एक्सक्लूसिव ग्रोथ" पर बहस है। जब यह बात समझ ली गई कि इस मुल्क में हम कमज़ोर हैं, इसके लिए एक स्कीम लाई गई, उस पर खामोशी है। कहा गया - आतंकवाद को, टेररिज्म को रोकेंगे। आज एक इंजीनियर पुणे में शहीद किया गया। वह प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास एक टीम है ट्विटर चलाने की, तो उंगलियां तो चलती हैं, लेकिन आज तक कोई उंगली इस बात पर नहीं आई कि उस नौजवान बच्चे का कसूर क्या था, सिवाय इसके कि दाढ़ी थी और टोपी थी! आप कहते हैं कि हम एसआईटी बनाएंगे।

**श्री सभापति** : प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

**श्री मोहम्मद अदीब** : सर, दो मिनट दे दीजिए।

**श्री सभापति** : दो मिनट नहीं।

**श्री मोहम्मद अदीब** : हज़रत, आपने सात मिनट का टाइम दिया था, मैं अभी खत्म करता हूं। एसआईटी के लिए कहा गया कि एसआईटी बाहर से पैसा लेकर आएगी। मेरे अज़ीज़ो, सिर्फ एनसीआर में जो रोज़ रजिस्ट्री होती है, करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी बनता है, उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला बनाया है, ज़रा यह भी तो बताइए। इस पर कोई बात नहीं है। एसआईटी बनेगी, बाहर से काला धन लाया जाएगा, यह ख्वाब अब मत दिखाइए। इसलिए न दिखाइए कि हमें कुछ खौफ हैं, कुछ डर हैं।

आपके एजेंडे में खुशी की बात है। मेरे एक साथी ने कहा कि आपके जो तीन एजेंडे हैं, जो तीन झुनझुने हैं, उनके कम से कम आपने प्रेज़िडेंट के ऐड्रेस में नहीं कहा। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा राम मंदिर और तीसरा 370 है। आप यह बता दीजिए कि आप इनको

कब-कब बजाएंगे, कब-कब वोट लेने के लिए बजाएंगे, इसको भी ज़रा खुलकर कह दीजिए ताकि हमें यह पता लग जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं।

**श्री सभापति** : अदीब साहब, शुक्रिया, थैंक यू।

**श्री मोहम्मद अदीब** : हमारे तिवारी जी ने जो एक बात कही, वह बात कहकर मैं खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अब मिनिस्टर नहीं, अब जो सेक्रेटरीज़ हैं, वे उनको डायरेक्ट इत्तिला करेंगे। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो...

**श्री सभापति** : अदीब साहब, थैंक यू।

**श्री मोहम्मद अदीब** : कहीं ऐसा न हो कि हमारी तानाशाही दबे पांव इस मुल्क पर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि हकीक़त यह है कि दुनिया ने यूरोप से लेकर हर जगह यह देखा है कि जम्हूरियत के नाम पर दबे पांव आकर कब्ज़ा हुआ है। इस खौफ के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब प्रैक्टिकल हो जाइए और ऐसी कोशिशें कीजिए...

**श्री सभापति** : थैंक यू अदीब साहब, प्लीज़ ... प्लीज़...**(व्यवधान)**...

**श्री मोहम्मद अदीब** : बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं:-

"हम हैं गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं,
अपनी कसरत पर न इतराओ, खुदा तुम भी नहीं।"

†[**جناب محمد ادیب (اتر پردیش)** : شکریہ جناب، میں جب پریسیڈینٹ صاحب کے ایڈریس پر یہاں بول رہا ہوں، تو میں نے پہلے اس کو پڑھا اور مجھے ایسا لگا کہ یہ بی-جے-پی- کے مینی-فیسٹو کا کوئی دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بی-جے-پی- کے لوگوں کو ابھی یہ یقین نہیں آیا ہے کہ یہ سرکار میں آ گئے ہیں، یہ ابھی الیکشن موڈ میں ہیں، جبکہ ان کے سہیوگی، میڈیا اور کارپوریٹ سیکٹر تو سمجھ گئے ہیں کہ یہ سرکار میں ہیں۔ اس میں تو آپ نے اس طرح کے وعدے کئے ہیں کہ آسمان لے آئیں گے، تارے زمین پر دے دیں گے، سورج لے آئیں گے۔ آپ کے لئے تو یہ ایسا وقت تھا کہ آپ کچھ کرکے دکھاتے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایسا کچھ آئے گا، آپ بتائیں کے آپ ایسا کیسے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف خواب بیچ کر آئے ہیں، اس میں ذمّہ داری ان لوگوں کی بھی ہے، جو آج ادھر ہیں۔ ان کے قعلے کو توڑنے کے لئے یہ کہا گیا کہ ایک لاکھ پچھتّر ہزار

†[Transliteration in Urdu Script.]

کروڑ روپیہ کھا لیا گیا۔ TRAI کے ایک چیئرمین صاحب نے 66 ہزار کروڑ اور کتنے لاکھ کا کہا۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک، غریب سے لے کر جوان تک سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ سرکار پیسے کھا گئی۔ جس آفیسر نے یہ پروگرام بنایا اور کہا کہ یہ آکشن نہیں ہوگا، فرسٹ-کم-فرسٹ-سروڈ بیسس پر ہوگا، وہ آج کیبنیٹ سکریٹری بنایا جاتا ہے اور قانون کے خلاف بنایا جاتا ہے، آرڈیننس لاکر بنایا جاتا ہے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے، تو ہندوستان میں کبھی کسی ایک بیوروکریٹ کے لئے آرڈیننس نہیں لایا گیا۔ اس وقت جس منسٹر نے یہ کیا، وہ تو جیل پہنچ گیا۔ میں جب اس پر سوچتا ہوں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور تھا۔ یہ جو ایک لاکھ پچھتّر ہزار کروڑ کی کہانی تھی، وہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سرکار کی نیو اکھاڑ دی گئی۔ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک سازش کے تحت ہوا تھا۔ آج وہ آفیسر کیبنیٹ سکریٹری بنتا ہے اور قانون کے خلاف، کیوں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ نوکری نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس کے لئے آرڈیننس لایا گیا۔ ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے۔

سر، یہ کہا گیا کہ ہم گھر-گھر میں بجلی پہنچائیں گے، کیسے پہنچاؤگے؟ جو ندیاں ہیں، وہاں تو سلٹنگ ہو گئی ہے، ہائیڈرو پاور کم ہو رہا ہے اور جو کوئلے سے لاؤگے، تو وہاں تو کوئلے کا گھوٹالہ ہو گیا، آکشن ہوگا۔ اب کوئلہ کتنے کا خریدا جائے گا، بجلی کتنے کی لائی جائے گی؟ ایک اور طریقہ تھا کہ اٹامک انرجی لائی جائے، تو اس وقت کہا گیا کہ امریکہ کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ادھر سے ادھر پہنچے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کے ہاتھوں اب آپ کتنا بکیں گے؟ آپ یہ طریقہ کار بدلئے۔ اب آپ بتائیے کہ بجلی

کہاں سے لائیں گے؟ چونکہ جب آپ بجلی لائیں گے، تبھی آپ گھر-گھر کو دیں گے۔ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے فارن افیئرس پر بات کی گئی تھی۔ اب نواز شریف صاحب تشریف لائے، ہم بے پناہ خوش ہوئے۔ ہم نے سوچا جب نواز شریف صاحب آئیں گے، تو داؤد ابراہیم بھی پیچھے ہتھکڑی لگائے چلا آرہا ہوگا، حافظ سعید بھی آرہے ہوں گے، وہ لوگ، جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کے قتل کئے تھے، ان کے کٹے ہوئے ہاتھ آرہے ہوں گے، مگر پتہ لگا کہ یہ تو نہیں ہوا بلکہ کچھ شالیں ایک دوسرے کو دی گئیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو پیسے بھیجے گئے۔ یہ کیا سیاست ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ جس وقت منموہن سنگھ جی نے یہ کہا، میں اس بات کا گواہ ہوں، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تعلّقات ٹھیک ہو جائیں، تو کہا گیا کہ گردنیں چاہئیں۔ کیا اس سیٹ سے اٹھ کر اس سیٹ پر جانے کا الگ نظام ہوتا ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، نقوی جی نے بھی یہ کہا، بہت خوب بات کہی، میرے دل میں جگہ بن گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس ملک کا مسلمان آج بھی مشتبہ اور مشکوک ہے۔ داڑھی اور ٹوپی والے پکڑے جاتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ میرے بھائی نے میرے درد کو محسوس کیا، لیکن آئی۔بی۔ کا وہ آفیسر، جس نے یہ پلان کیا تھا کہ مسلمان نوجوان، بچے جیلوں میں جائیں اور پکڑے جائیں، تب دس سال کے بعد عدالتوں نے ان کو باہر کیا، آج اسی آفیسر، اجیت ڈووال کا دوسرا اپائنٹمینٹ ہوا اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گیا۔ اس سے ہمارے دل کو دھکّا ضرور لگا۔

سر، ہماری بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہیں مائنارٹی افیئرس کی بات کرنے کے لئے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مائنارٹی افیئرس کو قائم رکھا گیا ہے اور یہ بات بار-بار کہی جا رہی ہے کہ "ایکسکلوسیو گروتھ" کریں گے، سب کو لے کر آئیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بالکل ایسی ہی کہ ریس کے گھوڑے اگے اور

تانگے کے گھوڑوں کے ساتھ دوڑائے جائیں گے، اس لئے کہیں گے کہ آپ کو دوڑانے کو دیا۔ جب اس سرکار کو یہ پتہ لگا کہ یہ جو گھوڑے ہیں، وہ اگلے اور تانگے کے گھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ان کے لئے کچھ پروگرام لانے گئے، ان پروگراموں کا کیا ہوگا، آپ ختم کریں گے یا رکھیں گے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، "ایکسکلوسیو گروتھ" پر بحث ہے۔ جب یہ بات سمجھ لی گئی کہ اس ملک میں ہم کمزور ہیں، اس کے لئے یہ اسکیم لانی گئی، اس پر خاموشی ہے۔ کہا گیا - آتنک-واد کو، ٹیریرزم کو روکیں گے۔ آج ایک انجینئر پونے میں شہید کیا گیا۔ وہ پرائم منسٹر، جس کے پاس ایک ٹیم ہے ٹونٹر چلانے کی، تو انگلیاں تو چلتی ہیں، لیکن آج تک کوئی انگلی اس بات پر نہیں آئی کہ اس نوجوان بچے کا قصور کیا تھا، سوائے اس کے کہ داڑھی تھی اور ٹوپی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایس۔آئی۔ٹی۔ بنائیں گے۔

**شری سبھا پتی** : پلیز کنکلوڈ کیجئے۔

**جناب محمد ادیب** : سر، دو منٹ دے دیجئے۔

**شری سبھا پتی** : دو منٹ نہیں۔

**جناب محمد ادیب** : حضرت، آپ نے سات منٹ کا ٹائم دیا تھا، میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ ایس۔آئی۔ٹی۔ کے لئے کہا گیا کہ ایس۔آئی۔ٹی۔ باہر سے پیسہ لے کر آئے گی۔ میرے عزیزو، صرف این۔سی۔آر۔ میں جو روز رجسٹری ہوتی ہے، کروڑوں روپے کا بلیک منی بنتا ہے، اس کے لئے آپ نے کیا فارمولہ بنایا ہے، ذرا یہ بھی تو بتائیے۔ اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ ایس۔آئی۔ٹی۔ بنے گی، باہر سے کالا دھن لایا جائے گا، یہ خواب اب مت دکھائیے۔ اس لئے نہ دکھائیے کہ ہمیں کچھ خوف ہے، کچھ ڈر ہے۔

آپ کے ایجنڈے میں خوشی کی بات ہے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کے جو تین ایجنڈے ہیں، جو تین جھنجھنے ہیں، ان کو کم سے کم آپ نے پریزیڈینٹ کے ایڈریس میں نہیں کہا۔ ایک ہے یونیفارم سول کوڈ، دوسرا رام مندر اور تیسرا دفعہ 370 ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ ان کو کب-کب بجائیں گے، کب-کب ووٹ لینے کے لئے بجائیں گے، اس کو بھی ذرا کھل کر کہہ دیجئے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔

**شری سبھا پتی** : ادیب صاحب، شکریہ، تھینک یو۔

**جناب محمد ادیب** : ہمارے تیواری جی نے جو ایک بات کہی، وہ بات کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب منسٹر نہیں، اب جو سکریٹریز ہیں، وہ ان کو ڈائریکٹ اطلاع کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو---

**شری سبھا پتی** : ادیب صاحب، تھینک یو۔

**جناب محمد ادیب** : کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تاناشاہی دبے پاؤں اس ملک پر قبضہ کر لے، کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے یوروپ سے لے کر ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ جمہوریت کے نام پر دبے پاؤں آکر قبضہ ہوا ہے۔ اس خوف کے ساتھہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پریکٹکل ہو جائیے اور ایسی کوششیں کیجئے---

**شری سبھا پتی** : تھینک یو ادیب صاحب، پلیز --- پلیز--- ---(مداخت)---

**جناب محمد ادیب** : بس ایک شعر کے ساتھہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں:

ہم ہیں غدّار، تو پابندوفا تم بھی نہیں
اپنی کسرت پر نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں ]

**श्रीमती रजनी पाटिल** (महाराष्ट्र) : सर, संसद के केंद्रीय सभागार में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ, उसके संबंध में राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करने और अपने सुझाव देने के लिए मैं यहां खड़ी हुई हूं। वास्तव में मुझे बहुत सारे मुद्दों पर बोलना था, लेकिन हमेशा की तरह आपने हमें तीन-चार मिनट तक ही सीमित कर दिया है। इसलिए बाकी सब मुद्दों को छोड़कर जो दो मुद्दे मुझे लगते हैं कि यहां नहीं बोले गए हैं, उनके बारे में मैं यहां बताना चाहूंगी।

सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो दो मुद्दे बोले गए, उनमें से एक "डिजिटल इंडिया" है, जिसका ज़िक्र हुआ। सोशल मीडिया की आजकल बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन मैं आपके द्वारा यह बताना चाहती हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुणे में जो हादसा हुआ, महाराष्ट्र में कई हादसे हुए, उन हादसों पर कहीं पाबंदी लगाने की आवश्यकता है, जिसका ज़िक्र अदीब साहब ने अभी-अभी किया। मुझे लगता है कि अगर ट्विटर पर या फेसबुक पर हमारे महापुरुषों की फोटो डालकर उनकी निन्दा-नालस्ती की जाती है और उसके ऊपर अगर हमारे यहां दंगे-फसाद होते हैं तो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जो समाज इस तरह से फोटो डालकर, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके हमारे बीच में दूरियां पैदा करना चाहता है, उनके ऊपर हमें पाबंदी लगाने की आवश्यकता है और उसके मुताबिक कानून बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, सबसे प्रमुख बात, जिसके बारे में बात करना, मैं समझती हूं कि मेरा कर्त्तव्य है, वह यह है कि हिन्दुस्तान की आधी आबादी, जो पचास प्रतिशत महिलाएं हैं, उनकी निगाहें इस सदन और लोक सभा की ओर लगी हुई हैं, जिसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनकी सरकार ने हमें वचन दिया है कि महिला आरक्षण बिल को वे पारित करेंगे। उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि हमारी नेता, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राज्य सभा में तो यह बिल पारित हो गया था। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया और उसी के तहत इस देश की 33 प्रतिशत महिलाएं पंचायती राज के माध्यम से राजनीति के प्रवाह में शामिल हो गयीं। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि इस देश में जो 30 लाख लोग चुनाव लड़ते थे, उन 30 लाख लोगों में से बहुत कम महिलाएं यहां पर चुनाव लड़ सकती थीं। श्री राजीव गांधी ने जो पंचायती राज का बिल पारित किया, उसके माध्यम से 30 लाख में से 10 लाख महिलाओं के लिए राजनीति के मुख्य प्रवाह में शामिल होने का काम शुरू हो गया और उसके बाद हाल ही में 33 का 50 प्रतिशत करने का काम अभी हमारे देश में हो रहा है, जिससे महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में राजनीति में आ सकती हैं। जो आरक्षण का मुद्दा है, उसके बारे में मैं अभिनंदन करना चाहूंगी, लेकिन उसी के साथ यह बताना चाहूंगी कि सन् 1996 में मेरा लोक सभा की सदस्य होने का अनुभव है। आपमें से कई लोग उस समय लोक सभा में थे। जब पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा लोक सभा में चर्चा के लिए आया तो लोगों ने भाषण करने शुरू कर दिए, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:।" हमें लगा कि बहुत अच्छा हुआ, हम सब महिलाओं को बहुत बड़ा महिला आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यहीं सेंट्रल हॉल में जाकर हमारे भाई लोग बोलते थे कि आप पागल हो गयी हैं क्या? हम आपको आरक्षण नहीं देने वाले हैं। इस तरह की बातें हमें सुननी पड़ती थीं। यह जो

महिलाओं के प्रति सीक्रेट डिसक्रिमिनेशन होता है, इसका पता भी नहीं चलता। यह डिसक्रिमिनेशन कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए, यह मानसिकता बदलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सुमित्रा महाजन जी का बहुत बड़ा अभिनंदन किया, वे अब लोक सभा की स्पीकर हो गयी हैं। हम भी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में, आज की तारीख में भी अगर हम समझते हैं कि आज हमारे भारतवर्ष की, हमारे देश की महिला सुरक्षित है, सम्मानित है, तो वह कहीं न कहीं हमारी गलतफहमी है। क्या आज भी ऑनर किलिंग की घटनाएं नहीं हो रही हैं? आज भी हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मायावती जी ने बदायूं का जिक्र किया। वहां पर दो लड़कियों का बलात्कार करके पेड़ पर टांग दिया गया। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं और जिनका जिक्र बान की मून जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। हमारे लिए वह बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज भी जन्म से पहले 7 लाख लड़कियों को मांओं की कोख में ही मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो महिलाओं के लिए गौरवास्पद नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर पुरुष मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है तथा जो डिसक्रिमिनेशन चल रहा है, उसे कम करने की आवश्यकता है।

महोदय, सिर्फ दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी और आपके लिए टाइम बेल बजाने की स्थिति नहीं आने दूंगी। मैं केवल दो पंक्तियां कहूंगी जो, हमारे देश की महिलाओं की भावनाएं हमारे देश के भाइयों के प्रति हैं, उनको व्यक्त करती हैं:-

"न किसी को गिराया, न खुदी को उछाला,
कटा ज़िंदगी का सफर धीरे-धीरे।
जहां पहुंचे आप, छलांगे लगाते,
वहां पहुंची मैं भी, मगर धीरे-धीरे।"

हम धीरे-धीरे बन जाएंगे। यहां पर भी 33 प्रतिशत पर आएंगे और लोक सभा में भी 33 प्रतिशत पर आएंगे, धीरे-धीरे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। यही कहते हुए, इस उम्मीद के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, उनकी नेक-नीयती साफ हो और वे सब वायदे वे पूरे करें, उसके लिए हम अपने दिल की गहराइयों को उनको शुभेच्छाएं देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Prem Chand Gupta.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, we are regional parties. We have to speak for five minutes. This is not fair. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One of your colleagues is listed to speak.

SHRI NARESH GUJRAL: But, Sir, the Prime Minister is supposed to speak in ten minutes. So, I hope we will get time.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, the BJD won 20 out of 21 seats in the Lok Sabha elections.

MR. CHAIRMAN: You are listed to speak. Now, Prem Chand Gupta ji.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण हुआ, उसके ऊपर सभी पार्टियों ने इस अगस्त हाउस में चर्चा की। सभापति जी, मैंने भाषण सुना भी और मैंने पढ़ा भी। उसको सुनकर और पढ़कर ऐसा लगा कि हमारे साथी लोगों का जो इलेक्शन मेनिफेस्टो था और इनके नेताओं ने जो इलेक्शन मीटिंग्स में भाषण किए, उसका एक प्रतिबिम्ब है।

श्रीमान् जी, वायदे करना एक अलग चीज़ है, सपने दिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको जमीन पर उतारना, उनको हकीकत में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, हमारे साथी डा. हर्षवर्धन यहां पर बैठे हैं, दिल्ली मैं विधान सभा के चुनाव थे और वहां पर कुछ एनजीओज़ के लोगों ने देश की जनता, दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया कि हम आपको चांद-सितारे देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पक्के मकान फ्री देंगे। इस तरह के वायदे करके और इस तरह के सुनहरे सपने दिखा कर आपकी सरकार को नहीं बनने दिया। हर्षवर्धन जी, आप उसके विक्टिम हैं और मेरी आपके साथ इस बारे में sympathy है।

श्रीमान् जी, यही वायदे आपने अपने मेनिफेस्टो में किए हैं, आपने अपनी इलेक्शन मीटिंग्स में किए हैं, राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें भी यही वायदे किए हैं। आपने कहा कि हम सब को पक्के मकान दे देंगे। पहले आपने कहा कि मुझे 60 साल के मुकाबले में 60 महीने का समय चाहिए। अब आपने 2022 की बात करनी शुरू कर दी है। आपने कहा कि हर घर में बिजली देंगे, हर घर में पानी देंगे, 100 नये शहर बसायेंगे। मान्यवर, जो शहर बसे हुए हैं, उनमें पानी नहीं है, उनमें बिजली नहीं है, उनमें सड़कें नहीं हैं, उनमें कोई यातायात का साधन नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम 100 नये शहर बसा देंगे। क्या चांद पर बसा देंगे? कैसे बसा देंगे? श्रीमान् जी, आपने कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। श्रीमान् जी, आपको ध्यान होगा कि जिस रोज़ इनकी सरकार बनी उसके दो रोज़ के अंदर डीजल की कीमतें 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गईं और कल हम टेलीविजन पर देख रहे थे और अखबारों में भी आया कि आप डीजल की सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आप जानते हैं कि डीजल का उपयोग खाली SUVs ही नहीं करतीं, हमारे लाखों, करोड़ों किसान भाई भी डीजल का उपयोग करते हैं क्योंकि सरकार बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए किसान डीजल का उपयोग करते हैं। अगर आप डीजल के भाव बढ़ा देंगे, तो उससे किराये बढ़ेंगे, उससे हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी, आप जो यह बोल रहे हैं कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, उसको आप कैसे करेंगे?

श्रीमान् जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सिर्फ गंगा जी की सफाई के बारे में कहा गया है। आप यमुना को भूल गए, आप कावेरी को भूल गए, आप देश की दूसरी नदियों को भूल गए। श्रीमान् जी, आप जानते हैं कि गंगा जी की सफाई के मामले में हम सब आपके साथ हैं। करोड़ों लोगों की आस्था गंगा जी की सफाई के साथ जुड़ी हुई है। हर हिन्दू चाहता है कि उसके अस्थिकलश

**5.00 P.M.**

के फूल गंगा जी में प्रवाहित किए जाएं। आप लोगों को इस तरह के वायदे नहीं करने चाहिए जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते हैं।

श्रीमान् जी, आपने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है। इस वक्त देश में 22 करोड़ नौजवान हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। हर साल दो करोड़ नये नौजवान तैयार होते हैं, जिनको रोज़ी-रोटी के लिए काम की जरूरत है और उनको यह मालूम नहीं है कि वे क्या काम करेंगे। उनके मां-बाप कर्ज लेकर उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से इन सब बिंदुओं के समाधान के बारे में आपने कुछ नहीं बतलाया है। श्रीमान् जी, आपने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाऐंगे। आप बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे? बुलेट ट्रेन के लिए एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन चाहिए होती है और उसको दोनों तरफ से कवर करना पड़ता है। आप इस बात को समझते हैं, आप चाइना भी गए थे, हांगकांग भी गए थे। आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेने के लिए दोनों तरफ कॉरिडोर बनाना पड़ता है, ऐसे बुलेट ट्रेन नहीं चलती है।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : प्रेम चन्द जी, आपका टाइम खत्म हो रहा है।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : मेरा टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आपके हिस्से का टाइम।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं कि मेरा समय खत्म हो, मेरे साथी नहीं चाहते कि मेरा समय खत्म हो।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आपके हिस्से का टाइम।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : श्रीमान् जी, अगर मेरे मित्र चाहते हैं कि मेरा समय खत्म हो तो एक्सेप्ट करता हूं। आप मुझे सिर्फ दो-तीन मिनट और दे दीजिए।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप घड़ी देखिए।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : श्रीमान् जी, आज मेरी मेडन स्पीच है और मैं इसमें 20 मिनट का इनटाइटल्ड हूं।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : आप किसी और वक्त कीजिएगा, आज के शैड्यूल पर यह मुमकिन नहीं है। प्लीज़, यह रिक्वेस्ट है।

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : सर, यह मेडन स्पीच का जो मेरा राइट है, इसको रिजर्व रखा जाए और मुझे दो मिनट या तीन मिनट का समय और दे दिया जाए।

श्रीमान् जी, जो सपने दिखाए गए थे, उसमें डा. हर्षवर्धन उसके शिकार हुए। आपने अभी केन्द्र में सरकार बनाई है, तो आपको इसके बारे में सीरियसली विचार करना होगा। श्रीमान् जी, अभी सदन में लीडर ऑफ दि हाउस नहीं हैं। श्री अरुण जेटली हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमारे साथियों पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि हमने अपने अलाइन्स पार्टनर्स को कभी भी बर्डन नहीं

[श्री प्रेम चन्द गुप्ता]

माना है। श्रीमान् जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये किस अलाइन्स पार्टनर्स की बात करते हैं? अगर आप फरवरी माह की लास्ट हाउस प्रोसिडिंग्स निकालकर देखें, तो जिन अनाइन्स पार्टनर्स के ऊपर ये गर्व महसूस कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह और किस लैंग्वेज में इनके नेताओं को गालियां दी थीं। यह बात देखने लायक है।

श्रीमान् जी, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी देखने वाली बात है। एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था। हम लोगों को जनरल मुशर्रफ ने इन्वाइट किया था। हम उस डेलीगेशन में वहां पर गए थे। जब जनरल मुशर्रफ ने डेलीगेशन के लोगों से मिल रहे थे, सबको सलाम कर रहे थे और पाकिस्तान का मीडिया भी सब देख रहा था तो जिन अलाइन्स पार्टनर्स की ये बात कर रहे हैं, जब जनरल मुशर्रफ उनको पास करके आगे चले गए तो इन्होंने दूर से कहा, जनरल साहब, हम वही सो एंड सो हैं, मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वरना मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप सब लोग समझ जाइए। उन्होंने कहा कि हम वही हैं, जिन्होंने गोधरा और गुजरात के दंगों को लेकर, वाजपेयी सरकार में मंत्री पद की कुर्सी को ठोकर मारी।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : श्रीमान् जी, मैं अरुण जेटली साहब को बोलना चाहूंगा कि उनको ऐसे अलाइन्स पार्टनर्स के ऊपर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please conclude.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : ये वे अलाइंस पार्टनर्स हैं, जो सत्ता के लिए इधर से उधर भी आ सकते हैं और उधर से इधर भी जा सकते हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अठावले** (महाराष्ट्र) : वे आपके साथ भी थे।...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : हां, वे हमारे साथ भी थे।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. No discussion on this. ...*(Interruptions)*...

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : मैं अपनी बात कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**... वे हमारे साथ भी थे।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Prem Chandji, please conclude. ...*(Interruptions)*... No, no. Please. ...*(Interruptions)*... No cross-talks, please. Please conclude now. You can't go any further.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : सिर्फ एक मिनट और...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, I am afraid, not. I am afraid, not.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : सर, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I will call the next speaker.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : मैं अरुण जेटली साहब को इस बारे में आगाह और सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे अलाइन्स पार्टनर्स से जरा ध्यान से रहें।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Prem Chandji. Thank you very much.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : वे क्या कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं, किधर आ सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। श्रीमान् जी, समय बहुत क्रिटिकल है...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I will call the next speaker. Please cooperate.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : मैं अंत में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरह का गर्व मत कीजिए। गर्व करना या जो अहंकार है, वह इंसान के या किसी भी पार्टी के गिरने का सबसे बड़ा कारण बनता है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : देश इस वक्त बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है।...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मैं बस एक मिनट लूंगा...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. Why are you constantly...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Just one minute, Sir. आज भी अखबारों में देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा गर्व है, जिसका संसार में नाम है...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, you are now pushing it beyond...

**श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : ...उसको छोटी-छोटी कंट्रीज़ ने Letter of Intent एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री साहब से कहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत ही सीरियस चीज़ है। श्रीमान् जी, मैं इसके साथ ही आपका और अपने साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने...**(व्यवधान)**... मेरी बात को सुना। धन्यवाद।

**श्री रामदास अठावले** : सभापति महोदय, मैं लोक सभा में तीन बार रहा हूं, लेकिन यहां आपके हाउस में पहली बार आया हूं। मुझे यह गर्व है कि भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, जो उस संविधान के शिल्पकार थे, जिस संविधान पर यह देश चल रहा है। सभापति महोदय, यहां सत्ता में कोई भी आए, उनको संविधान के मुताबिक ही आगे चलना है। यहां सामने वाले लोग जरूर बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करता था, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया था।

सेकुलरिज्म की जो बात है, वह सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर हमने भारत का संविधान स्वीकारा है और यदि नरेन्द्र मोदी जी भारत के संविधान को लेकर आगे चलने की बात करते हैं तो वहां यह सेकुलरिज्म उस संविधान में है। पार्टी का एजेंडा अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि यहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, ईसाई भी है, तुम भी हो और हम भी हैं। हम सभी लोग

[श्री रामदास अठावले]

मिलकर देश को चला रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों को यह मौका मिला है। मैं इधर नहीं आता था, आप लोगों ने मुझ पर बहुत अन्याय किया है। ठीक बात है, आने की बात नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है। यह बात ठीक है कि जब मैं आपके साथ था, तब कुछ मुद्दों पर मतभेद थे, अगर मैं इनके साथ हूं और हमारी पार्टी अलग है तो जरूर उन मुद्दों पर भी मतभेद होगा। अगर मुद्दों पर कुछ मतभेद न हो तो एक ही पार्टी होनी चाहिए। एनडीए की 29 पार्टियां अभी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को 282 का अच्छा मेंडेट मिला है। बीजेपी के दो लोग ही 1984 में थे। जब मैं लोक सभा में था तब मुझे बोलने के लिए केवल दो-तीन मिनट ही देते थे और मैं अध्यक्ष जी का आदेश सुनता नहीं था, लेकिन मैं आपका आदेश सुनूंगा। मैं रिपब्लिकन पार्टी का लोक सभा में अकेला सदस्य था, इसलिए मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता था। मैं यहां भी अगर इस हाउस में आया हूं तो भारत को बलवान बनाने के लिए आया हूं। मैं यहां सभी हिंदू-मुसलमानों को जोड़ने के लिए आया हूं, मैं यहां दलित और हिंदुओं को जोड़ने के लिए आया हूं। हमें यह झगड़ा खत्म करना है। अगर नरेन्द्र मोदी जी चाहते हैं कि झगड़ा खत्म करना है तो आप क्यों झगड़ा लगा रहे हैं? वे ऐसा चाहते हैं और यह बात भी ठीक है कि यह बीजेपी का एजेंडा होगा। अगर देश में सर्वधर्म-समभाव की भावना है तो जिनको राम मंदिर बनाना है, वे राम मंदिर बनाएं, जिनको मस्जिद बनानी है, वे मस्जिद बनाएं, जिनको बुद्ध मंदिर बनाना है, वे बुद्ध मंदिर बनाएं। संविधान ने सबको यह आजादी दी है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहां हमारे बीच में विवाद पैदा मत करो, क्योंकि अपने देश का भला होने वाला है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि,

"राज्य सभा में आया हूं मैं पहली बार
और कांग्रेस की देख रहा हूं बुरी हार।"
यहां सुरक्षित नहीं है देश की नार,
इसलिए एनडीए आई है सत्ता में इस बार।"

हम लोग आए हैं, ठीक बात है। अगर आप लोग बोलते हैं कि इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया, तो क्या आपके पास पैसा नहीं था? आप लोग बोल रहे हैं कि भाई नरेन्द्र मोदी ने इतना पैसा खर्च किया। पूरा पैसा तो आपके पास ही था, पूरे कारखानेदार आपके पास थे, तो आप इधर क्यों आए? इनको लगा था कि बाद में ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं। पैसे की बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी बीजेपी-शिवसेना-आरपीआई का गठबंधन था और देश भर में बीजेपी और एनडीए ने लोगों में ऐसा वातावरण तैयार किया। महंगाई बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, दलित पर अत्याचार बढ़ गए थे, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। आपने इनके ऊपर काम क्यों नहीं किया? सरकार आपकी थी। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आकर टू-थर्ड मेजोरिटी से महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय कर सकते थे। जब मैं लोक सभा में था, तब मैंने महिलाओं के आरक्षण को सपोर्ट किया था। समाजवादी पार्टी वाले विरोध कर रहे थे, ठीक बात है, उनको विरोध करने दीजिए। लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी मिल कर टू-थर्ड मेजोरिटी हो जाती, तो महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय होना चाहिए था। महिलाएं, आप उधर क्यों बैठी हैं? आप बैठिए,

मगर मुझे लगता है कि अभी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को मान्य करना होगा। अगर उनको 33 परसेंट रिजर्वेशन देना है, तो जब मैं लोक सभा में था, तो मैंने मांग की थी कि लोक सभा की 545 सीटें हैं, जिसमें 543 इलेक्टेड सीटें और 2 एंग्लो-इंडियन की सीटें हैं, आप 181 सीटें महिलाओं को दीजिए। लोक सभा को सेंट्रल हॉल में रखिए और इसमें 181 सीटें बढ़ाइए। आप बड़े एडवोकेट हैं, आपको पूरा कानून मालूम है। इसलिए 543 में और 181 सीटें बढ़ा कर लोक सभा को सेंट्रल हॉल में रखिए। हमारी राज्य सभा की सीटें कम हैं। सभापति महोदय, जब मैं इधर आया, तो मुझे यह सभागृह एकदम छोटा लग रहा था। इसलिए मैंने यह सोचा कि इसमें और 100 सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें सीटें बढ़ा कर इस हाउस को लोक सभा में ले जाना चाहिए। इसलिए महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को हमें मान्य करना चाहिए।

दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त कीजिए। देखिए, समय बहुत कम है।

**श्री रामदास अठावले** : प्राइम मिनिस्टर को आने दीजिए, उनके आने तक मैं बोलता हूं।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं। अभी और सदस्य बोलने वाले हैं। आपके बाद आपके पड़ोसी भी बोलने वाले हैं। आप समाप्त कीजिए, प्लीज़।

**श्री रामदास अठावले** : ठीक है। अपनी पार्टी से मैं अकेला हूं, लेकिन एक बात है, मैं हमेशा अकेला ही होता हूं। मैं उधर भी था, तो अकेला ही था, इधर भी हूं, तो अकेला ही हूं।...**(व्यवधान)**... यह मेरी मेडन स्पीच तो है ही।

मुझे लगता है कि अभी हम सब मिल कर काम करेंगे। यहां हमारे सोशलिस्ट्स हैं कम्युनिस्ट्स हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, टीडीपी है, हमारी आरपीआई है, बीजेपी है। हम सब लोग मिल कर इस हाउस को चलाएंगे। मनमोहन सिंह साहब भी इधर हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी भी इधर हैं, शरद पवार साहब भी इधर हैं। ...**(समय की घंटी)**... पवार साहब के साथ तो हम हमेशा रहे, बहुत सालों तक रहे, लेकिन दो-ढाई सालों से कांग्रेस-एनसीपी को छोड़ कर मैं इधर चला आया, क्योंकि मुझे शिरडी में खड़ा किया गया था और उधर मैं हार गया। सभापति महोदय, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : अब आप बैठ जाइए।

**श्री रामदास अठावले** : मैं 8-ए, लोदी इस्टेट में रहता था। जब मैं 2009 में चुनाव हार गया, तो दो महीने के अंदर मेरे पूरे घर का सामान बाहर निकाल दिया गया था।

**श्री सभापति** : श्री ए.वी. स्वामी।

**श्री रामदास अठावले** : इसलिए मैंने सोचा था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालूंगा और उनको निकाल कर मैं इनके साथ आया हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में जो मुद्दे आए हैं, हमारी सरकार उनको इम्प्लिमेंट करेगी। आप चिन्ता मत करिए, हम अभी 5 साल रहेंगे, 5 सालों के बाद और 5 साल रहेंगे तथा 5 सालों के बाद और 5 साल रहेंगे। बाद में देखते हैं। इसलिए मैं इस अभिभाषण को पूरा सपोर्ट करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

SHRI A.V. SWAMY (Odisha): Sir, I have a soar throat. In spite of that, I will make an attempt. Thank you very much for giving me this opportunity. I have been hoping that this time when I am going to hear the speech of the President, I will get a fresh and a new insight. For the last 60 years, I have been listening the same old story of how to remove poverty, how to stop violence and all that. This time, when I heard the speech of the President, I was rather taken aback to see that there was nothing new. It was conventional. It became a conventional type of speech and, therefore, I was a bit disappointed. But some of the slogans were given. In one of them, that is, 'minimum government and maximum governance' because of my own background, it appeared to me that the focus is more on dissolving centralised power and extending it to five-and-a-half lakh villages, which Gandhiji conceived of. That was my perception of 'minimum government and maximum governance'.

I have been working for the poor people for the last 60 years. I know what has happened. Despite majority of the programmes, that were initiated by Government or voluntary agencies, and I have done it on my own, still we are removing poverty. What is the reason? Our perception of poverty will have to change now. We have been thinking of poverty as merely giving some sort of an elevation. Somebody says it poverty alleviation; somebody says it poverty elimination, but the poverty is a State of powerlessness. You will find that sometimes, even a rich man is addressed as a poor man. That means, he is brought into a state where he cannot help himself. What are the components that give power or bring him up? Those three components happen to be — political, economic, and third and the most important is social. The three components to eliminate the state of powerlessness of the poor are drawn from his social power, that is, the status that he occupies within the society, the minimum economic resource that he has, and also the education that he gets.

Mr. Chairman, Sir, our efforts over the past 60 years about elimination of poverty have been devoid of these three components of supplying that power so that poor people can get their due. This is like tripod. If you give one of the legs, like you give some economic power, but you do not give the political and also the social power, the status in the society, it will fall like a tripod. Therefore, whatever efforts we have made over last 60 years, we have been able to give only one or two of these components and not in totality.

Mr. Chairman, Sir, I have 60 years of experience of Naxal areas. The area in which I am working now has become a naxalite area. Let me tell you that area is Koraput district, bordering Andhra Pradesh and also Chhattisgarh.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.V. SWAMY: I will do that, Sir.

MR. CHAIRMAN: We are very hard pressed for time. Please co-operate.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, naxalism is being looked at as a problem of uprising which can only be solved by gun to gun, and, if somebody gets up, use of police force has been the strategy of the Governments so far. But, the problem has accelerated. What is the cause of naxalism? Sir, hon. Prime Minister is here. He should know more about that area as to how actually naxalism could ever come there.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, let the area be known. That is the area where maximum amount of people have sacrificed their lives for freedom struggle. That is the area where people have responded to Gandhi and Vinoba's call of *Gramdan* and *Bhoodan*, and, made great sacrifices.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please conclude now. I have to call the next Speaker. Please.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, give me two minutes more.

MR. CHAIRMAN: I am sorry, I don't have two minutes. You need to conclude. Please understand the situation.

SHRI A.V. SWAMY: What I would like to say in one sentence is that violence against the naxalite will not stop naxalism, and, therefore, you must try to bring about a sort of dialogue with them, and, they have been done injustice by depriving them of their land and their rights.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Baishnab Parida.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in this historic discussion. Sir, the elections are over and the Indian democracy has proved its strength and depth before the world and it has shown that the greatest democracy can survive and prosper, and the country can solve its problems through the democratic methods.

But, Sir, many of my friends have glorified these elections. I also agree with them but there are certain black aspects of these elections. One of those aspects is the role of money. Democracy is based on free and fair elections. We have promised this and we accepted it in our Constitution. But with the role of money, liquor and allurement by the political parties has, I think, spoiled many of the achievements of these elections.

[Shri Baishnab Parida]

As per the Indian press, black money amounting to around Rs. 30,000 crores was spent in these elections. The Election Commission had fixed the expenditure limit of Rs. 28 lakhs for an Assembly constituency, and, Rs. 70 lakhs for a Parliamentary constituency. Can we, the Members who are sitting here, ask ourselves, have we obeyed this or have we observed this limit? How much money did we spend for an Assembly constituency, and, how much money did we spend for a Parliamentary constituency. Crores of rupees were spent; seven crores of rupees, ten crores of rupees were spent for a Parliamentary constituency. And, Sir, at some places, attempts were made to purchase the votes. The voters have not given massive consent or votes to our political parties or to us, Sir. This is the problem. If this goes on unhindered, if we do not introspect this thing, where will it lead the future of democracy? We are now having a very strong, resolute Prime Minister. Since his younger days to this House, he traveled for many decades and many miles, from Himalayan range to Nagpur to Gujarat. One thing he has shown all his life is his resoluteness, and I appreciate it. We have promised that we will eradicate corruption. Without curbing corruption, we cannot implement any programme, we cannot build up this country and we cannot bring ourselves out of the problems which the country is facing now. So, we promise the people that we will curb corruption. You have made promises with respect to black money and you have taken some steps also. I welcome that.

Another thing, Sir, which I want to bring to your notice is that we have promised in the President’s Address zero tolerance towards left wing extremism. One thing which I am saying and which many of my friends have also mentioned is that the right wing terrorism, taking some communal colour, is also raising its ugly head. That must be noticed and curbed at the proper time. Otherwise, it will create problem for you to bring this country together, bring social order and social peace.

Another thing which I want to say is you have proclaimed cooperative federalism. On behalf of my party, BJD, I welcome it and thank you that you have adopted that the federal structure must be strengthened and kept alive. But, in practice, the smaller States, the backward States, what are they doing? They are being deprived of their rights. One of my friends from Odisha has mentioned about this. Our hon. Prime Minister knows it. We met him along with our Chief Minister and brought to his notice as to how Odisha has been neglected by the Centre for decades together. We are contributing towards the national revenue. Our revenue contribution to the Railways is about Rs. 14,000 crores, but we are getting Rs. 800 to develop our railway infrastructure. The Railways projects which started some twenty years back are still

lying unfinished. This is why we are lacking in infrastructure and connectivity. The only airport is there in Bhubaneswar for the entire State.

MR. CHAIRMAN: Okay, thank you.

SHRI BAISHNAB PARIDA: It was promised that it would be made international airport, but till now nothing has been done.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Please conclude.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Just two minutes, Sir.

Another thing is regarding Polavaram Project. It is a disputed issue and the case is pending with the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN: There will be many occasions when you can discuss that. ...*(Interruptions)*... Please conclude that. ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Without consulting the stakeholders, how was the promulgation of the Ordinance done by this Government?

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, we are bringing it to your notice. This whole reality is also depending. So, I am bringing it to your notice. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, another thing ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, I am afraid ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, just one minute.

MR. CHAIRMAN: No more subjects, please.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Regarding this language, Sir, I congratulate you. Throughout your campaign, you used only Hindi language. I feel proud of it. Sometimes I am inspired to speak in Hindi. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, just one thing. I am requesting you to please help the regional language. Make it a digital language. That language must be used in the administration and in your business. ...*(Time-bell rings)*... I feel shy to tell you here that in Odisha, still English is the official language. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Kindly cooperate and conclude.

SHRI BAISHNAB PARIDA: I am requesting you to do it. Regarding Gandhiji's ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI BAISHNAB PARIDA: *

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BAISHNAB PARIDA: With this, I support the Motion of Thanks on the hon. President's Address. We wish you a bright future to serve this country.

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Otherwise, you will face the same problem as our friends sitting on the right side faced. I wish you all success. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Some hon. Members have graciously cooperated in withdrawing their names. I now call upon Shri Anand Sharma.

**श्री आनन्द शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल की तरफ से राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण और धन्यवाद ज्ञापन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सदन में और दूसरे सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। कल नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी। मेरे दल के वरिष्ठ साथियों ने, नेताओं ने और तमाम राजनैतिक दलों के नेताओं ने अपनी बात सदन में रखी। यह एक परंपरा है सदन की मर्यादा को रखने की, अपनी बात को कहने की, दूसरे की बात सुनने की। यह प्रजातंत्र की बुनियादी जरूरत है। इसका हर एक को समझना, स्वीकार करना और सम्मान करना आवश्यक है। तभी हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। चाहे कोई भी चुनाव जीत कर आए हैं या हम इस तरफ बैठे हैं, लोग हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन पर उनके सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। कल इस सदन में चर्चा हुई कि अभिभाषण में कहा गया है कि एक मेंडेट मिला है, जनमत मिला है, स्थिरता का जनमत मिला है, एक मजबूत सरकार का जनमत मिला है। हमने उस मेंडेट को, उस जनमत को विनम्रता से स्वीकार किया है। नेता सदन ने ठीक कहा कि सत्ता परिवर्तन होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, शांतिपूर्वक तरीके से होता है। आप वहां से यहां आए थे, हम यहां से वहां चले गए, 10 वर्ष के बाद हम यहां आ गए। यह परंपरा बनी रहेगी और यह टूटनी भी नहीं चाहिए। यही भारतीय प्रजातंत्र की एक शक्ति है और यही देश की एक सोच है। मुझे आपको एक चीज़ कहनी है कि जहां हमने इसको स्वीकार कर लिया है और हमें जो कहा गया कि कड़वाहट नहीं होनी

*Not recorded.

चाहिए, हमको बड़ी शालीनता से, गरिमा से इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। We are being told that we should not be bitter in defeat and we should accept it with grace. I was rather surprised. Arun Jaitleyji is a very respected and a learned Member of this House and a friend. I would like to remind them that these two words were somehow deleted from the memory when the courtesy and the special privilege of the Prime Minister to introduce his Council of Ministers was denied to Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister in 2004. It happened in this House. It was in this House that we were not allowed even to present the Budget or to have a discussion on the Budget. I can assure you we know how to be graceful in defeat. We know how to engage in constructive engagement. We know how to uphold the dignity of Parliament. We have also suffered. Both the Houses and the nation has witnessed when the Houses did not function and no business was transacted. This is not to say that I am suggesting कि जो परिपाटी आपने बनाई, उस पर हम चलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कल स्पष्ट कर दिया था कि हम सत्ता में रहे हैं, यह हमारे प्रजातंत्र की परिपक्वता है। आपने सही कहा कि this is the maturity of democracy. इसलिए जहां देशहित की बात होगी, जहां आपकी कोई नीति हिन्दुस्तान को मजबूत करने की होगी, हिन्दुस्तान के विकास की होगी, आम आदमी के विकास की होगी, जो हिन्दुस्तान की मजबूती लाएगी, हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखेगी, उसमें आपको हमारा रचनात्मक सहयोग मिलेगा।

कल कई बातें हुईं, जो कि अभिभाषण में हैं। मैं समय का ध्यान रखते हुए अपने आपको उन्हीं तक सीमित रखूंगा। The Leader of the House said something which, to my mind, was unfair. He said that in what state they had handed over the country and its economy to Dr. Manmohanji and the UPA in 2004 and that the GDP growth rate was 8.5 per cent. That's a fact on record. We don't deny. He asked what we have left in legacy and that we have left a shattered economy, we have left the country where the GDP has nosedived, where the investment cycle has been destroyed and investment climate has been vitiated. I was rather surprised. Let me put the record straight. Mr. Chairman, Sir, when the NDA left office and the UPA formed the Government, there were global tailwinds. The global economy was doing extremely well. During the first four years of this century, Atal Bihari Vajpayeeji was Prime Minister and the NDA benefited from the global tailwinds. Were we able to sustain? We did sustain for the next four years. Then the economic crisis came in 2008. All countries were affected. Any person having elementary knowledge of Economics knows that if an economic crisis is preceded by a financial crisis, that is more severe and difficult to overcome. The entire tenure of UPA-II was in the global headwinds and not tailwinds. From 2008 until now, the global economy has not lifted itself out of the crisis. The capital inflows were very weak. There is contraction in global

[श्री आनन्द शर्मा]

trade. But, let me now tell you and place on the record, for the benefit of the Members and through the media, which always plays an important role, as my learned friends on the other side know, because we have seen the kind of campaign which the world has taken note of – Congratulations! High decibel, high voltage, high technology, मैं तो दिल से बधाई दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने यह कर के दिखाया कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कैसे होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं कि एक ही समय में देश के 600 जगहों पर आपका भाषण जनता सुने। यह प्रजातंत्र है, आपकी यह सोच है, आपने यह दिखाया और हमने यह प्रचंड प्रचार तंत्र देखा। इसलिए मैं मीडिया से कहता हूं कि भाई, ज़रा हमारी बात को भी ग़ौर से सुनो, यह बैलेंस बने रहना चाहिए।

भारत की जी.डी.पी. 2004 में 590 बिलियन डॉलर थी। हमने क्या छोड़ा है? दो ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की जी.डी.पी. हमारी थी, जब पांच साल आर्थिक संकट है। गहरा संकट है, आप कहते हैं कि ऐवरेज ग्रोथ की बात मत करें। क्यों न करें ऐवरेज ग्रोथ की बात? आपकी ऐवरेज 5.9 थी। आप केवल अपने अच्छे दिन देखेंगे और दुनिया के संकट के दिन नहीं देखेंगे। हमारी ऐवरेज 7.6 प्रतिशत है। देश की पर-केपिटा इन्कम, माननीय नेता सदन ने कहा कि "We have elevated poverty". मैं बताता हूं। हिन्दुस्तान की पर-केपिटा इन्कम चौबीस हजार रुपए थी, जो 69 हजार रुपए हुई है। यानी तीन गुना बढ़ी है। मैं सारे विषयों पर नहीं कहता। भारत के फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व 110 अरब डॉलर था। हम 312 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़कर गए हैं, जबकि हमारे पेट्रोलियम का जो इम्पोर्ट होता है, देश में अगर आप उसको देखें, जो हमको खर्चा करना पड़ता है, जब आप सत्ता में थे, उसकी तुलना में 5 गुना ज्यादा तेल की कीमतों में उछाल आया है और पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में, हमको एक वर्ष में 180 अरब डॉलर पेट्रोलियम इम्पोर्ट का खर्चा करना पड़ा, लेकिन यह हम छोड़कर गए। मुझे आपको शायद यह भी बताना आवश्यक होगा कि आपने जो बात इकॉनोमी की कही, Mr. Chairman, Sir, through you, let me again inform this House that when the NDA Government left the office and the learned Leader of the House was my predecessor, I was in the same Ministry where I had the privilege and honour to serve this country for five years. India's exports stood at 63 billion dollars. When we left, mind you, there was 7 to 12 per cent contraction of the trade following the crisis, Indian exports was to the tune of 313 billion. This question was put to us that we have left the country in tatters and a shattered economy, which is not true. Rightly it has been said that the President's Address has been packed with slogans. Perhaps the mindset has not changed. The elections are over. People have voted. You have won. We have come to this side. We have accepted it and respect it. We have congratulated you repeatedly. But please stop the election slogans. Let us get down to serious business.

Shri Arun Jaitleyji has mentioned about the investment climate. Let me tell him that since 2003 India has received 327 billion dollars of the FDI, whereas during the NDA rule in 2002-04, 19.83 billion dollars of the FDI was received. More than 303 billion dollars of the FDI was received during the UPA-I and UPA-II Governments. During the period of UPA-II Government, the period of crisis, the FDI which came to India, was 205 billion dollars. This can't be denied. It is not that we have handed back nothing, and we were not a responsible Government, we were not a focussed Government, that we were not serious and sincere in serving our country. It is expected of every Government, the Prime Minister and Ministers to be true to their responsibility which we tried to do. We had an environment which made functioning difficult. I do not wish the same misfortune and the same climate to confront the new Government, the Prime Minister and his new team. We are responsible both as Members in the Opposition and as citizens of this great Republic of India. We will do everything which is in the interest of democracy and in the interest of this country. Sir, on poverty alleviation, I must congratulate our leader, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, and the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, for giving to us policies where citizen's rights and entitlements were recognized and respected and where democracy was empowered. If you look at the steps that we took, the social security net was strengthened. When it comes to spending, it multiplied six times on health and eight times on education. So, let us not be told that we are going to see एक नया युग, एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री जी, यह भारत हमेशा श्रेष्ठ रहा है, यह भारत निकृष्ट कभी नहीं रहा है। आपने चुनाव में कह दिया, लोगों ने सुन लिया। यह भारत सदियों से महान रहा है। यह एक प्राचीन संस्कृति है, महान देश है और हमें अपने देश पर नाज है।

जहां तक गरीबी की बात है, हम ने योजनाएं बनायीं और हिंदुस्तान के 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए। यह सच्चाई है या नहीं? इस देश में कोई इस बात से इंकार कर सकता है? आप भले ही हमारी आलोचना करें, विरोध करें, आपका अधिकार है, लेकिन आप सत्य को नहीं नकार सकते। यह सत्य जनता के पास भी जाएगा। महोदय, इतिहास हमेशा सत्य लिखता है, चाहे वह हमारी सच्चाई हो, चाहे आप की सच्चाई हो। आपके ये शुरू के दिन हैं, एक अरसे के बाद आप से बात होगी। अभी हमारी ओर से इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमारी शुभ-कामनाएं हैं कि आप अपनी सोच को पूरा करें, लेकिन आपने जो दिखाया है, उस में नवीन क्या है? यह तो सामान्य है। There is nothing new, this generalization as well as the use of words. हम को कोई आपत्ति नहीं है, यह आपकी सोच है। If the vision is of 5 Ts, — मैंने बड़े गौर से सुना था जब यह पहली बार कहा गया — Tradition, Talent, Tourism, Trade and Technology, in English language, if you have to spell these words, 'T' will be used in all the five. This is nothing new. India is an old civilization. So, traditions are there. Also, when we talk of 3Ss and 3Ds, if we have

[श्री आनन्द शर्मा]

to use the word, Democracy, Demography and Development, 'D' will be used in English language for all the three, and if we have to talk of Skills, Scale and Speed, — Shri Derek O'Brien is nodding as he knows the language better than me — 3Ss are used. So, vision is good, and I hope the country benefits. But let us be clear, let us not be carried away that this country has not seen either talent or technology. यह देश तो चांद पर पहुंच गया है और मंगल पर जा रहा है। यह एक परमाणु शक्ति है, इस देश की मिसाइल्स दुनिया के हर हिस्से में जा सकती हैं। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि जो इस देश के वैज्ञानिकों की, इस देश के लोगों की एचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए यह कर के दिखाया है और जिन्होंने यह कर दिखाया है, हम उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार करें।

आपने कहा है, आप चाहेंगे कि एक कंसेंसस बने, आम सहमति बने, रजामंदी, रायशुमारी बने। यह अच्छी बात है। हो सकता है कि नेता सदन ने जो कहा, उसमें कुछ कमी रह गयी हो। मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, कहीं कोई कमोबेशी हो, आपको शिकायत रही हो, लेकिन अगर आप देश को आम सहमति से चलाना चाहते हैं, रायशुमारी से चलाना चाहते हैं, तो सदन में बैठे सब लोग उसका स्वागत करेंगे। हम उसका विरोध नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया, मेरे साथियों ने भी कह दिया कि काफी चीज़ें वही हैं, अधिकांश वही हैं। कोई नई बात नहीं है। But, let me be specific about manufacturing. Let me be specific about industrial corridors. Let me be specific about freight corridors. जब अभिभाषण बनता है, तो अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे सारी बातें सरकार के समक्ष रखें कि देश में ये-ये बड़े काम हो रहे हैं। सरकार उनको स्वीकार करती, तो हमें, देश को भी अच्छा लगता। अब मैं आपको बताता हूं। This country adopted the National Manufacturing Policy on 25th October, 2011. The Cabinet had approved it on that day. It is under implementation. It proposes to raise the share of manufacturing in GDP by 10 percentage points in a decade. The principle instrument is the establishment of the National Investment and Manufacturing Zones. These NIMZs will be stand alone integrate industrial cities, manufacturing cities of future. Is it on paper? The answer is 'no.' We are doing it in partnership with States. Sir, sixteen of these cities or the NIMZs have been notified, four have been launched and a singlewindow clearance mechanism has been effectively put in place. Japan is a major developmental partner in the development of the industrial corridors. मैंने जिन शहरों का जिक्र किया, जो बनने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको मालूम है कि इसमें जापान का योगदान रहा। हमने जापान के साथ जो सहमति बनाई, जो करेन्सी स्वाप की, इसके लिए मैं पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को

धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इनकी सूझ-बूझ थी, इनका दर्शन था कि इंटरेस्ट स्वैप का अरेंजमेंट किया, पहले 15 बिलियन डॉलर आया, पिछले साल उसको बढ़ाकर 50 बिलियन कर दिया गया। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, is the most innovative infrastructure project ever conceived and is presently the largest project under implementation in the world. मैंने जिन शहरों का जिक्र किया, जो 16 नोटिफाइड हैं, वे 6 राज्यों में हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में तीन बड़े हैं, एक शेन्द्रे बिदकिन लांच कर दिया गया, एक पोर्ट सिटी दिघी बन रही है, एक नागपुर के पास, तुमकुर-उमरेद ताल्लुका के पास बन रहा है, जो शायद सबसे छोटा NIMZ 50 किलोमीटर का है और सबसे बड़ा 920 स्क्वेयर किलोमीटर का है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात के धोलेरा में है। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। हम नहीं कहते कि यह हम ही कर रहे थे, जापान साथी बन कर आया, पैसा लाए, टैक्नोलॉजी लाए और राज्य की सरकारें उसमें भागीदार बनीं। राज्यों की सरकारों को हम साथ में लेकर चले हैं। It is being done in partnership with States, not otherwise.

Now, with regard to other corridors, let me inform this august House. The Amritsar-Kolkata Industrial Corridor was approved by the Cabinet on 20th January, 2014. The Chennai-Bengaluru Industrial Corridor has been extended, first, to Tumkur and now to Chitradurg. The fourth is the spine. It is the Bengaluru-Mumbai Economic Corridor in which UK has come as a partner country. It is my responsibility and duty to put all this before the House and the country, so that this impression which is being created will become clear. An impression has been created as if we were doing nothing — we were just going to office and coming back home. That is not true.

With regard to e-governance, good luck. But, let me also inform that e-Governance National Mission Mode Projects were launched in 2006.

Twenty-seven Mission Mode Projects are under implementation. We have e-enabled most of the institutions for business climate, for approvals and registrations. Mr. Chairman, Sir, there is a National Mission Mode Project called the e-based project. All payments and applications are done electronically. Infosys has executed it. Bank realizations and certificates are done electronically. National Optical Network Mission was approved by the Cabinet and it is under implementation on the same day as the National Manufacturing Policy day, on 25th October, 2011. So, you please continue with this work. But, let this impression not be given that nothing was happening. We hope that your worthy colleagues in the Government the Finance Minister of India, and my successor—she may have come to Government now, but she is earnest and sincere, and she brings lot of knowledge—I am sure they will continue with the work and our best wishes to you.

[Shri Anand Sharma]

Sir, this President's Address has spoken about FDI. It is important for me to mention. We opened up most of the sectors, raised the sectoral caps; I will not go into details. There was a very vague reference made on FDI in defence. Mr. Sitaram Yechury raised it yesterday. It also talks about FDI in Railways. Sir, on FDI in Railways the Cabinet Notes were cleared, but the matter was not listed because the Model Code of Conduct came and I am sure, you will go ahead with it. But, there is another issue. We did not vitiate the investment climate, my dear friends; you did it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Certainly not. The people know it and that is why you lost. Realise it at least now. See your fate in the other House!

SHRI ANAND SHARMA: I will tell you. I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sharmaji, you are exhausting your party-time. Precisely three minutes.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I will need a bit of time and conclude.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate and conclude.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, not in three minutes, please.

What I am trying to say is that on the FDI in multi-brand retail, which was brought in, the first executive decision which was brought to Parliament for debate, for vote; both the Houses voted in favour. There were ringing endorsements even by the Supreme Court. All the farmers' unions in the country, all the consumers' unions in the country wanted it. The President's Address talks about managing agriculture production and technology. We were bringing in technology. It was mandatory that 50 per cent had to be there in the rural areas for infrastructure. Why was this opposed? People have organized retail in India. Big corporates are engaged in organized retail. If the farmers wanted it, if the consumers wanted it, micro and small industries wanted it, you opposed it...*(Interruptions)*...

Now, we would like to know, because you want to invite investors, who want predictability and stability. I urge and, I think, it is my duty; I know what your views are. The stability and predictability of the policies are important. Mr. Chairman, Sir, we never changed or reversed any policy decision of the NDA Government. I would urge you to be cautious and careful. ...*(Interruptions)*...

Retrospective is not policy, my dear young friend. Sir, there are two things which I have to mention before I conclude. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please don't disrupt. ...*(Interruptions)*... Please let the speaker conclude. ...*(Interruptions)*... Sharmaji, please conclude now.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I think, respecting the occasion and the fact that we are the Opposition, I do expect accommodation from the Chair. That is why we have cut a large number of our speakers and reserved this time, and I hope that would be recognised.

MR. CHAIRMAN: Party time.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Prime Minister and his Government has talked about repeal of archaic laws. Secretaries to the Government of India have instructed each Department to identify and repeal 10 laws. There are 80 Departments in the Government of India with 76 Secretaries. Is there a list? The country would like to know which 760 laws are going to be repealed. This is a serious matter. It is very serious.

Secondly, as capitalism has grown in any country, regulatory frameworks have evolved; as new technologies have come, regulatory frameworks have evolved. We have seen in electricity; we have seen in telecom; we have seen in power sector; so, why not recognize that there is also equally a real need of a regulatory framework to govern this country in a rule-based manner?

Sir, considering the constraints of time, I want to flag quickly three things. The President's Address has talked of 'One-Rank-One-Pension'. I am happy that you and we are on the same page. The Leader of the House has said that it will be implemented; the President's Address says it is to be implemented. The then Defence Minister is here. The first Order to implement 'One-Rank-One-Pension' was issued on 26th February, 2014. This is the Notification, and the final Order, to ensure orderly implementation and the constitution of a Working Group headed by the Controller General of Defence Accounts as the Chair, was issued on 24th April, 2014. If this information was not made available to the new Government, I am just trying to be helpful in giving you this information and setting the records straight again.

Sir, the important thing which I have to say is this. Let me also tell with all respect that today we have a news a day, and this is important to hear, Sir. Today, I was reading; every day there is some instruction, and it is the right of the Government, that every Minister will now disclose their assets and liabilities. Let this country not get an impression that the Ministers were not declaring their assets and liabilities now. Until the last day, till 31st of July, all of us, without any exception, submitted it to

[Shri Anand Sharma]

our Prime Minister then. So, this is not something new. Cabinet Committees are being dissolved; EGOMs dissolved. You have got a mandate. I do not know whether it is minimum governance – my colleagues have spoken and I won't take time on that – but these are disturbing signs of centralization and concentration of power.

Sir, lastly, I would like to talk about the world view, which is important. The President's Address has talked about it. माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया। वे आए, अच्छी बात है। आपने अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ अपने संबंध मज़बूत करने की बात कही, हम इससे सहमत हैं।

But can I ask one thing? Your world view is truncated. You cannot engage with a truncated globe. Why is there no mention of West Asia in your world view? Why is there no mention of ASEAN, which is part of our Look East Policy and we are engaged in important negotiations, the RCEP Negotiations? Why is there no mention even of Africa? Why is there no mention of Latin America? शायद आपकी मंशा नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूं कि इसके बारे में सोचिए, कहीं दुनिया के ये इलाके, जिनके साथ हमारी बड़ी एंगेजमेंट है, इसका गलत मतलब न निकाल लें। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं, एक चीज़ कहूंगा और आप भी उसको सुनकर अगर मुझे कुछ और समय देंगे तो अच्छी बात होगी। मैं उसका कारण बताता हूं। आपने कहा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म के 150 साल पूरे होंगे, उसको देश अच्छी तरह से मनायेगा। इसे मनाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रपिता हैं। उनका विचार, उनका दर्शन पूरी दुनिया सम्मान से मानती है, आपने इस काम को करने के लिए कहा है, पूरे देश का इसमें सहयोग रहेगा। यह नेक काम है, आप इसे अच्छी तरह से करिए। परन्तु मेरा एक प्रश्न है कि जब आजादी का आंदोलन हुआ था, तो जो अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कुर्बानियां दीं, अपनी जवानी जेल में काटी, देश के पहले प्रधान मंत्री, जिन्हें दुनिया ने स्टेट्समैंन माना, जिनकी दुनिया ने इज्जत की, जवाहर लाल नेहरू जी के जन्म के 125 साल हो रहे हैं, इसका आपने ज़िक्र क्यों नहीं किया? आपका विरोध हो सकता है, परन्तु सरकार को देश की बात करनी चाहिए। जवाहर लाल नेहरू एक बहुत बड़ी धरोहर देश के लिए छोड़कर गए हैं। उनकी कुर्बानी रही है, उनकी दुनिया में इज्जत है। Therefore, I am surprised that this is the world view. It is a complete departure. If this country does not recognize those who fought for the Freedom, the tall leaders, the statesmen, a leader who was respected across continents, I would like you to reflect upon this and correct this.

**श्री सभापति** : थैंक्यू।

**श्री आनन्द शर्मा** : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे यही कहना है कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उस पर पूरी चर्चा हो चुकी। यह परम्परा रही है, यह गरिमा रही है कि उसका

हम समर्थन करें। हम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हैं और आपसे भी कहते हैं, मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप सही मायने में आम सहमति करके, सही मायने में जीत में अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाते हुए, सबको साथ लेकर चलेंगे तो देश हित में हमारा सहयोग रहेगा। जहां हम देखेंगे कि हिन्दुस्तान के हित को कहीं भी चोट पहुंचती है, तो चाहे हमारी संख्या कितनी भी हो, गलतफहमी न रहे, विरोध होगा। आप भी दो की संख्या में रह गए थे। वे दिन भी हमने और आपने देखे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा होता है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो आपने कहा है, हम उसका सम्मान करते हुए, उम्मीद रखते हैं कि वैसी ही दिशा रहेगी, वैसे ही आप चलेंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : थैंक्यू वेरी मच।

**डा. वी. मैत्रेयन** : ये सरकार से कह रहे हैं कि जवाहर लाल नेहरू को भूल गए, लेकिन ये भी तो सरदार पटेल को भूल गए।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।...**(व्यवधान)**... प्लीज़।

**प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी)** : आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्यगण, सदन में मुझे आज पहली बार बोलने का अवसर मिला है। यहां सारे वरिष्ठ और अनुभवी महानुभाव हैं। आगे मुझे उन सब से बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन आज प्रारम्भ में, मेरे अनुभव की कमी के कारण अगर कोई चूक रह जाए, तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में करीब 42 आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी, श्री देरेक ओब्राईन जी, श्री डी.पी. त्रिपाठी जी, प्रो. राम गोपाल यादव जी, श्री सीताराम येचुरी जी और सभी वरिष्ठ महानुभावों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। सभी दलों के नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं और बहुतायत में इसका समर्थन हुआ है, कहीं पर कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए हैं और कुछेक में अपेक्षाएं भी व्यक्त की गई हैं। यह चर्चा बहुत सार्थक रही है, किसी भी बैंच पर क्यों न बैठे हों, लेकिन स्वीकार करने योग्य जो भी सुझाव आए हैं, उन सझावों का आने वाले दिनों में रचनात्मक तरीके से सही उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे।

मैं इसके लिए रचनात्मक सुझाव देने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और आशंका भी व्यक्त की है कि यह कैसे संभव होगा, कब करोगे और कैसे करोगे? यह बात सही है कि पिछले कई वर्षों से एक ऐसा निराशा का माहौल छाया हुआ है और हर किसी का मन ऐसा बन गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब बेकार हो गया है। उसकी छाया अभी भी है और उसके कारण कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, यह सवाल उठाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे मित्रों को भी कुछ ही दिनों में विश्वास हो जाएगा कि अब निराशा का माहौल छंट चुका है और देश एक नई आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प कर चुका है।

कई वर्षों के बाद देश ने एक ऐसा जनादेश दिया है, जिसमें देश ने स्थिरता को प्राथमिकता दी है और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट किया है। भारत के मतदाताओं का यह निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। हम देशवासियों के आभारी हैं कि उन्होंने भारत की संसदीय प्रणाली का इतनी उमंग

[श्री नरेन्द्र मोदी]

और उत्साह के साथ अनुमोदन किया है। इसके साथ-साथ समय की मांग है कि हम अपने महान लोकतंत्र के प्रति गौरवान्वित होकर विश्व के सामने जरा सिर ऊंचा करके, आंख मिलाकर बोलने की आदत बनाएं। हमारे मतदाताओं की संख्या अमेरिका और यूरोप के मतदाताओं की कुल जनसंख्या से ज्यादा है, यानी हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां पर चाहे कोई अनपढ़ हो, गरीब हो, गांव में रहता हो और उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी न हों, लेकिन उसकी रगों में लोकतंत्र ने जिस प्रकार से जगह बनाई है, यह हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन हम इसको विश्व के सामने उस रूप में अभी तक ला नहीं पाए हैं। यह हम सबका सामूहिक कर्त्तव्य है कि हम भारत की इस लोकतांत्रिक ताकत को विश्व के सामने उजागर करें और एक नए आत्मविश्वास का संचार करें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बिन्दुओं को स्पर्श किया है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से उनको व्यक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि विजय और पराजय दोनों में सीख देने की ताकत होती है और सीख पाने की आवश्यकता भी होती है। जो विजय से सीख नही लेता है, वह पराजय के बीज बोता है और जो पराजय से सीख नहीं लेता, वह विनाश के बीज बोता है। जय और पराजय के तराजू से ऊपर उठकर हमें कुछ सीखना भी है। मैं एक बार आचार्य विनोबा जी के चिंतन को पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने 'युवा' की व्याख्या की है। वह व्याख्या बड़ी सरल और अच्छी है। उन्होंने कहा कि 'युवा' वह होता है जो आने वाले कल की सोचता है, आने वाले कल की बात बोलता है। लेकिन जो बीती हुई बातों को गाता रहता है, वह 'युवा' नहीं हो सकता है, उसकी सोच 'युवा' नहीं हो सकती है। उसके लिए बीती हुई बातों को ही गुनगुनाते रहना, लोग चाहे स्वीकार करें या न करें, लोग अस्वीकार करें, तो भी अपने उसी लहजे में रहना, उचित नहीं है। हमने भी देखा है कि रेल या बस में जब कभी कोई बूढ़े सज्जन मिल जाते हैं, तो उनको देर तक सुनना पड़ता है। उनका भूतकाल क्या था, उनकी वे सारी कथाएं सुननी होती हैं। मैं मानता हूं कि विनोबा जी की 'युवा' की यह बड़ी बढ़िया डेफिनिशन है, जो हमें आगे आने वाले दिनों की ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है।

भारत की एक ताकत उसका संघीय ढांचा है। बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय के हमारे विद्वत पुरुषों ने हमें जो संविधान दिया है, उसकी एक सबसे बड़ी ताकत यह संघीय ढांचा है। हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने दिल्ली में बैठकर संघीय ढांचे को ताकत दी है या नहीं दी है? इसको और अधिक सामर्थ्यवान बनाया है या नहीं बनाया है? अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो राज्यों को आगे बढ़ना होगा, अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है, तो राज्यों को समृद्ध होना होगा और अगर राष्ट्र की सशक्त होना है, तो राज्यों को सशक्त होना पड़ेगा।

इसलिए जब मैं गुजरात में मुख्य मंत्री के रूप में काम करता था, तो हम हमेशा एक मंत्र बोलते थे, "भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास।" हम हमेशा ये शब्द प्रयोग करते थे। क्या हम राज्यों के अंदर यह माहौल पनपा पाए हैं? मेरा यह सद्भाग्य रहा है कि एक राज्य के मुखिया के रूप में क्या पीड़ा होती है, मैंने उसको बहुत झेला है, अनुभव किया है। मेरा यह

भी सौभाग्य रहा है कि यदि दिल्ली में अनुकूल सरकार हो, तब राज्य का क्या हाल होता है और यदि प्रतिकूल सरकार दिल्ली में हो, तब राज्य का क्या हाल होता है। मैं एक भुक्तभोगी व्यक्ति हूं। मैंने इन कठिनाइयों को झेला है कि राज्यों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मैंने इसको भली-भांति समझा है कि राज्य कितनी ठोकरें खाता है, राज्य की बात को किस प्रकार से नकारा जाता है, सिर्फ निजी स्वार्थ की खातिर राज्य की योजनाओं को किस प्रकार से रोका जाता है, पर्यावरण के नाम पर राज्य की विकास यात्रा को दबोचने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, मैं इन सारी बातों का भुक्तभोगी हूं। इसलिए आज एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, एक ऐसे व्यक्ति को देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जो राज्यों की पीड़ा को भली-भांति समझता है। आज मैं इस पीड़ा को जानते हुए इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्य करेंगे।

आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने इस बात पर बल दिया है और हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। यह बड़े भाई, छोटे भाई वाला कारोबार नहीं चलेगा। हमें राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की दिशा बना ली है। हमें एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें राज्य को भी अनुभूति हो कि मैं भारत की भलाई के लिए काम कर रहा हूं और भारत की सरकार चलाने वाले लोगों के मन में भी यह रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का छोटे से छोटा राज्य भी क्यों न हो, उसके विकास के बिना हिंदुस्तान का विकास होने वाला नहीं है। हमें इस मन की रचना के साथ देश को आगे चलाना है। आदरणीय सभापति जी, यह मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर हम राज्यों को विश्वास में लें, तो हमारे कार्य की गति बहुत बढ़ सकती है। हमने टीम इंडिया कांसेप्ट के बाद आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में कह दिया है कि अगर भारत जैसे संघीय राज्य की व्यवस्था वाले देश को चलाना है, तो प्रधानमंत्री और सभी मुख्य मंत्री, इनको एक टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्री, यह टीम सफिशिएंट नहीं है। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री, यही टीम का एक स्वरूप हमें उभारना होगा और अगर हम उस पर बल देंगे, तो हम राज्यों की ताकत राष्ट्र के विकास में जोड़ पाएंगे। मैंने सुना, हमारे मैत्रेयन जी का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि उनके मुख्य मंत्री ने 40 चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन एक का जवाब नहीं आया था। यह स्थिति हमें बदलनी होगी। इसलिए इस अवस्था को लाने के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित हो, उस पर हम प्रयास करने के पक्ष में हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

हमारे देश में कुछ लोगों को गुजरात मॉडल की बड़ी चिन्ता हो रही है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या? उनकी इस मुसीबत का मैं अंदाजा लगा सकता हूं। अगर गुजरात मॉडल को सरल भाषा में समझना है, तो वह यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो, तो उसको समझना, स्वीकार करना और हमारे यहां लागू करना, यह गुजरात मॉडल है। केरल में लेफ्टिस्ट की सरकार थी, लेकिन उनका एक कुडुम्बश्री प्रोग्राम था। हमने उससे सीखा और हमारे यहां अनुकूलता के अनुसार उसको लागू किया। सबसे बड़ी बात है कि आज एक राज्य और दूसरे राज्य की जो चर्चा हो रही है, वह मॉडल की चर्चा हो रही है और मॉडल की चर्चा विकास के संदर्भ में हो रही है। यह हमारे

[श्री नरेन्द्र मोदी]

लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ विकास की स्पर्द्धा के साथ चर्चा कर रहा है। मेरे कान इस बात को सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं कि कभी बंगाल यह कहे कि हम गुजरात से आगे निकल गए, कभी तमिलनाडु कहे कि गुजरात और बंगाल, दोनों से हम आगे निकल गए, कभी आन्ध्र प्रदेश कहे कि हम तेलंगाना से आगे निकल गए, कभी तेलंगाना कहे कि हम आन्ध्र प्रदेश से आगे निकल गए, कभी बिहार कहे कि हमने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। यह स्पर्द्धा का माहौल, विकास की स्पर्द्धा का माहौल हमें देश में देखना है, बढ़ाना है। उस दिशा में हम इस बात को लेकर आए हैं कि हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में हर राज्य की अपनी शक्ति भी है, हर राज्य की अपनी विशेषता भी है। हमें उसको समझना होगा। गुजरात जैसा छोटा सा राज्य, लेकिन हर जिले में हमारा एक मॉडल काम नहीं करता है। एक ही प्रकार के कुर्ते सारी दुनिया को पहनाए नहीं जा सकते। वहां की विशेषता यह है कि रेगिस्तान वाले कच्छ का मॉडल हरे-भरे वलसाड में नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से एक राज्य का मॉडल दूसरे राज्य पर थोपा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से दिल्ली के विचार राज्यों पर नहीं थोपे जा सकते। उसकी प्रायरिटी क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या हैं, उसके अनुरूप संसाधनों का उपयोग करके उन शक्तियों को बल देने से वे तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसलिए विकासमय राज्य और राष्ट्र, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी, एक नए राजनीतिक चरित्र की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भारत माता के चित्र को देखें, तो हमें ध्यान में आता है कि भारत मां का पश्चिमी किनारा, वहां तो कुछ गतिविधि नजर आती है, जिसमें केरल है, कर्णाटक है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, लेकिन हमारे देश का पूर्वी इलाक़ा है, जिसमें ओडिशा है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है। क्या हमारी भारत माता ऐसी हो, जिसका एक हाथ तो मज़बूत हो और दूसरा हाथ दुर्बल हो? तो यह भारत माँ कैसे मज़बूत बनेगी? इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता है कि भारत का पूर्वी छोर, जो विकास में पीछे रह गया है, उसको कम से कम पश्चिम की बराबरी में लाने के लिए हमें अथाह प्रयास करना है।

जब हम कहते हैं, "सबका साथ, सबका विकास", विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सार्वदेशिक होना चाहिए, विकास सर्वप्रिय होना चाहिए, विकास सर्वहितकारी होना चाहिए। इसलिए विकास को किसी एक कोने में देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम हम उसको परिभाषित करें, तो एक समग्र के कल्याण की परिभाषा को लेकर, आगे बढ़ने की कल्पना को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। इसलिए भारत का जो पूर्वी इलाक़ा है, उसकी हम चिन्ता करें।

नॉर्थ-ईस्ट, हम केवल नॉर्थ-ईस्ट की आर्थिक मदद करें और फिर उसको उसके नसीब पर छोड़ दें, ऐसे कब तक चलेगा? क्या हम नये सिरे से नहीं सोच सकते? आज हमारे देश में 30,000 से ज्यादा कॉलेजिज़ हैं। हर कॉलेज के स्टुडेंट्स हफ्ता-दस दिन के लिए टूर पर जाते हैं, यह उनका एक रेगुलर कार्यक्रम रहता है। क्या कभी हमने अपने कॉलेजिज़ को गाइड किया है कि कम से कम हर कॉलेज साल में एक बार दस दिन के लिए नॉर्थ-ईस्ट का एक टूर जरूर करे? आप विचार कीजिए अगर देश के 30,000 कॉलेजिज़ के 100-100 विद्यार्थी भी नॉर्थ-ईस्ट में एक हफ्ता रह करके

आते हैं, उससे नॉर्थ-ईस्ट का टूरिज्म कितना बढ़ सकता है, ईको टूरिज्म कितना बढ़ सकता है? इससे नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के सुख-दुःख को हिन्दुस्तान के कोने-कोने का व्यक्ति जानेगा और नॉर्थ-ईस्ट के साथ उनका कितना अपनापन हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में भारत माँ की जय बोलने वाले लोग हैं। उनको गले लगाने का एक रास्ता नहीं हो सकता है?

तरीके ढूंढने होते हैं कि किस प्रकार से नये तरीकों से हम देश को चला सकते हैं, उसकी योजना बनानी होती है। एक बार मुख्य मंत्री के कार्यकाल के दरमियान नॉर्थ-ईस्ट के सभी मुख्य मंत्रियों को मैंने इस सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी थी। जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तब एक बार उन्होंने एनडीसी की मीटिंग बुलाई थी, उस समय भी मैंने उनसे पब्लिकली यह कहा था और उनसे आग्रह किया था कि नॉर्थ-ईस्ट के सभी स्टेट्स से 200 विमेन पुलिस आप दो साल के लिए गुजरात में भेज दीजिए और फिर हर दो साल के बाद आप उनको चेंज करते रहिए। इससे 1500 से 2000 लोगों को वहां काम मिलेगा और जब वे वापिस जाएंगे तो यहां के कई परिवारों से उनका नाता जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इंटिग्रेशन का कितना बढ़िया काम संभव हो सकेगा। हम जो एक भारत की कहते हैं, यह एक भारत का सपना है। यह दो या तीन भारत के संदर्भ में एक भारत नहीं है, यह भारत की एकता की बात है।

आज जातिवाद के जहर ने देश को डुबो दिया है। प्रान्तवाद की भाषा ने देश को तबाह करके रखा है। समय की मांग है कि यह तोड़ने वाली भाषा छोड़ करके एकता की भाषा को एक स्वर से बोलना चाहिए, इसलिए "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" का सपना हम लाए हैं। अगर किसी को एक भारत में से दो दिखता है, तो यह उनकी मानसिक बीमारी का परिणाम है, हम तो एकता का मंत्र ले करके आए हैं। हम भाषा से परे हो करके, जाति से परे हो करके, सम्प्रदाय से परे हो करके एक राष्ट्र का सपना ले करके हम चलें।

यह देश विविधता में एकता वाला देश है। हमारा देश एकरूपता वाला देश नहीं है और देश एकरूपता वाला बनना भी नहीं चाहिए। हम वे लोग नहीं हैं कि हर बीस किलो मीटर पर एक ही प्रकार का पिज्ज़ा खाएं, हम तो वे लोग हैं, जो नीचे से निकले तो इडली खाते-खाते निकले और ऊपर जाते-जाते वह परांठा हो जाता है। यह विविधता से भरा हुआ देश है, उसे एकरूपता से नहीं रखा जा सकता, इसलिए "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" का सपना ले करके हम देश के कल्याण की बात कर रहे हैं। हमारे देश में संसाधनों के सम्बन्ध में हम एक नये तरीके से सबको कैसे प्रेरित करें? राज्यों के अपने स्वभाव हैं, अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कठिनाइयां हैं। उन समस्याओं का सामयिक रूप से समाधान करने का कल्चर क्यों न बने? जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स तो हम तराई के इलाकों की प्रगति के मॉडल से फिट नहीं कर सकते। हमारा अफसर वहां जाएगा, तो वह कहेगा कि यहां 60 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन हिमालय में 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी कैसे चलेगी? वह कहेगा एक गाड़ी है, जब यह इतने किलोमीटर जाए तो इतना डीज़ल मिलेगा, तब वहां यह इतने डीज़ल से कहां चलने वाली है? इसलिए, हमें एक tailor-made solution में से बाहर आना पड़ेगा और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात को हमने उजागर किया है कि हिमालयन रेंज के जितने स्टेट्स हैं, उनको एक साथ बिठा कर उनकी समस्याओं को समझा जाए और क्या उनके लिए कोई कॉमन व्यवस्था विकसित कर सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करें।

[श्री नरेन्द्र मोदी]

कोस्टल स्टेट्स में समुद्र तट पर विकास की बात है। आज विश्व-व्यापार का युग है, हमारे समुद्र तट का विकास जितनी तेजी से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। हमारे भारत का समुद्र तट भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन सकता है। हमारा कोस्टल एरिया भारत की प्रॉस्पेरिटी का साधन बन सकता है, लेकिन आज वह सबसे ज्यादा उपेक्षित है। हमने ज्यादा-से-ज्यादा सोचा तो मछुआरों के बारे में सोचा। हमने पूरे कोस्टल बेल्ट के डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा और इसीलिए तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोस्टल डेवलपमेंट के लिए अलग से विचार करने की एक व्यवस्था सोची गई है। हम चाहते हैं कि कोस्टल राज्य एक साथ बैठें। कोस्टल डेवलपमेंट में क्या कॉमन विचार हों, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, एक-दूसरे को वे कोऑर्डिनेट कैसे करें, वे एक-दूसरे की ताकत कैसे बनें और विकास की स्पर्धा में वे एक-दूसरे के साथ कैसे अपने अनुभव शेयर करें। भारत का समुद्री तट बहुत बड़ा है। हम एक ऐसी भौगोलिक लोकेशन पर हैं कि हम ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सामुद्रिक ताकत बन सकते हैं, लेकिन हमें उसमें जितना आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़े। श्रीलंका का कोलम्बो छोटा-सा है, लेकिन आज वह विश्व व्यापार में, सामुद्रिक व्यापार में जिस प्रकार का सेंटर बना हुआ है, वैसा उस तरफ सिंगापुर बना हुआ है और इस तरफ पाकिस्तान के अंदर चीन अपने डेरे-तम्बू डाल रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत को अपने समुद्री तट की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उसके लिए हमारे समुद्र तट के राज्यों के विकास का मॉडल उनके साथ बैठ कर नहीं बनाया जा सकता?

हमारे यहां लैंड-लॉक्ड स्टेट्स हैं। उनमें भी विविधताएं भरी पड़ी हैं। उनकी विविधताओं को समझना होगा। हमारे यहां माओवाद से इफेक्टेड एरियाज़ हैं। कुछ माओवाद प्रोन ज़ोन भी हैं। क्या उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बैठ कर उसी स्पेसिफिक समस्या के समाधान के लिए केन्द्र और राज्य मिल कर काम नहीं कर सकते? इसीलिए, हम आगे आने वाले दिनों में इन चीज़ों को आगे कैसे ले जाएं, उस आगे ले जाने का हमारा रास्ता भी यही लेकर हम चलना चाहते हैं, ताकि हिन्दुस्तान का हरेक राज्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर विकास की यात्रा में आगे आए। आजकल क्या हुआ है? हम दिल्ली में राजनीतिक माइलेज प्राप्त करने के लिए कोई भी निर्णय कर लेते हैं, कोई भी कानून बना देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी स्टेट्स की होती है। उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं और इसीलिए वह योजना धरी की धरी रह जाती है। अखबार में चार-छ: दिन आ जाता है और फिर स्टेट्स को गाली पड़ती है कि आपकी दिल्ली ने यह किया लेकिन उसे आपने लागू नहीं किया। यह तनावपूर्ण वातावरण हम क्यों पैदा करते हैं? मैं राज्य में रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि यह तनाव हमें विपरीत दिशा में ले जाता है और इसलिए हमें इन स्थितियों पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है और उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है।

हमारे एग्रीकल्चर के भी एग्रो-क्लाइमेट ज़ोन्स हैं। हर राज्य में एक फसल का एक निश्चित एरिया है। उसकी मैपिंग तो है, लेकिन गेहूं पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनको अलग से बिठाकर बात करेंगे, चावल पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनसे हम अलग से बात करेंगे और गन्ना पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनसे अलग से बात करेंगे। जब तक

हम इश्यू-सेंट्रिक फोकस्ड एक्टिविटी नहीं करते, हम इतने बड़े विशाल देश को सिर्फ दिल्ली से चलाने की कोशिश करते रहेंगे और नीतियां बनाने के मामले में हम दुनिया को कहेंगे कि हमने इतने एक्ट बनाए, इतने काम किए, लेकिन इससे स्थितियां नहीं बदलेंगीं। आज आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। लास्ट मैन डिलीवरी सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए मूल कारण गवर्नेंस है।

स्वराज्य मिला, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम सुराज नहीं दे पाए। जिस दिन मैं नेता चुना गया, जिन्होंने उस दिन का मेरा भाषण सुना होगा, मैंने साफ कहा है कि मैं इस विचार का नहीं हूं कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया है और कोई सरकार कुछ न करने के लिए तो आती नहीं है, हर सरकार कुछ करने के लिए आती है। अपने-अपने समय में हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। उन सब का cumulative परिणाम है कि आज हम यहां हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है, जिस दिशा में होना चाहिए था, उस दिशा में नहीं हुआ है और जिस प्रकार से देश के अंदर ऊर्जा भरनी चाहिए थी, उस प्रकार से ऊर्जा नहीं भरी है। इन कमियों को हमें पूर्ण करना होगा।

महोदय, यही देश के नेता बाहर जाकर आज भी कहते हैं कि हमारा देश तो गरीब है और वही हमें यहां मिसाइल दिखा रहे हैं। यह देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह देश विश्व के समृद्ध देशों में आगे माना जाता था। यह देश ज्ञान-विज्ञान की दुनिया में प्रगति पर माना जाता था। गुलामी के कालखंड में सब ध्वस्त हो चुका, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। हम सुराज की ओर कैसे बल दें? हमारे लोकतंत्र के ढांचे से हम इस रूप से दब गए, अपने आप पता नहीं क्या कठिनायां महसूस कीं कि हमने good governance पर बल नहीं दिया। Good governance सामान्य नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है। क्या आज हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा प्रशासन तंत्र सामान्य नागरिक के प्रति जवाबदेह है? लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि वह नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन यह स्थिति नहीं है। क्या हम यह कह सकते हैं कि आज के व्यवस्था तंत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति की सुनवाई हो रही है? अगर गरीब के लिए सरकार नहीं है, तो लोकतंत्र की वह कौन सी असलियत है, जो इस प्रकार की कमियां पैदा कर रही है? इसलिए समय की मांग है कि देश के अंदर सुराज पर हमें बल देना पड़ेगा। इसलिए हमें सुराज पर बल देना है।

महोदय, व्यक्ति कितना ही स्वस्थ क्यों न दिखता हो, ऊंचाई हो, वजन ठीक हो, सब हो, कोई बीमारी न हो, लेकिन अगर एक डायबिटीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, तो उसका सारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। जिस प्रकार से शरीर में डायबिटीज का प्रवेश पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से शासन व्यवस्था में bad governance की एंट्री पूरे शासन तंत्र को, पूरे देश को तबाह कर देती है। Bad governance डायबिटीज से भी भयंकर होता है। हमारा आग्रह है, हमारा प्रयास है कि हम good governance की ओर चलें।

महोदय, देश में करप्शन की चिंता है और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में हमारी एक पहचान बनी है, अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, हर एक के अपने-अपने विचार होंगे, लेकिन दुनिया के सामने हिन्दुस्तान एक 'scam India' बन गया, यह आम पहचान बन गई है और उसी ने भारत

[श्री नरेन्द्र मोदी]

की विकास यात्रा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। हमारे टूरिज्म पर बहुत बड़ी ब्रेक लगी, यह क्यों लगी? बलात्कार की घटनाओं ने टूरिस्टों के आने में रोक पैदा कर दी। पूरे देश की विकास यात्रा में भारत की छोटी-छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं और इस पर राजनीति नहीं हो सकती है। क्या हम terrorism पर भी राजनीति करेंगे? क्या हम माओवाद के हमलों पर भी राजनीति करेंगे? क्या हम मां-बहनों के बलात्कार पर भी राजनीति करेंगे? क्या हम निर्दोषों की हत्या पर भी राजनीति करेंगे? समय की मांग है कि हम इससे ऊपर उठ करके एक सामूहिक दायित्व के साथ इन समस्याओं के संबंध में कोई compromise नहीं करेंगे, मिल-बैठ कर कोई रास्ता निकालेंगे और देश की छवि जो बर्बाद हो रही है, उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे।

महोदय, विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बन रहा था। टूरिज्म के लिए लोग भारत की तरफ मुड़े थे, लेकिन अचानक पिछले कुछ समय में इसमें गिरावट आई है। यह गिरावट इन्हीं घटनाओं के कारण आई है। क्या यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है? क्या राजनीति से ऊपर उठ करके इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते नहीं निकाले जा सकते हैं?

महोदय, यह ऐसा सदन है, जहां हमारे देश के टैलेंट बैठते हैं। यह देश की विद्वत सभा है। इन्हें मार्गदर्शन करना पड़ेगा। इसी गृह में मार्गदर्शन करना पड़ेगा। हमें मिल करके रास्ते खोजने पड़ेंगे और हमारी कोशिश है कि हम मिल-बैठ कर रास्ता खोजें और देश को आगे ले जाएं।

महोदय, हमारे देश में करप्शन के खिलाफ आम आदमी का रोष है। हमारी कानूनी व्यवस्था में कौन करप्ट आदमी कब जेल जाएगा, इसके लिए देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। उसके हाथ में जो शस्त्र है, उससे राजनेताओं को सजा देने के लिए आज वह काबिल हुआ है। लेकिन, उससे बात नहीं बननी है। जितनी चिन्ता करप्शन के बाद की होती है, उससे ज्यादा चिन्ता करप्शन न हो, इसके लिए करने की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने इस बात पर भी बल दिया है कि करप्शन के बाद लिए जाने वाले measures पर ज्यादा चर्चा हो चुकी है, उसके कई मुद्दे हैं, लेकिन करप्शन न हो, इसके लिए भी तो कुछ-कुछ चीज़ें की जा सकती हैं और उनमें से एक है, the State must be policy-driven. अगर राज्य नीतियों के आधार पर चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नीतियां available हैं, तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप नहीं रहता। पहला और आखिरी करने का अवसर नहीं रहता है, सबको समान अवसर मिलता है और अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो हर कोई सवाल पूछ सकता है। The State must be policy-driven. अगर स्टेट पॉलिसी-ड्रिवन है तो करप्शन की सम्भावनाएं बहुत ही कम रहती हैं, ग्रे-एरिया बहुत ही कम रहता है।

दूसरा है, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एन्वॉयरन्मेंट मिनिस्ट्री की फाइलें ऐसे ही जमा रहती हैं और भांति-भांति के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर वे ऑनलाइन हों तो कोई भी अप्लिकेंट घर बैठकर अपने पासवर्ड से ऑनलाइन यह देख सकता है कि आज मेरी फाइल की क्या पोजिशन है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी

आ सकती है कि हमारे यहां एक सामान्य मानव भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचेगा। सीसीटीवी कैमरा जैसी चीज़ें भी आज आदमी को डरा रही है, खूंखार-खूंखार व्यक्तियों को भी डरा रही हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। करप्शन को curb करने के लिए अभी ई-टेंडरिंग वगैरह छोटी-मोटी चीज़ें प्रारंभ हुई हैं, लेकिन उसको और व्यापक रूप से आगे लाया जाए। इतना ही नहीं, अगर हम स्कूल्स में बच्चों के presence को बायोमिट्रिक सिस्टम से जोड़ दें, तो फिर अगर कहीं 40 बच्चें हैं और कोई 80 लिखवाकर सारी सहायता ले रहा है, तो वह करप्शन अपने आप चला जाएगा। ग्रासरूट लेवल पर टॉप लेवल तक करप्शन की सारी बातें होती हैं। अगर रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी तो रेलवे के भीतर चलने वाली गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं, जैसे एक पॉलिसी-ड्रिवन स्टेट हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और करप्ट लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था हो, तो मुझे विश्वास है कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं।

हम चाहें या न चाहें, देश में हमारे इन सदनों की गरिमा पर चोट लगी हुई है। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वे लोग जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। पांच हों, सात हों, दस हों, लेकिन एक छवि बनी हुई है। यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस कलंक से हमारे इन दोनों सदनों को मुक्त करें और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है कि हम सब मिलकर तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट से request करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं, उनमें से किसी पर भी यदि एफआईआर लॉज हुई है, तो ज्यूडिशियल मेकैनिज्म के द्वारा उसको expedite किया जाए और एक साल के भीतर-भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो, वह जेल चला जाए, जो निर्दोष हों, वे बेदाग होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाएं। क्यों राजनीतिक कारणों से इतने गुनाह रजिस्टर होते हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं? हम देश और दुनिया को बताएं कि कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिन्दुस्तान को सदन में देखेंगे, चाहे वह लोक सभा हो या राज्य सभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से एक बार लोक सभा को क्लीन कर दें तो फिर राजनीतिक दलों को भी टिकटें देते समय 50 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम एक साल के भीतर यह सफाई कर देते हैं तो सीटें खाली होने लगेंगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह क्रम बाद में असेम्बलीज़ में ले जाया जाए और फिर धीर-धीरे कॉर्पोरेशंस में ले जाया जाए। जब एक बार माहौल बन जाएगा और वह सर्वसम्मति से बनेगा तो हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने का यह सही तरीका है। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई ऐसा भी होगा, जो इससे मुक्ति न चाहता हो। जिस पर एफआईआर होगी, वह भी कहेगा-साहब, यह तलवार 15 साल से लटक रही है, हर बार मुझे नामांकन करते समय लिखना पड़ता है, हर बार एनजीओ के द्वारा अखबार में छपता है कि इसके ऊपर 30 गुनाह हैं, इसके ऊपर 25 गुनाह हैं। इससे हर कोई मुक्ति चाहता है। हम न्याय की प्रक्रिया को इस प्रकार से संचालित करें। मैं मानता हूं कि सभी सदस्य, चाहे वे लोक सभा के हों, राज्य सभा के हों, ये सब मिल करके इस बात के लिए सहयोग करेंगे और हम उस

[श्री नरेन्द्र मोदी]

दिशा में सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर जो गुनहगार हैं उनके लिए जेल हो, जो बेगुनाह हो, वह बेदाग दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, उसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और इन दो सदनों में वह सामर्थ्य है कि ये उस काम को कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं।...**(व्यवधान)**...

**श्री वी. हनुमंत राव** (तेलंगाना) : सर, बैंकों के करोड़ों रुपए लूटे हैं, उनका क्या होगा? पहले उनको पकड़ो।...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : प्लीज़, बैठ जाइए।

**श्री नरेन्द्र मोदी** : हम लोग यहां से शुरुआत करें और उसके बाद बाकी हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूं कि कोई बचना नहीं चाहिए। कानून का राज होना चाहिए, बेगुनाहों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए तो अभी जो ब्लैक मनी के लिए दो साल से एसआईटी बनाना लटक रहा था, हमने आते ही उस काम को कर दिया। उस काम को कर दिया, क्योंकि यह हमारी प्राथमिकता है। हम में से कोई नहीं जानता कि वे ब्लैक मनी वाले कौन हैं, लेकिन देश की जनता के सामने यह सत्य आना जरूरी है कि ब्लैक मनी है या नहीं है, है तो किस की है, किसकी है तो कितनी है, कैसे आई और कहां गई, देश को पता तो चले और अगर नहीं है तो देश से इस प्रकार का धुआं हट जाएगा। देश एक शांति का आनन्द लेगा। इसलिए ऐसे कामों में कोताही बरते बिना हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के सामान्य व्यक्ति की संसद के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ेगी और सरकारी व्यवस्था में वह भरोसा करने लगेगा।

आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि उसका भरोसा टूट गया है और यह भरोसा इस हद तक टूटा है कि यहां बैठे हुए लोग भी कभी मोबाइल फोन से किसी को एस.एम.एस. करते होंगे और बाद में फोन करते होंगे कि मेरा एस.एम.एस. मिला? क्यों? भरोसा टूट गया है। भरोसा टूट गया है, वरना भरोसा होना चाहिए कि मेरे मोबाइल से मैंने एस.एम.एस. भेजा है तो गया ही होगा। लेकिन फोन करके पूछता है कि मैंने कोई एस.एम.एस. किया था, वह मिला क्या? यह जो भरोसा टूट गया है, उसको पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पताल में गया तो उसको विश्वास होना चाहिए कि उसकी बीमारी ठीक होगी। बच्चा सरकारी स्कूल में गया तो मां-बाप को भरोसा होना चाहिए कि उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होगी, यह भरोसा होना चाहिए और यह भरोसा पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम मिल बैठकर उस काम को करें, तो कर सकते हैं। आप सबने जो सुझाव दिए हैं, सभी सुझाव हमारे लिए सम्माननीय हैं और मैं कहता हूं और मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं, भले ही हम विजयी होकर आए हों, भले ही देश की जनता ने कई वर्षों के बाद हमारा इतना बड़ा समर्थन किया, लेकिन अगर आपका समर्थन नहीं, तो वह समर्थन अधूरा है, और इसलिए हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो आपके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जेनेवा के अंदर एक कांफ्रेंस में जाना था, पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबीइंग करने की आवश्यकता थी और नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पसंद किया और उनको डेलीगेशन के रूप में भेजा था और उस काम को किया था। तो सारी

जो अच्छी बातें हैं, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है और इसलिए हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। दल से बड़ा देश होता है, इस मंत्र को लेकर चलना है और इस पवित्र सदन में उस मंत्र को उजागर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपका सहयोग रहेगा तो समस्याओं का समाधान करने की सुविधा और ज्यादा तेज होगी। राजनीति करने के लिए आखिरी वर्ष काफी होता है, अभी तो चार साल सिर्फ राष्ट्र हित के लिए सोचें, राष्ट्रनीति के लिए सोचें। जय और पराजय में कड़वाहट आई है, उसको बाहर रख करके आएं। आती है कड़वाहट। इतनी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और यह तो वरिष्ठ गृह है, वरिष्ठ गृह का माहौल एक उमंग और उत्साह का होना चाहिए, उसको बरकरार करने के लिए हम कोशिश करेंगे।

मुझे विश्वास है कि देश के सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ विजयी लोग ही नहीं, चुने हुए सब लोगों का जो दायित्व होता है, उस दायित्व को पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। फिर एक बार, सदन के सामने अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं और मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, उस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए देश को हम नई दिशा दें, नई ताकत दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments (Nos. 1 to 10) by Prof. Saif-ud-Din Soz. Prof. Saif-ud-Din Soz, are you withdrawing the amendments? Or should I put them to vote? There will be no discussion. Say either yes or no.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I want a minute to speak on Amendment No. 6. किसी ने मोदी जी को गलत मशविरा दिया है...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: What about the recommendations of the Sachar Committee? ...*(Interruptions)*... I am withdrawing them. I am not pressing. But the recommendations of the Sachar Committee have been accepted by the Government of India.

MR. CHAIRMAN: This is not the occasion for it.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Those recommendations have to be implemented. I am not pressing.

*Amendments (Nos.* 1 *to* 10*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 11) by Shri Shantaram Naik. Are you pressing the amendment? Or are you withdrawing it?

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I am not pressing.

*Amendment (No.* 11*) was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 19 to 123) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you withdrawing the amendments?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am withdrawing the amendments.

*Amendments (Nos.* 19 *to* 123*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 124 to 149) by Shri Madhusudan Mistry. Are you withdrawing the amendments? Or should I put them to vote?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, since everybody is withdrawing their amendments, I am not pressing them. I must say that there are a number of things which were not there in the President's Address and the Government must take a note of it and in future those should be there.

*Amendments (Nos.* 124 *to* 149*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 150 to 171) by Shri K.C. Tyagi.

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने सम्बोधन में हमारी पार्टी का जिक्र नहीं किया कि वह पूर्वांचल के लिए अच्छा करेंगे और हमारे बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं अपने संशोधन विद्ड्रा करता हूं।

*Amendments (Nos.* 150 *to* 171*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 172 to 188) by Shri Vijay Jawaharlal Darda; not present. I shall now put the Amendments (Nos. 172 to 188) to vote.

*Amendments (Nos.* 172 *to* 188*) were negatived.*

Amendments (Nos. 189 to 195) by Shri Mani Shankar Aiyar.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, I am not pressing the amendments. But I do request the Chairman to give Members an opportunity to explain why they moved the amendments. I had asked for that specifically. You have not granted it.

MR. CHAIRMAN: We need procedural modifications to do that.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: In future please give us this opportunity.

*Amendments (Nos.* 189 *to* 195*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 196 to 203) by Shri D. Raja. Are you withdrawing the amendments? Or should I put them to vote?

SHRI D. RAJA : Sir, procedurally, I have already moved the amendments. I want the Government to take note of those issues which I have raised through these amendments. In fact, I asked for the fishermen...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: This is not the occasion for it.

SHRI D. RAJA: It is not for the development of fishing industry. But it is the question of protecting fishermen who are being attacked by...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. This is not the occasion for elaboration. You made your point in your intervention.

SHRI D. RAJA: I have already moved the amendments. That is the position now. But, after the Prime Minister's reply and since it is a new Government, I am thankful to the Prime Minister, he has come and explained, so, I am not insisting on the amendments. The Government should take note of them.

*Amendments (Nos.* 196 *to* 203*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 204 to 242) by Shri P. Rajeeve, Shri K.N. Balagopal and Shri C.P. Narayanan. Are you pressing?

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I am sharing the views put forward by my learned colleague, Shri D. Raja. It is a new Government. I have raised very important issues of Universal Public Distribution System and employment generation. I request the Government to note these issues and I consider the common consensus of the House. If the Government is ready to consider these points, I am ready to withdraw my amendments.

MR. CHAIRMAN: No, no, there is no conditionality about it. Are you pressing the amendments or withdrawing them?

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is my right to request the Government. That is a part of democracy. That is my right.

MR. CHAIRMAN: This is a matter of procedure.

SHRI P. RAJEEVE: The Government is ready to consider that. That is a positive sign in a democratic system.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, whatever amendments are moved, the Government always takes note of the suggestions made.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

*Amendments (Nos.* 204 *to* 242*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 243 to 251) by Shri P. Rajeeve. Are you pressing?

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I withdraw the amendments.

*Amendments (Nos.* 243 *to* 251*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 252 to 258) by Shri K.N. Balagopal. Are you pressing?

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I have one point. In respect of inter-linking of rivers, the federal character is to be protected and the right of the State is to be protected. I am not pressing it, but that is the issue.

*Amendments (Nos.* 252 *to* 258*) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote. The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms—

> 'That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 9, 2014.' "

*The motion was adopted.*

---

## VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we come to the close of the 231st Session of the Rajya Sabha, which commenced on the 9th of June, 2014. The three-day Session began with the President's Address to both Houses of Parliament, which was discussed in the form of Motion of Thanks spread over two days. More than 40 Members participated in the debate and the discussions lasted for about 12 hours. I commend the Members for the constructive manner in which they participated in the discussions.

We welcomed 54 newly elected or re-elected Members and one nominated Member to the House in this Session. The Prime Minister and his Council of Ministers were also introduced to the House.

Obituary references were made to the passing away of a Union Cabinet Minister, one sitting and six former Members of this House. A reference was also made to

**7.00 P.M.**

the tragic incident of drowning of students of an Engineering College in Hyderabad in river Beas in Mandi District of Himachal Pradesh.

I have asked the Secretary-General to make available the statistical information relating to this Session.

I thank the Leader of the House, the Leader of the Opposition, the Leaders of various Parties and Groups, and all the Members for the cooperation extended by them that enabled the smooth conduct of the proceedings of the House.

I also thank the Deputy Chairman and officers and staff of the Secretariat for their help and cooperation.

---

**THE NATIONAL SONG**

**(The National Song, *"Vande Mataram"*, was then played.)**

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned *sine die.*

The House then adjourned *sine die* at one minute past seven of the clock.

Vol. 231
No. 3

Wednesday
11 June, 2014
21 Jyaishtha, 1936 (Saka)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

## OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Proclamation under Article 356 of the Constitution (pages 1-8 and 9-10)

Papers Laid on the Table (pages 8-9)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development — *Laid on the Table* (page 10)

Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture — *Laid on the Table* (pages 10-11)

Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour — *Laid on the Table* (page 11)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment — *Laid on the Table* (pages 11-12)

Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development — *Laid on the Table* (page 12)

Clarification of Government concerning appointment of Army Chief (pages 12-15)

Motion of Thanks on the President's Address — *Adopted* (pages 15-140)

Valedictory Remarks (pages 140-141)

National Song (page 141)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : **Rs. 50.00**

Web-site Address: http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail Address: rsedit-e@sansad.nic.in

PUBLISHED UNDER RULE 260 OR RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA) AND PRINTED BY THE INDIAN PRESS, AZAD PUR, DELHI-110033